



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 1, 2018/माघ 12, 1939

No. 48]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 1, 2018/MAGHA 12, 1939

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2018

फा. सं. 2(10)—बी(डी)/2018.—निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

बजट 2018-2019

वित्त मंत्री

अरुण जेटली

का

भाषण

1 फरवरी, 2018

खंड-1

प्रशासन, अर्थव्यवस्था तथा विकास

1. अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2018-19 का बजट प्रस्तुत करता हूँ।
2. महोदया, चार वर्ष पहले हमने भारत के लोगों को इस राष्ट्र को एक ईमानदार, स्वच्छ तथा पारदर्शी सरकार देने का वचन दिया था। हमने एक ऐसा नेतृत्व देने का वादा किया था, जो कठिन निर्णयों को करने में और भारत की अर्थव्यवस्था में विश्वास को बहाल करने में सक्षम हो। हमने देश में गरीबी को कम करने, आधारभूत सुविधाओं के सृजन की गति में तेजी लाने तथा एक मजबूत, आत्म विश्वास से परिपूर्ण नवभारत देने का वचन दिया था। यह वह समय था जबकि भारत कमजोर देशों की श्रेणी में माना जाता था- एक ऐसा राष्ट्र था, जो नीतिगत ठहराव एवं भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। हमने इस स्थिति में निर्णायक बदलाव लाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार ने अनेक बुनियादी संरचनात्मक सुधारों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इसके परिणामस्वरूप, भारत विश्व के सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है।
3. गत कुछ वर्षों के दौरान आर्थिक सुधारों की यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तथा परिणामोत्पादक रही है। सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारात्मक उपायों के परिणामस्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा किए गए उपायों से भारत में व्यवसाय करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। अब प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन में पारदर्शिता एवं ईमानदारी बरती जाने लगी है। अब ईमानदारी हमारे लिए सर्वोपरि हो गई है। एक समय था जब भ्रष्टाचार शिष्टाचार का अंग बन गया था। आज हमारे नागरिक, विशेष रूप से नवयुवक वर्ग, ईमानदारी का जीवन व्यतीत करने को तत्पर हैं। माल एवं सेवा कर को लागू करने से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अधिक आसान हो गई है। डिजिटल प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लाने से गरीबों को अधिक प्रभावी रूप में लक्षित करते हुए उन्हें लाभ पहुंचाया जाने लगा है। उच्च मूल्य की मुद्रा के विमुद्रीकरण से भारत में नकद मुद्रा एवं परिचालन की मात्रा में कमी आई है। इससे कराधान का आधार व्यापक हुआ है तथा देश में अर्थव्यवस्था के डिजिटलाइजेशन में तेजी आई है। शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन कोड को लागू किए जाने से ऋणी-ऋण दाताओं के बीच संबंध बदला है। बैंकों का पुनःपूंजीकरण किया गया है और अब ये बैंक विकास की गति को सहायता प्रदान करने में पहले से कहीं अधिक सक्षम हैं। इन सभी संरचनात्मक सुधारों से मध्यम अवधि एवं दीर्घावधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक टिकाऊ सुदृढ़ विकास गति को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।
4. मई, 2014 में हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। हमारी सरकार के पहले 3 वर्षों में भारत में आर्थिक विकास की औसत दर 7.5 प्रतिशत पर पहुंच गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब 2.5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था है तथा विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आशा है कि भारत शीघ्र ही विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) आधार पर हमारा देश पहले से ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है।
5. भारतीय समाज, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था ने संरचनात्मक सुधारों को अपनाने में उल्लेखनीय लोच प्रदर्शित की है। दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर ने अर्थव्यवस्था में

आमूलचूल बदलाव आने का संकेत दिया था। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में हमारे जीडीपी में 7.2 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने की आशा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि आगामी वर्ष के दौरान भारत की विकास दर 7.4 प्रतिशत होगी। हम 8 प्रतिशत से भी अधिक की उच्च विकास दर को प्राप्त करने के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। विनिर्माण क्षेत्र भी विकास के तीव्रतर पथ पर लौट आया है। सेवा क्षेत्र, जो हमारे विकास का एक मुख्य क्षेत्र है, में भी 8 प्रतिशत से भी अधिक की उच्च दर से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2017-18 में हमारे निर्यात में 15 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।

6. हमने देश के किसानों, गरीब वर्ग के लोगों एवं समाज के अन्य कमजोर तबकों को संरचनात्मक बदलावों एवं अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर के लाभ पहुंचाने तथा देश के अल्प विकसित क्षेत्रों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इस वर्ष के बजट में इन लाभों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा विशेषकर कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, आर्थिक दृष्टि से कम सुविधा प्राप्त वर्ग के लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने, वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा करने, आधारभूत सुविधाओं का सृजन तथा देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के साथ मिलकर कार्य करने पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है।

7. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा से ही अच्छे प्रशासन के महत्व पर बल दिया है। आपने "न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन" की अवधारणा पर बल दिया है। इस अवधारणा से सरकारी एजेंसियां नियमों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं में सैकड़ों सुधार लाने के लिए प्रेरित हुई हैं। यह बदलाव भारत द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक की रिपोर्ट "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" में शामिल देशों की रैंकिंग में 42 स्थानों के सुधार आने से प्रदर्शित होता है। भारत पहली बार इस सूची में शीर्षस्थ 100 देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। मैं इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को बधाई देता हूँ।

8. हमारी सरकार अब "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" से आगे बढ़कर देश के जनसामान्य, विशेषकर गरीब और मध्यमवर्ग की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, उनकी "ईज ऑफ लिविंग" पर जोर दे रही है। गुड गवर्नेंस का आधार भी यही है कि देश के आम नागरिक के जीवन में सरकारी दखल कम से कम हो।

9. उज्ज्वला योजना के माध्यम से सरकार देश के गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दे रही है। सौभाग्य योजना के जरिए चार करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। 3 हजार से ज्यादा जन औषधि केन्द्रों में 800 से ज्यादा दवाइयां कम कीमत में बेची जा रही हैं। स्टेंट की कीमत नियंत्रित की गई है। गरीबों के लिए मुफ्त डायलिसिस के लिए विशेष योजना शुरू की गई है। गरीबों और मध्यम वर्ग को आवास योजनाओं में भी ब्याज दर में बड़ी राहत दी जा रही है। सरकारी सेवाएं, चाहे बस-ट्रेन का टिकट हो या फिर अलग-अलग प्रमाण-पत्र, सभी को ऑनलाईन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। दो से तीन दिन के भीतर घर पर आने वाला पासपोर्ट हो, या एक दिन में रजिस्टर होने वाली कंपनी, इससे देश के बड़े वर्ग को लाभ पहुंचा है। सर्टिफिकेट अटेस्टेड कराने की बाध्यता खत्म करने और ग्रुप सी व डी की नौकरी में इंटरव्यू खत्म किए जाने से लाखों नौजवानों के समय और पैसे की बचत हुई है। यह सरकार अनावश्यक नियमों-कायदों के साथ संघर्ष कर रहे हर व्यक्ति को आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।

10. महोदया, इन सुधारों तथा कार्यक्रमों को लागू करते समय हमने ईमानदारी से कार्य किया है तथा किसी प्रकार के राजनीतिक हानि-लाभ को दरकिनार रखा है। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इन

कार्यक्रमों के लाभ सभी पात्र लाभभोगियों तक पहुंचें तथा उन्हें सीधे उपलब्ध हों। अनेक सेवाएं तथा लाभ जनता को उसके द्वार पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा वित्तीय लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाए जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है तथा लाभ एवं सेवाओं की सुपुर्दगी की लागत कम हुई तथा इस प्रक्रिया में बिचौलिया की भूमिका समाप्त हो गई है। भारत में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का तंत्र विश्व में अपने प्रकार का सबसे बड़ा है और विश्व भर को हमारे देश की सफलता की कहानी का संदेश देता है।

खंड-II

निवेश, व्यय तथा नीतिगत पहल

कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था

11. मेरी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। दशकों से देश की कृषि नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन केन्द्रित रही थी। हमने इसमें एक मौलिक संकल्पनात्मक बदलाव लाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक जबकि भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, किसानों की आय को दोगुनी करने के संबंध में आह्वान किया है। हमारा बल किसानों के लिए अधिक आय सृजित करने पर है। हम कृषि को एक उद्यम मानते हैं और किसानों को उसी भू-खण्ड से अपेक्षाकृत कम लागत पर अधिक उत्पादन करने तथा अपने उत्पादों के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने में सहायता करना चाहते हैं। हम किसानों तथा भूमिहीन परिवारों के लिए उत्पादक तथा लाभकारी आन-फार्म एवं नॉन-फार्म रोजगार सृजित करने पर भी बल दे रहे हैं।

12. अध्यक्ष महोदया, देश के किसानों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज देश में कृषि उत्पादन रिकार्ड स्तर पर है। वर्ष 2016-17 में लगभग 275 मिलियन टन खाद्यान्न और लगभग 300 मिलियन टन फलों एवं सब्जियों का ऐतिहासिक उत्पादन हुआ है।

13. अध्यक्ष महोदया, हमारे दल के घोषणा-पत्र में यह संकल्प है कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसान भाइयों को उनकी उत्पादन की लागत से कम-से-कम 50 प्रतिशत अधिक अर्थात् लागत से डेढ़ गुना दाम मिले। सरकार इस संकल्प के प्रति संवेदनशील रही है। रबी की अधिकांश घोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम डेढ़ गुना तय किया जा चुका है। अब हमने बची हुई अधिघोषित फसलों के लिए भी इस संकल्प को एक सिद्धांत की तरह लागू करने का फैसला लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि तय किये गए सिद्धांत के अनुसार, सरकार ने आगामी खरीफ से सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम-से-कम डेढ़ गुना करने का फैसला लिया है। मेरा विश्वास है कि यह ऐतिहासिक निर्णय किसान भाइयों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

14. हमारी सरकार किसी भी विषय को टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं, समग्रता में सुलझाने की अप्रोच के साथ काम करती है। खाली न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि घोषित MSP का पूरा लाभ किसानों को मिले। इसके लिए यह आवश्यक है कि यदि बाजार में दाम MSP से कम हो तो सरकार या तो MSP पर खरीदी करे या किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत किसान को पूरी MSP मिले। NITI आयोग, केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर एक पुख्ता व्यवस्था तैयार करेगा जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाया जा सके।

- 15.** बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि किसान किसी फसल की बुआई के संबंध में अपने निर्णय उसकी कटाई के बाद उसके संभावित मूल्य को ध्यान में रखते हुए करें। सरकार मूल्य तथा मांग के संबंध में पूर्वानुमान लगाने, भावी तथा वैकल्पिक बाजार के प्रयोग, माल-गोदाम (वेयर हाउस) निक्षेपण प्रणाली के विस्तार तथा विशिष्ट निर्यात एवं आयात संबंधी उपायों के संबंध में निर्णय लेने हेतु उपयुक्त नीतियों एवं पद्धतियों को विकसित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से एक संस्थागत तंत्र सृजित करेगी।
- 16.** अध्यक्ष महोदया, पिछले वर्ष मैंने ई-नैम को सुदृढ़ बनाने तथा ई-नैम के कवरेज को 585 एपीएमसी तक पहुंचाने के संबंध में घोषणा की थी 470 एपीएमसी ई-नैम नेटवर्क से संयोजित कर दिए गए हैं तथा शेष को मार्च, 2018 तक इस नेटवर्क से संयोजित कर दिया जाएगा।
- 17.** हमारे 86 प्रतिशत से भी अधिक किसान अभी भी लघु एवं सीमांत किसान हैं। ये हर बार एपीएमसी में या अन्य थोक बाजारों में सीधे अपने उत्पादों को बेचने की स्थिति में नहीं होते। हम मौजूदा 22000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजारों के रूप में विकसित तथा उन्नत करेंगे। इन ग्रामीण कृषि बाजारों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और अन्य सरकारी स्कीमों का प्रयोग करके भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-नैम से जुड़े तथा एपीएमसी के विनियमों से छूट प्राप्त ये ग्रामीण कृषि बाजार किसानों को सीधे उपभोक्ताओं एवं थोक खरीदारों को अपने उत्पाद बेचने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
- 18.** 22000 ग्रामीण कृषि बाजारों तथा 585 एपीएमसी में कृषि विपणन अवसंरचना के विकास तथा उन्नयन के लिए 2000 करोड़ रुपये की स्थायी निधि के साथ एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष की स्थापना की जाएगी।
- 19.** सभी मौसम में प्रयोग में लाए जाने वाली सड़क अवसंरचना से युक्त सभी पात्र निवास स्थानों को जोड़ने का काम काफी हद तक पूरा हो गया है तथा इस संबंध में लक्ष्य को मार्च 2022 के स्थान पर मार्च, 2019 तक प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। अब ग्रामीण निवास स्थानों को कृषि एवं ग्रामीण बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों से जोड़ने वाले बड़े लिंक मार्गों को शामिल करके इसकी परिधि को और अधिक सुदृढ़ एवं विस्तृत करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-III में इन सभी लिंक मार्गों को शामिल किया जाएगा।
- 20.** हम वर्षों से यह कहते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है वैसे ही देश के जिले भी किसी न किसी कृषि उत्पाद के लिए जाने जा सकते हैं। लेकिन हमने इस पर विशेष ध्यान अब तक नहीं दिया है। जैसे उद्योग जगत के लिए क्लस्टर बेस्ड विकास का मॉडल अपनाया गया वैसे ही हमारे जिलों में कृषि उत्पाद को चिह्नित कर, वैज्ञानिक तरीके से क्लस्टर मॉडल पर विकास की आवश्यकता है।
- 21.** एक समूह में बागवानी फसलों की खेती करने से विभिन्न प्रकार के संबंधित कार्यों से छूट मिलती है तथा इससे उत्पादन से लेकर विपणन तक की संपूर्ण श्रृंखला को लाभ पहुंचता है। इससे संबंधित जिलों को विशिष्ट फसलों के लिए मान्यता भी प्राप्त होगी। कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध मंत्रालयों के साथ मिलकर अपनी चालू स्कीमों की समीक्षा करेगा तथा कृषि-जिन्सों एवं संबंधित क्षेत्रों के समूह आधारित विकास को बढ़ावा देगा।

22. हमारी सरकार ने जैविक कृषि को बढ़ावा दिया है। इसके लिए बड़े समूहों में जिनमें से प्रत्येक 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का हो, कृषि उत्पादक संगठनों एवं ग्रामीण उत्पादक संगठनों द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। महिला स्व-सहायता समूहों को भी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत समूहों में जैविक कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

23. हमारी पारिस्थितिकी अत्यधिक विशिष्ट औषधीय एवं सुगंध पौधों की खेती के भी अनुकूल है। भारत में बड़ी संख्या में लघु एवं कुटीर उद्योग भी चलाए जाते हैं, जिनमें इत्र, इन्हें विकसित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले तेलों एवं अन्य संबंधित उत्पादों को तैयार किया जाता है। हमारी सरकार संगठित कृषि एवं संबद्ध उद्योग को सहायता उपलब्ध कराएगी। मैं इस प्रयोजनार्थ 200 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

24. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रति वर्ष औसतन 8 प्रतिशत की दर से विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हमारा अग्रणी कार्यक्रम है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए आबंटन की राशि 2017-18 के संशोधित अनुमान के 715 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना करके 2018-19 में 1400 करोड़ रुपये किया जा रहा है। सरकार इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कृषि प्रसंस्करण वित्तीय संस्थाओं को स्थापित करने को बढ़ावा देगी।

25. टमाटर, प्याज और आलू ऐसी प्रमुख सब्जियां हैं, जिन्हें पूरे वर्ष प्रयोग में लाया जाता है। तथापि, इन शीघ्र नष्ट हो जाने वाले जिन्सों के मौसमी एवं क्षेत्रीय उत्पादन के कारण किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों को संतुष्ट करते हुए उनके बीच पारस्परिक संपर्क स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है। हमारी सरकार का प्रस्ताव "ऑपरेशन फ्लड" की तर्ज पर "ऑपरेशन ग्रीन्स" शुरू करने का है। "ऑपरेशन ग्रीन्स" किसान उत्पादक संगठनों, कृषि संभारतंत्र, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा व्यावसायिक प्रबंधन को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। मैं इस प्रयोजनार्थ 500 करोड़ रुपये की राशि आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

26. भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावना काफी अधिक है, जो 100 बिलियन अमरीकी डालर तक हो सकती है जबकि मौजूदा निर्यात 30 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का किया जाता है। इस संभावना को प्रयोग में लाने के लिए कृषि जिन्सों के निर्यात को उदार बनाया जाएगा। मैं सभी 42 मेगा फूड पार्कों में अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

27. मैं, किसान क्रेडिट कार्डों की सुविधा मत्सिकी एवं पशुपालन से जुड़े किसानों को भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि वे अपनी कार्य चालन पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस व्यवस्था से छोटे और सीमांत किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।

28. बांस "हरित सोना" है। हमने वन क्षेत्र से बाहर उगे बांस को पेड़ों की परिभाषा से अलग कर दिया है। अब मैं बांस क्षेत्र को एक सम्पूर्ण रूप में बढ़ावा देने के लिए 1290 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

29. अनेक किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए सौर जल पंपों को संस्थापित कर रहे हैं। सौर विद्युत उत्पादन द्वारा किसान अपने खेतों का प्रयोग करके सौर ऊर्जा का संचयन करते हैं। भारत सरकार इस संबंध में

आवश्यक उपाय करेगी तथा राज्य सरकारों को एक ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जिससे उनके अधिशेष सौर विद्युत को विद्युत वितरण कंपनियों या लाइसेंस धारकों द्वारा उचित लाभकारी मूल्यों पर खरीद लिया जाए।

30. हमारी सरकार ने सिंचाई निर्माण कार्यों की वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाबार्ड में एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष (एलटीआईएफ) स्थापित किया है। इस कोष के स्कोप को विस्तारित करके विशिष्ट कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं को कवर किया जाएगा।

31. गत वर्ष मैंने डेयरी उद्योग की आधारभूत सुविधाओं में वित्त निवेश में सहायता के लिए सूक्ष्म सिंचाई तथा डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास कोष (डीपीआईडीएफ) के अंतर्गत कवरेज को विस्तार प्रदान करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) स्थापित करने की घोषणा की थी। अब इस प्रकार के निवेश कोषों को विस्तार प्रदान करने का समय है। अब मैं मत्स्यी क्षेत्र के लिए मत्स्य क्रांति अवसंरचना विकास कोष (बीआरआईडीएफ) तथा पशुपालन क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता के वित्त पोषण के लिए पशुपालन हेतु आधारभूत सुविधा विकास कोष (एएचआईडीएफ) स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इन दोनों कोषों की कुल स्थायी निधि 10,000 करोड़ रुपये होगी।

32. हमारी सरकार कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण की राशि में वर्षानुवर्ष निरंतर वृद्धि करती रही है और यह राशि 2014-15 के 8.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2017-18 में 10 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। मैं अब इस राशि को वर्ष 2018-19 में 11 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

33. वर्तमान में पट्टाधारी किसान फसल ऋण का लाभ नहीं उठा पाते। इसके परिणामस्वरूप कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा परती पड़ा रहता है तथा पट्टाधारी किसान सूदखोर महाजनों से ऋण लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नीति आयोग राज्य सरकारों से परामर्श करके भू-स्वामियों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पट्टाधारी किसानों को ऋण सुलभ कराने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित करेगा।

34. सरकार किसानों को अपने आदानों की आवश्यकता, फार्म सेवाओं, प्रसंस्करण तथा विक्रय प्रचालनों से संबंधित आवश्यकता ज्ञात करने में सहायता के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के लिए अनुकूल कराधान व्यवस्था लागू करेगी। इस संबंध में मैं अपने भाषण के भाग-ख में ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा।

35. एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण चिंता का विषय रहा है। वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने तथा फसल अवशिष्ट के खेत में ही प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी हेतु सब्सिडी प्रदान करने के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारों के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष स्कीम लागू की जाएगी।

36. अध्यक्ष महोदया, देश का वर्तमान शीर्ष नेतृत्व गरीबी को बहुत करीब से देखकर, गरीबी में जीकर यहां तक पहुंचा है। एससी/एसटी वर्गों की पिछड़ों की, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो चिंताएं होती हैं, उनसे भली-भांति परिचित है। गरीब और मध्यम वर्ग उनके लिए केस स्टडी नहीं, बल्कि वो खुद एक केस स्टडी हैं।

37. पिछले तीन वर्षों में सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब रहा है, मध्यम वर्ग रहा है। ये सरकार गरीब की छोटी-छोटी चिंताओं और बड़ी-बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है।

38. गरीब महिलाओं को लकड़ी के धुएं से मुक्ति मिले, इसलिए हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी। शुरूआत में हमने 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा था। लेकिन इस योजना की गति देखकर और महिलाओं में इसकी लोकप्रियता देखकर हम इसका लक्ष्य बढ़ाने जा रहे हैं। अब सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी।

39. देश के हर गरीब के घर में रोशनी पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत देश के 4 करोड़ गरीबों के घरों को बिना कोई शुल्क लिए बिजली कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। इस योजना पर 16 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। घर में एक घंटा बिजली ना आए तो हम लोग इधर-उधर दौड़ने लगते हैं, टीवी कैसे चलेगा, मोबाइल कैसे चार्ज होगी, लैपटॉप का क्या होगा, यह सोचने लगते थे। आप लोगों का सोचिए, उन महिलाओं और उन बच्चों के बारे में सोचिए, जिनके घर में अब बिजली पहुंचेगी। किस तरह उनकी जिंदगी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना बदलने जा रही है।

40. गरीब को सरकार के स्वच्छ भारत मिशन से भी बड़ा लाभ पहुंचा है। इस मिशन के तहत सरकार अब तक 6 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करा चुकी है। इन शौचालयों का सकारात्मक प्रभाव नारी की गरिमा, बेटियों की शिक्षा और पूरे परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा पर स्पष्ट रूप से पड़ रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में हमारा लगभग दो करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य है।

41. अध्यक्ष महोदया, गरीब की एक और चिंता रही है— सिर पर एक अदद छत की। भ्रष्टाचार करके जुटाई गई बेनामी संपत्तियों से दूर, गरीब तो बस ईमानदारी की कमाई से एक छत, एक छोटा सा मकान चाहता है। गरीब, अपने घर का सपना पूरा कर सके, इसके लिए हमारी सरकार, उसकी पूरी मदद कर रही है। हमने लक्ष्य रखा है 2022 तक देश के हर गरीब के पास उसका अपना घर हो। इसके लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2017-18 में 51 लाख और वर्ष 2018-19 में 51 लाख यानि एक करोड़ से ज्यादा घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख मकान बनाने के लिए मदद स्वीकृत की गई है।

42. हमारी सरकार राष्ट्रीय आवास बैंक में समर्पित सस्ती आवासन निधि की भी स्थापना करेगी, जिसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देय उधार में हुई कमी से और भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत पूर्णतः शोधित बांडों द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

43. महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के ऋण को पिछले वर्ष के मुकाबले 37% बढ़ाकर वर्ष 2016-17 में लगभग 42,500 करोड़ रुपए करा दिया गया था। हमारी सरकार पूरी तरह आश्वस्त है कि मार्च, 2019 तक स्व-सहायता समूहों को ऋण राशि बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपये कर दी जाएगी। मैं 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के आवंटन को पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 5750 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं।

44. प्रधान मंत्री हर खेत को पानी योजना के तहत भू-जल सिंचाई स्कीम, सिंचाई से वंचित 96 जिलों में शुरू की जाएगी जहां वर्तमान में 30% से भी कम खेतों की सिंचाई सुनिश्चित हो पाती है। इस प्रयोजन के लिए मैंने 2600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

45. जैसा कि मेरे प्रस्ताव की रुपरेखा संकेत करती है, अगले वर्ष सरकार का ध्यान रोजी-रोटी, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं निर्माण पर और अधिक धनराशि खर्च करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर होगा। वर्ष 2018-19 में, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए मंत्रालयों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि 14.34 लाख करोड़ रुपये होगी, इसमें 11.98 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय संसाधन शामिल हैं। खेती संबंधी कार्यकलापों और स्व-रोजगार के कारण रोजगार के अलावा, इस खर्च से 321 करोड़ मानव दिवस के रोजगार, 3.17 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों, 51 लाख नए ग्रामीण मकानों, 1.88 करोड़ शौचालयों का सृजन होगा और इससे कृषि को प्रोत्साहन मिलने के अतिरिक्त 1.75 करोड़ नए परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्राप्त होंगे। ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

स्वास्थ्य शिक्षा तथा सामाजिक संरक्षण

46. हमारी सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सहायता और अवसर प्रदान करना है ताकि वह अपने आर्थिक और सामाजिक सपनों को पूरा करने की अपनी पूरी संभावित क्षमता का उपयोग कर सके। हमारी सरकार, सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना के अनुसार वृद्धों, विधवाओं, बेसहारा बच्चों, दिव्यांगजनों और वंचित लोगों के प्रत्येक परिवार तक पहुंचने के लिए एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पर आवंटित 2018-19 में 9975 करोड़ रुपए रखा गया है।

47. हमने बच्चों को स्कूल में पढ़ते हुए देखने की व्यवस्था की है किन्तु शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी एक गंभीर चिन्ता बनी हुई है। अब हमने शिक्षण के परिणाम परिभाषित किए हैं और जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करने के लिए 20 लाख से अधिक बच्चों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जिला-वार रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। अब हमारा प्रस्ताव नर्सरी पूर्व से कक्षा 12 तक बिना किसी विखंडन के शिक्षा को व्यवहार्य माने जाने का है।

48. अध्यापकों की गुणवत्ता सुधारने से देश में शिक्षा की गुणवत्ता भी जरूर बढ़ेगी। शिक्षकों के लिए एक एकीकृत बी.एड कार्यक्रम प्रारम्भ करेंगे। सेवा के दौरान शिक्षकों का प्रशिक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमने 13 लाख से अधिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है।

49. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयोगी संचालक होगी। हमारा प्रस्ताव शिक्षा में डिजिटल तीव्रता बढ़ाने और धीरे-धीरे "ब्लैक बोर्ड" से "डिजिटल बोर्ड" की दिशा में बढ़ने का है। हाल ही में संचालित "दीक्षा" डिजिटल पोर्टल के जरिए शिक्षकों के कौशल उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जाएगा।

50. सरकार, जनजातीय बच्चों को अपने स्वयं के माहौल में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभियान को आगे ले जाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2022 तक, अनुसूचित जन जाति की 50% से अधिक जनसंख्या वाले और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय के समतुल्य होगा और इसमें

खेलकूद और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

51. स्वास्थ्य संस्थानों सहित, प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित अवसंरचना में निवेश की गति में तेजी लाने के लिए, मैं अगले चार वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ "2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुविधाओं और प्रणालियों को पुनःजानदार बनाने (राइज)" नामक एक बड़ी पहल प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस पहल के वित्तपोषण के लिए उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (हेफा) को उपयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा।

52. हमारी सरकार ने श्रेष्ठ संस्थानों की स्थापना के लिए बड़ी पहल की है। सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में संस्थानों द्वारा इस पहल की जबर्दस्त प्रतिक्रिया रही है। हमें 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। हमने बड़ोदरा में विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भी कदम उठाए हैं।

53. हम चुनौती विधि पर चयन किए जाने वाले आयोजना और स्थापत्य कला के दो नए पूर्णतः सुसज्जित स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं। इसके अतिरिक्त आईआईटी/एनआईटी में 18 नए एसपीए की भी चुनौती विधि से स्वायत्त निकायों के रूप में स्थापना की जाएगी।

54. इस वर्ष सरकार "प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता (पीएमआरएफ)" नामक पहल प्रारंभ करेगी। इस पहल के अंतर्गत, हम श्रेष्ठ संस्थानों से हर वर्ष 1,000 उत्कृष्ट बी.टेक छात्रों की पहचान करेंगे और उन्हें एक अच्छी अध्येतावृत्ति के साथ आईआईटी/आईआईएससी में पी.एच.डी. करने के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे। आशा है कि ये उदीयमान युवा साथी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्वेच्छा से पढ़ाने के लिए सप्ताह में कुछ घंटे देंगे।

55. अब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र पर आता हूँ। सर्वेभवनतुः सुखिन, सर्वे संतुः निरामया" हमारी सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। केवल स्वच्छ भारत ही समृद्ध भारत बन सकता है। यदि भारत के नागरिक स्वस्थ नहीं होंगे तो इसके बिना अपना देश युवा साथियों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

56. मैं, निवारण और स्वास्थ्य संवर्धन दोनों को शामिल करके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देख-रेख प्रणाली में स्वास्थ्य समस्या से व्यावहारिक ढंग से निपटने के लिए पथ अवरोधक हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से बनाए गए "आयुष्मान भारत" के भाग के रूप में दो प्रमुख पहलों की घोषणा करता हूँ।

57. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की नींव के रूप में स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों की परिकल्पना की गई है। ये 1.5 लाख केंद्र, स्वास्थ्य देख-रेख प्रणाली को लोगों के घरों के पास लाएंगे। ये स्वास्थ्य केन्द्र असंचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देख-रेख उपलब्ध कराएंगे। ये केन्द्र आवश्यक दवाइयां और नैदानिक सेवाएं भी मुफ्त उपलब्ध करवाएंगे। मैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए इस बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं इन केंद्रों को अपनाने में सीएसआर और लोकोपकारी संस्थाओं के जरिए निजी क्षेत्र को योगदान के लिए आमंत्रित करता हूँ।

58. अध्यक्ष महोदया, हम सब यह जानते हैं कि हमारे देश में लाखों परिवारों को अस्पतालों में अंतरंग (इंडोर) इलाज कराने के लिए उधार लेना पड़ता है या संपत्तियां बेचनी पड़ती है। सरकार, निर्धन और कमजोर परिवारों की ऐसी दरिद्रता के बारे में अत्यधिक चिंतित है। मौजूदा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्कीम गरीब परिवारों को

30,000/- रुपये की वार्षिक कवरेज प्रदान करती है। अनेक राज्य सरकारों ने भी कवरेज में विविधता उपलब्ध कराके स्वास्थ्य संरक्षण योजनाएं कार्यान्वित अनुपूरित की हैं। अब हमारी सरकार ने स्वास्थ्य संरक्षण को और अधिक आकांक्षा वाला स्तर प्रदान करने का निर्णय लिया है।

59. हम 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को दायरे में लाने के लिए एक फ्लेगशिप राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना प्रारम्भ करेंगे जिसके तहत द्वितीयक और तृतीयक देख-रेख अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह विश्व का सबसे बड़ा सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य देख-रेख कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

60. अध्यक्ष महोदया, आयुष्मान भारत के तहत ये दो दूरगामी पहलें वर्ष 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करेंगी और इनसे संवर्धित उत्पादकता, कल्याण में वृद्धि होगी और इनसे मजदूरी की हानि और दरिद्रता से बचा जा सकेगा। इन योजनाओं से, खासकर महिलाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर भी सृजित होंगे। सरकार सर्वजन स्वास्थ्य कवरेज के लिए स्थायी रूप से किंतु निश्चित रूप से उत्तरोत्तर अग्रसर है।

61. किसी दूसरी संक्रामक बीमारी की तुलना में टीबी से हर वर्ष अधिक जानें जाती हैं। यह मुख्य रूप से गरीब और कुपोषित लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए हमारी सरकार टी.बी. से पीड़ित सभी रोगियों को उनके उपचार की अवधि के दौरान 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पोषणाहार सहायता प्रदान करने के लिए 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की है।

62. गुणवत्तायुक्त चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देख-रेख की पहुंच में और वृद्धि करने के उद्देश्य से, हम देश में मौजूदा जिला अस्पतालों को अपग्रेड करके 24 नए सरकारी चिकित्सा कालेजों और अस्पतालों की स्थापना करेंगे। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक 3 संसदीय क्षेत्रों के लिए कम से कम एक चिकित्सा कालेज और देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक सरकारी चिकित्सा कालेज है।

63. हमारे गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के हमारे संकल्प का उद्देश्य अपने गांवों के जीवन को बेहतर बनाना है। हम जानवरों के गोबर और ठोस अपशिष्ट को कम्पोस्ट, उर्वरक, बायो गैस और बायो-सीएनजी के रूप में बदलने के लिए खेतों में इसके प्रबंधन और रूपांतरण हेतु गाल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबर-धन) नामक योजना प्रारम्भ करेंगे।

64. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) से केवल 330/- रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर 5.22 करोड़ परिवार 2 लाख रुपये के जीवन बीमा कवर से लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 12 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम के भुगतान पर 13 करोड़ 25 लाख व्यक्तियों को 2 लाख रुपये के व्यक्तिगत दुर्घटना कवर के साथ बीमित किया गया है। सरकार सभी गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों सहित, को इसके तहत एक मिशन मोड में शामिल करने का प्रयास करेगी।

65. सरकार समस्त साठ करोड़ बुनियादी खातों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाकर इसके दायरे का विस्तार करेगी और इन खातों के जरिए सूक्ष्म बीमा और असंगठित क्षेत्र पेंशन योजनाओं की सेवा प्रदान करने हेतु उपाय करेगी।

66. “बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं” के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है। जनवरी, 2015 में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि खाता योजना बहुत सफल रही है। यह योजना शुरू करने से लेकर नवंबर, 2017 तक बालिका के नाम से देश भर में 1.26 करोड़ खाते खोले गए हैं जिनमें 19,183 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

67. गंगा की सफाई, राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और हम इस पर दृढ़ प्रतिज्ञा हैं। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस कार्य ने गति पकड़ ली है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 16,713 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत सुविधाओं विकास, नदी तल की सफाई, ग्रामीण स्वच्छता और अन्य कार्यक्रमों हेतु कुल 187 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 47 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। सभी 4465 गंगा ग्रामों- नदी के किनारे पर बसे गांव को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है।

68. सरकार ने केन्द्रित ध्यान देने और समावेशी समाज का सपना पूरा करने के लिए विकास के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए ऐसे 115 महत्वाकांक्षी जिलों की पहचान की है। सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार, कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेशन जैसी सामाजिक सेवाओं तथा सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाओं तथा तीव्र गति व समयबद्ध तरीके से शौचालयों तक पहुंच में निवेश करते हुए इन जिलों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। हमें आशा है कि ये जिले विकास के माडल बनेंगे।

69. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कठोर परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति हेतु सरकार ने खास ध्यान दिया है। हमारी सरकार ने 279 कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों के लिए कुल अलग से रखा गया आबंटन 2016-17 में 34,334 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सं.अ. 2017-18 में 52,719 करोड़ रुपये कर दिया है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए 305 कार्यक्रमों के लिए अलग से रखा गया आबंटन 2016-17 में 21,811 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सं.अ. 2017-18 में 32,508 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मैं, ब.अ. 2018-19 में अलग से रख गया आबंटन अनुसूचित जातियों के लिए 56619 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजातियों के लिए 39,135 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

70. सरकार का स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर अनुमानित स्कीमवार बजटीय व्यय 2017-18 में 1.22 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की तुलना में 2018-19 में 1.38 लाख करोड़ रुपये है। इनके ब्यौरे अनुबंध-II में दिए गए हैं। यह व्यय अतिरिक्त आबंटन और उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी के जरिए सहित बजट बाह्य व्यय के कारण 2018-19 में कम से कम 15,000 करोड़ रुपये बढ़ने की संभावना है।

मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्यम एवं रोजगार

71. लघु और मध्यम उद्यम देश की प्रगति तथा रोजगार के प्रमुख वाहक हैं। मैंने एमएसएमएमी क्षेत्र को ऋण सहायता, पूंजी और ब्याज सब्सिडी तथा नवोन्मेष के लिए 3794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। विमुद्रीकरण और जीएसटी लागू होने के पश्चात् देश में लघु और मध्यम उद्यमों के व्यवसायों का प्रभावशाली आकार बढ़ रहा है। यह लघु और मध्यम उद्यमों के व्यवसायों और वित्त साधनों के प्रचुर वित्तीय सूचना डाटाबेस बना रहा है। यह बड़ा डाटा लघु और मध्यम उद्यमों की कार्यशील पूंजी सहित पूंजी की जरूरतों के वित्तपोषण में सुधार करने हेतु प्रयोग किया जाएगा।

72. यह प्रस्ताव है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और कारपोरेटों को ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक रिसिवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम पर आनबोर्ड किया जाए और इसे जीएसटीएन के साथ जोड़ा जाए। यह एमएसएमई को बृहत वित्तपोषण में सक्षम बनाएगा और उनके द्वारा सामना की जा रही नकदी प्रवाहों की चुनौतियों को काफी सुखद भी बनाएगा। बैंकों द्वारा शीघ्र निर्णय लेने के लिए एमएसएमई हेतु आनलाइन ऋण स्वीकृति सुविधा सुधारी जाएगी। सरकार एमएसएमई की अनर्जक आस्तियों और भारग्रस्त खातों के प्रभावी समाधान के उपायों की शीघ्र घोषणा करेगी। मैं एमएसएमई पर करों का भार घटाने और अनेक नौकरियां सृजित करने के लिए अपने भाषण के भाग-ख में कुछ उपायों की घोषणा करूंगा।

73. अप्रैल, 2015 में शुरू की गई मुद्रा योजना में 10.38 करोड़ मुद्रा ऋणों से उधार के लिए 4.6 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ऋण के 76 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं और 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं। पिछले सभी 3 वर्षों में लक्ष्य से अधिक सफलता प्राप्त करने के पश्चात 2018-19 में मुद्रा के अंतर्गत उधार देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

74. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने विमुद्रीकरण के पश्चात एमएसएमई का वित्तपोषण बढ़ाया है। एनबीएफसी मुद्रा के अंतर्गत ऋण देने के लिए बहुत शक्तिशाली साधन हो सकती हैं। एनबीएफसी बेहतर वित्तपोषण हेतु मुद्रा द्वारा निर्धारित पुनर्वित्तपोषण नीति और पात्रता मापदंडों की पुनरीक्षा की जाएगी।

75. वित्तपोषण की गुंजाइश में फिनटेक का प्रयोग एमएसएमई के विकास में सहायता करेगा। वित्त मंत्रालय में एक समूह इस नीति और भारत में बढ़ने के लिए फिनटेक कंपनियों हेतु अच्छा माहौल बनाने हेतु जरूरी संस्थागत विकासात्मक उपायों की जांच कर रहा है।

76. उपक्रम पूंजी निधियों और ईमानदार निवेशकों को उनकी संवृद्धि हेतु नवोन्मेषी और विशेष विकासात्मक व नियामक व्यवस्था की जरूरत होगी। हमने "स्टार्ट-अप इंडिया" कार्यक्रम शुरू करके, देश में बहुत ठोस वैकल्पिक निवेश व्यवस्था बनाकर तथा उपक्रम पूंजी निधियों व ईमानदार निवेशकों के विशेष स्वरूप के लिए तैयार की गई कराधान व्यवस्था आरंभ करने सहित अनेक नीतिगत उपाय किए हैं। हम उनके विकास और भारत में वैकल्पिक निवेश निधियों के सफल कार्यचालन हेतु माहौल सुदृढ़ करने के अतिरिक्त उपाय करेंगे।

77. नौकरी के अवसर सृजित करना और रोजगार सृजन सुगम बनाना, हमारे नीति-निर्माण का केन्द्र बिन्दु रहा है। पिछले तीन वर्ष के दौरान, हमने देश में रोजगार सृजन बढ़ाने के अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं:

- सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों का 8.33 प्रतिशत अंशदान।
- कपड़ा और चमड़ा तथा फुटवियर जैसे बड़ी संख्या में व्यक्तियों को रोजगार देने वाले क्षेत्रों में तीन वर्ष के लिए नए कर्मचारियों की कर्मचारी भविष्य निधि में 12 प्रतिशत का अंशदान।
- आयकर अधिनियम के अंतर्गत नए कर्मचारियों को अदा किए गए पारिश्रमिक के 30 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती।

- सरकार द्वारा 2020 तक 50 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए वजीफा देते हुए राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम शुरू करना और बुनियादी प्रशिक्षण का खर्च बांटना।
- परिधान और फुटवियर क्षेत्र हेतु नियतकालिक रोजगार की शुरुआत करना।
- क्रेचों की व्यवस्था के साथ ही सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना।

78. इन कदमों ने परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में किए गए स्वतंत्र अध्ययन ने दर्शाया है कि इस वर्ष 70 लाख औपचारिक नौकरियां सृजित होंगी।

79. इस गति को बढ़ाने के लिए मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि सरकार अगले तीन वर्ष तक सभी क्षेत्रों की कर्मचारी भविष्य निधि में नए कर्मचारियों के वेतन के 12 प्रतिशत का अंशदान करेगी। इसके अतिरिक्त, नियत काल के रोजगार की सुविधा सभी क्षेत्रों तक दी जाएगी।

80. अनौपचारिक क्षेत्र में आधिकाधिक महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें अपेक्षाकृत अधिक निवल वेतन प्राप्त करने के लिए भविष्य निधि में महिला कर्मचारियों के अंशदान को प्रथम तीन वर्षों के लिए विद्यमान 12% अथवा 10% से अब मालिक के अंशदान में किसी परिवर्तन के बिना 8% करने के लिए मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

81. सरकार प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत देश के हर जिले में माडल महत्वाकांक्षी कौशल केन्द्र स्थापित कर रही है। ऐसे केन्द्रों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण देने के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र खोले गए हैं।

82. परिधान और तैयार संघटकों को बढ़ावा देने के लिए 2016 में 6,000 करोड़ रुपये का व्यापक कपड़ा क्षेत्र पैकेज अनुमोदित किया गया था। मैं अब वस्त्र क्षेत्र के लिए 2018-19 के लिए 7148 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ।

आधारभूत सुविधाओं तथा वित्तीय क्षेत्र में हुए विकास

83. आधारभूत सुविधाओं अर्थव्यवस्था के विकास का चालक है। हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोत्तरी करने, सड़कों, हवाई अड्डों, रेलवे, बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के नेटवर्क से देश को जोड़ने व एकीकृत करने तथा अपने नागरिकों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना में 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित भारी भरकम निवेशों की जरूरत होगी।

84. हमने रेल व सड़क क्षेत्रों में अब तक का सबसे ज्यादा आबंटन किया है। हम सरकारी निवेश और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विद्युत हेतु कोयला, रेलवे हेतु विद्युत और कोयले के लिए रेलवे रेक जैसे मुख्य संपर्कों की व्यवस्था युक्तिसंगत और बहुत सक्षम बनाई गई है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से नियमित आधार पर विनिर्माण क्षेत्रों में लक्ष्यों और उपलब्धियों की पुनरीक्षा करते हैं। अकेली प्रगति की आनलाइन मानीटरिंग प्रणाली का प्रयोग करते हुए 9.46 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं सुगम व तीव्र गति में लाई गई हैं।

85. भारत की सुरक्षा के लिए हम सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्कता आधारभूत सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। लद्दाख क्षेत्र को सभी मौसमों में जोड़े रखने के लिए रोहतांग सुरंग पूरी हो चुकी है। 14 किमी से अधिक की

जोजिला पास सुरंग के निर्माण का ठेका सही प्रगति कर रहा है। मैं अब सेला पास के तहत सुरंग के निर्माण शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार पर्यटन और आपातकालीन चिकित्सा सेवा के संवर्धन हेतु समुद्री प्लेन के कार्यकलापों में निवेश बढ़ाने के लिए आवश्यक ढांचा बढ़ाएगी।

86. शहरीकरण अवसर और हमारी प्राथमिकता है। मेरी सरकार ने परस्पर जुड़े दो कार्यक्रम- स्मार्ट शहर मिशन और अमृत- शुरू किए हैं।

87. स्मार्ट शहर मिशन का लक्ष्य 100 शहरों को आधुनिक सुविधाओं वाला बनाना है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि 2.04 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से 99 शहरों का चयन किया गया है। इन शहरों ने स्मार्ट कमांड और नियंत्रण केन्द्रों, स्मार्ट सड़कों, सौर छतों, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियों, स्मार्ट पार्कों जैसी विभिन्न परियोजनाओं को क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। 2350 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 20,852 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। भारत में विरासत शहरों की मौलिकता सहेज कर रखने व सजीव करने के लिए राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और सदृढीकरण योजना (हृदय) बड़े तौर पर शुरू की गई है।

88. भारत में पर्यटन स्थलों की प्रचुरता है। यह प्रस्ताव है कि दस प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को आधारभूत सुविधाओं व कौशल विकास वाला व्यावहारिक दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी का विकास, निजी निवेश आकर्षित करके, ब्रांडिंग व विपणन का अनुसरण करते हुए आदर्श पर्यटन गंतव्यों में विकसित किया जाए। इसके अतिरिक्त, आगंतुकों का अनुभव बढ़ाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 100 आदर्श स्मारकों में पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा।

89. अमृत कार्यक्रम 500 शहरों के सभी परिवारों को जलापूर्ति की व्यवस्था करने पर केन्द्रित है। अमृत योजना के अंतर्गत 500 शहरों के लिए 77,640 करोड़ रुपये की राज्य स्तरीय योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। 19,428 करोड़ रुपये की लागत से 494 परियोजनाओं हेतु जलापूर्ति संविदाएं और 12,429 करोड़ रुपये की लागत वाली 272 परियोजनाओं हेतु सीवरेज कार्य की संविदा प्रदान की जा चुकी है।

90. इन मिशनों द्वारा सुधारों को उत्प्रेरित किया जा रहा है। 482 शहरों की क्रेडिट रेटिंग शुरू हो गई है। 144 शहरों को निवेश ग्रेड की रेटिंग मिल चुकी है।

91. मेरा मंत्रालय सामरिक और बड़े सामाजिक लाभ वाले शैक्षणिक और स्वास्थ्य आधारभूत सुविधाओं में निवेशों सहित आधारभूत सुविधा परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहायता करने के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैस कारपोरेशन लि. को शक्ति प्रदान करेगा।

92. सरकार ने सड़क अवसंरचना क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमें 2017-18 के दौरान 9000 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को पूरा करने का विश्वास है। देश के भीतरी और पिछड़े क्षेत्रों व सीमाओं को निर्बाध संपर्कता उपलब्ध कराने के लिए 5,35,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चरण-1 में लगभग 35,000 किलोमीटर के सड़क निर्माण हेतु महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना अनुमोदित की गई है। एनएचएआई अपनी तैयार सड़क आस्तियों हेतु बाजार से इक्विटी जुटाने के लिए अपनी सड़क आस्तियों को विशेष प्रयोजनी साधन बनाने और टोल, चलाओ और अंतरण तथा आधारभूत सुविधा निधियों जैसे नए मुद्रीकरण ढांचों का प्रयोग करने पर विचार करेगा।

93. रेलवे नेटवर्क मजबूत करना और रेलवे की दुलाई क्षमता बढ़ाना, सरकार का प्रमुख केन्द्र बिंदु रहा है। वर्ष 2018-19 के लिए रेलवे कैपेक्स 1,48,528 करोड़ रुपये रखा गया है। कैपेक्स का बड़ा हिस्सा क्षमता सृजन के लिए है। 18000 किलोमीटर के दोहरीकरण/तीसरी/चौथी लाइन के निर्माण कार्य और 5000 किलोमीटर के गेज परिवर्तन क्षमता के अवरोधों को समाप्त कर देंगे और लगभग समूचे नेटवर्क को ब्राड गेज में बदल देंगे।
94. वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हम लोग रेलवे नेटवर्क के इष्टतम विद्युतीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान 4000 किलोमीटर के प्रारंभण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
95. पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल भाड़ा गलियारों से संबंधित कार्य जोर-शोर से चल रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान पर्याप्त चल स्टॉक 12000 वैगनों, 5160 कोचों और लगभग 700 लोकोमोटिव की खरीदारी की जा रही है। माल शेडों में अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा निजी साइडिंग के फास्ट ट्रैक शुरू करने के लिए एक वृहत कार्यक्रम शुरू किया गया है।
96. 'सुरक्षा सर्वप्रथम' नीति में सुधार पर बल दिया जाता है जो रेलवे की आधारशिला है और जिसे राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के अंतर्गत पर्याप्त निधियों का आबंटन किया जाता है। पटरियों की अवसंरचना के रख-रखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चालू राजकोषीय वर्ष में रेल की लगभग 3600 किमी पटरियों के नवीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अन्य प्रमुख कदमों में फाग सेफ तथा "ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम" जैसी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग बढ़ाना शामिल है। अगले दो वर्षों में 4267 मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर बीजी नेटवर्क में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।
97. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कंपनी लि. द्वारा 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुनः विकसित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। 25000 से अधिक आगंतुकों वाले सभी स्टेशनों में एस्कलेटर होंगे। सभी रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाएगी। सभी स्टेशनों पर और रेलगाड़ियों में सीसीटीवी उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि यात्रियों की संरक्षा बढ़ाई जा सके। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, पेराम्बुर में उन्नत सुविधाओं और विशेषताओं से युक्त आधुनिक ट्रेन-सेट तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे पहले ट्रेन सेटों का प्रारंभण वर्ष 2018-19 के दौरान किया जाएगा।
98. मुंबई की परिवहन प्रणाली, जो शहर की जीवन रेखा है, का विस्तार किया जा रहा है और 11,000 करोड़ रुपये की लागत से इसमें 90 कि. मी. दोहरी पटरियां (डबल लाइन ट्रैक) जोड़ी जा रही हैं। लगभग 40000 करोड़ रुपये की लागत से 150 किमी के अतिरिक्त उप नगरीय नेटवर्क की योजना बनाई जा रही है जिसमें कुछ खंडों में ऊंचे उठे हुए गलियारे शामिल हैं। बेंगलुरु मेट्रोपोलिस के विकास की जरूरतों को पूरा करने लिए 17,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर लगभग 160 किलोमीटर के उपनगरीय नेटवर्क की योजना बनाई जा रही है।
99. भारत की पहली अत्यधिक गति (हाईस्पीड) वाली रेल परियोजना, मुम्बई- अहदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला 14 सितम्बर, 2017 को रखी गई। 'हाई स्पीड' रेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए बड़ोदरा में एक संस्थान स्थापित किया जा रहा है।

100. पिछले तीन वर्षों में घरेलू हवाई यात्री यातायात प्रति वर्ष 18 प्रतिशत बढ़ा और हमारी एयरलाइन कंपनियों ने 900 से अधिक एअरक्राफ्टों की खरीद के लिए आर्डर प्लेस किया है। पिछले वर्ष सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम देश भर के 56 ऐसे हवाई अड्डों और 31 हेलीपैडों में कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी जहां पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे 16 हवाई अड्डों पर प्रचालन शुरू किए जा चुके हैं। सरकार की इस पहल से हवाई चप्पल पहनने वाले नागरिक भी जहाज से यात्रा कर रहे हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास 124 हवाई अड्डे हैं। नई पहले नभ निर्माण स्कीम के अंतर्गत वर्ष में एक बिलियन यात्राओं को संभालने के लिए हमारी हवाई अड्डों की क्षमता का 5 गुने से अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस विस्तार को धन उपलब्ध कराने के लिए अधिक संसाधन जुटाने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के तुलन-पत्र को लिवरेज किया जाएगा।

101. अंतरराष्ट्रीय अच्छी परिपाटियां विकसित करके, सुनम्य आधारभूत सुविधा विकास के लिए समुचित मानक और विनियामक तंत्र विकसित करने के लिए आपदा लोचनीय आधारभूत सुविधा पर सहमिलन स्थापित करने का हमारा प्रयास भलीभांति कार्य कर रहा है। वर्ष 2018-19 में इस पहल को शुरू करने के लिए 60 करोड़ रुपये आबंटित करने का मेरा प्रस्ताव है।

102. सरकार ने अभी बाजार विनियामकों के भारत में आधारभूत सुविधाओं निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) और वास्तविक निवेश न्यास (आरईआईटी) जैसे मुद्रीकरण वाहनों के विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। अगले वर्ष से सरकार इनविट का प्रयोग करते हुए चुनिंदा सीपीएसई आस्तियों के मौद्रिकरण की पहल करेगी।

103. चालू वर्ष में हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रज्जुमार्ग (रोपवे) को शामिल किया, रेलवे स्टेशनों और लाजिस्टिक पार्कों के आस-पास की वाणिज्यिक भूमि के विकास को शामिल करने के लिए रेलवे आधारभूत सुविधा के दायरे का विस्तार किया ताकि उन्हें आधारभूत सुविधा की सुमेलित सूची में शामिल किया जा सके।

104. भारतीय रिजर्व बैंक ने कारपोरेट पहुंच बांड बाजार को टहोका देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सेबी भी बड़े कारपोरेटों से शुरू कर अधिदेश देने पर विचार करेगा ताकि उनकी एक चौथाई वित्तीय जरूरतें बांड बाजारों से पूरी की जा सकें।

105. बीबीबी रेटिंग वाले कारपोरेट बांड या समकक्ष निवेश ग्रेड हैं। भारत में अधिकांश विनियामक (रेगुलेटर) केवल एए रेटिंग बांडों को ही निवेश के उपयुक्त मानकर उनकी अनुमति देते हैं। अब समय आ गया है कि एए से ए ग्रेड रेटिंग की ओर बढ़ा जाए। सरकार और संबंधित विनियामक इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएंगे।

106. राज्यों से परामर्श कर हम वित्तीय प्रतिभूति संव्यवहार से संबंधित स्टॉप ड्यूटी व्यवस्था के संबंध में सुधारात्मक कदम उठाएंगे और भारतीय स्टॉप अधिनियम में आवश्यक संशोधन करेंगे।

107. गिफ्ट सिटी में प्रचालित हो चुके अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) के पूर्ण विकास के लिए एक सशक्त और समेकित विनियामक ढांचे की जरूरत है ताकि वह अपतट वित्तीय केन्द्रों से प्रतिस्पर्धा कर सके। भारत में आईएफएससी की सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए सरकार एक एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करेगी।

108. डिजिटल स्पेस - मशीन लर्निंग, कृत्रिम आसूचना इंटरनेट, 3डी प्रिंटिंग और इसी प्रकार की अन्य विधाओं में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में रूपांतरण हो रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी डिजिटल पहलों से भारत को स्वयं को ज्ञान और डिजिटल सोसाइटी के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। हमारे प्रयासों को अनुप्रयोगों के अनुसंधान और विकास सहित कृत्रिम आसूचना के क्षेत्र निर्देशित करने के लिए नीति आयोग एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ करेगा।

109. साइबर और भौतिक प्रणालियों के संयुक्त रूप देने में न केवल नवोन्मेषी पारिस्थितिकी प्रणाली को रूपांतरित करने की क्षमता है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जीवन शैली में भी बदलाव लाने की क्षमता है। अनुसंधान, रोबोटिक्स, कृत्रिम इंटेलिजेंस, डिजिटल विनिर्माण, बड़े आंकड़ों के विश्लेषण, क्वांटम कम्युनिकेशन और इंटरनेट जैसी बातों में प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना को सहयोग देने के लिए साइबर भौतिक प्रणाली एक मिशन शुरू करेगा। मैंने 2018-19 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए आवंटन को दोगुना करते हुए 3073 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

110. भारत नेट परियोजना के चरण-1 के अंतर्गत तेज गति वाले ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे लगभग दो लाख पचास हजार गांवों में 20 करोड़ ग्रामीण भारतीयों तक ब्राडबैंड की सुविधा सुलभ करवाई जा सकी है। सरकार का विचार पांच लाख वाई फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का भी है जिनमें पांच करोड़ भारतीयों को ब्राडबैंड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मैंने 2018-19 में दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और संवर्धन के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

111. उदीयमान नई प्रौद्योगिकियों, विशेषकर 'फिफ्थ जनरेशन' (5जी) प्रौद्योगिकियों और इसको अपनाने को गति देने के लिए दूरसंचार विभाग, आईआईटी, चेन्नई में स्वदेशी 5जी टेस्टबेड स्थापित करने में सहायता उपलब्ध करवाएगा।

112. डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम या ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में मध्यवर्तियों की जरूरत के बिना रिकार्डों या संव्यवहार की श्रृंखला के आर्गेनाइजेशन की अनुमति होती है। सरकार क्रिप्टो-करेंसी लीगल टेंडर या क्वाइन पर विचार नहीं करती है और अवैध गतिविधियों को धन उपलब्ध कराने अथवा भुगतान प्रणाली के एक भाग के रूप में इन क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रयोग को समाप्त करने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाएगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए सरकार ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के प्रयोग की संभावना तलाशने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगी।

113. सड़क स्थित टोल प्लाजा पर भौतिक रूप से नकद में टोल टैक्स भुगतान की प्रणाली का शीघ्र ही फास्टेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां स्थान लेने जा रही हैं इससे सड़क मार्ग से यात्रा निर्बाध होगी। फास्टेज की संख्या दिसम्बर, 2016 में लगभग 60,000 से बढ़कर वर्तमान में 10 लाख से अधिक हो चुकी है। दिसम्बर, 2017 से "एम" और "एन" श्रेणी के सभी वाहन फास्टेज के साथ ही बेचे जा रहे हैं। सरकार टोल प्रणाली को "प्रयोग की तरह भुगतान" आधार पर प्रारम्भ करने के लिए एक नीति लाएगी।

114. रोजगार सृजन और सहायता वृद्धि के उद्देश्य से, वर्ष 2018-19 के लिए आधारभूत सुविधा पर सरकार के अनुमानित बजटीय और अतिरिक्त बजटीय व्यय को वर्ष 2017-18 में 4.94 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के मुकाबले बढ़ाकर 5.97 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है।

संस्थाओं का निर्माण तथा सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार

115. अपनी सीमाओं पर हमारे द्वारा सामना किए जाने वाली चुनौतियों से निपटने और जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तरपूर्व दोनों में आंतरिक सुरक्षा माहौल की व्यवस्था करने में सशस्त्र बलों ने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्र हित की रक्षा करने में सेना की तीनों सेवाओं द्वारा किए गए प्रयासों और बलिदानों के लिए मैं उनकी भूरि-भूरि सराहना करना चाहूंगा।

116. वर्ष 2014 में जबसे एनडीए सरकार ने कार्यभार संभाला है, रक्षा बलों की प्रचालनात्मक सामर्थ्य के आधुनिकीकरण और अभिवर्धन के लिए काफी जोर दिया गया है। अपनी रक्षा संबंधी जरूरतें पूरी करने में राष्ट्र को आत्म निर्भर बनाने के लिए आंतरिक रक्षा उत्पादन सामर्थ्य को विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। हमारी प्राथमिकता प्रर्याप्त बजटीय सहायता सुनिश्चित करना होगी।

117. हमने रक्षा उत्पादन में निजी निवेश के दरवाजे खोल दिए हैं, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को और उदार बनया गया है। हम देश में रक्षा उद्योग के उत्पादन के लिए दो गलियारे विकसित करने के लिए कदम उठाएंगे। सरकार उद्योग अनुकूल रक्षा उत्पादन नीति, 2018 का पदार्पण करेगी ताकि सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।

118. आधार से प्रत्येक भारतीय को पहचान मिली है। आधार के माध्यम से हमारे लोगों को अनेक सार्वजनिक सेवाएं सरलता से मिलने लगी हैं। प्रत्येक छोटे या बड़े उद्यम को भी विशिष्ट पहचान (यूनिक आईडी) की आवश्यकता है। सरकार भारत में प्रत्येक उद्यम को अलग से एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की स्कीम लाएगी।

119. 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' के लिए व्यावसायिक सुधारों को देश के और भीतर तक तथ प्रत्येक राज्य में पहुंचाने के लिए, भारत सरकार ने व्यवसाय के 372 विशिष्ट कार्यक्रमों की पहचान की है। सभी राज्यों ने इन सुधारों को और सरल बनाने की प्रक्रियाओं के एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए एक अभियान के रूप में लिया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन अब प्रयोगकर्ता से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाएगा।

120. भारतीय खाद्य निगम के पूंजीगत ढांचे को पुनः तैयार किया जाएगा ताकि इसकी स्थाई कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इक्विटी को बढ़ाया जा सके और लंबी अवधि के ऋणों को उगाहा जा सके।

121. इक्विटी में भारत सरकार के अंशदान और राज्य सरकारों द्वारा संचालित मेट्रो उद्यमों के ऋण की बजट प्रक्रिया को कारगर बनाया जाएगा।

122. वाणिज्य विभाग सभी स्ट्रेकधारकों को आपस में जोड़ने के लिए एक सिंगल विंडो ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल तैयार करने जा रहा है।

123. सरकार ने दो बीमा कंपनियों सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 14 उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने का अनुमोदन किया है। सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 24 उद्यमों में सामरिक विनिवेश की प्रक्रिया भी प्रारंभ की है। इसमें एयर इंडिया का सामरिक निजीकरण भी शामिल है।

124. ओएनजीसी द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के अधिग्रहण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई है। सरकारी क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियां नैशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि. और ओरियंटल इंडिया इश्योरेंस कंपनी लि. को एक बीमा कंपनी में आमेलित किया जाएगा और बाद में इसे सूचीबद्ध किया जाएगा।

125. सरकार ने 14,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए एक्सचेंज ट्रेड फंड भारत-22 को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत सभी ओर से अपेक्षा से कहीं अधिक रकम जुटाई गई। दीपम ऋण ईटीएफ सहित ईटीएफ के और अधिक पेशकश लाएगा।

126. विनिवेश के लिए वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान अब तक के उच्चतम स्तर 72,500 करोड़ रुपये पर स्थिर रहे। मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम बजट अनुमानों के लक्ष्य से आगे बढ़ निकल गए हैं। 2017-18 में 1,00,000 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान लगा रहा हूँ। इसलिए 2018-19 के लिए 80,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रख रहा हूँ।

127. बैंक पुनः पूंजीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत इस वर्ष 80,000 करोड़ रुपये के बांड जारी किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को एक एनहानस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस (ईज) कार्यक्रम के दिशानिर्देश के तहत एक महत्वाकांक्षी सुधार एजेंडे के साथ समेकित किया गया है। इस पुनःपूंजीकरण प्रक्रिया से 5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण देने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का मार्ग प्रशस्त होगा।

128. सुदृढ़ साख वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ताकि इन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी साख को और बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके।

129. राष्ट्रीय आवास बैंक की इक्विटी को भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार को अंतरित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। भारतीय डाकघर अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अधिनियम को समामेलित किया जा रहा है और इसमें कुछ लोक हितैषी उपाय जोड़े जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक नकदी व्यवस्थित करने के साधन उपलब्ध कराने और असंपार्श्विक जमा सुविधा को संस्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 को संशोधित किया जा रहा है ताकि न्याय निर्णयन प्रक्रियाओं को कारगर बनाया जा सके और कुछ उल्लंघनों के लिए दंड का प्रावधान किया जा सके। ये प्रस्ताव इस वित्त विधेयक में रखे गए हैं।

130. सभी विस्तृत अनुदान मांगों को सरलता से उपलब्ध कराने के लिए इनके लिंक india.gov.in पर दिए जाएंगे। सरकार प्रकट की गई राजकोषीय सूचना को मशीन रीडेबल फार्म में उपलब्ध कराने की व्यावहारिकता पर भी विचार करेगी।

131. सरकार केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में ई-आफिस और ई-गवर्नेंस से संबंधित पहलों को शुरू करते हुए अपने कार्यचलन के सुचारु निपटान की पद्धति में बदलाव ला रही है। इन पहलों को अनुबंध-IV में सूचीबद्ध किया गया है।

132. सरकार सोने को एक आस्ति की श्रेणी में लाने के लिए एक व्यापक गोल्ड पॉलिसी बनाएगी। सरकार देश में सोने के विनियमित आदान-प्रदान की उपभोक्ता हितैषी और व्यापार दक्ष प्रणाली भी स्थापित करेगी। सोना मौद्रिकरण स्कीम को पुनः सुदृढ़ किया जाएगा ताकि लोग गोल्ड डिपोजिट खाता बिना किसी परेशानी के खोल सकें।

133. भारत की ओर से बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) प्रतिवर्ष 15 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। सरकार मौजूदा दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं की समीक्षा करेगी और एक सुसंगत और समेकित बहिर्गामी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) नीति लाएगी।

134. विभिन्न उपयुक्त क्षेत्रों में, विशेषकर स्टार्टअप और उद्यमी पूंजीगत फर्मों के लिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मिले-जुले साधन उपयुक्त हैं।

135. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की परिलब्धियों में पिछली बार 1 जनवरी, 2006 से संशोधन किया गया था। इन परिलब्धियों में संशोधन करने और माननीय राष्ट्रपति के लिए प्रतिमाह 5 लाख रुपए, उप-राष्ट्रपति के लिए प्रतिमाह 4 लाख रुपए तथा राज्यपालों के लिए प्रति माह 3.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

136. संसद सदस्यों को भुगतान की जाने वाली परिलब्धियों के संबंध में जनता के बीच वाद-विवाद होता रहा। मौजूदा कार्यपद्धति में प्राप्तकर्ताओं को अपनी खुद की परिलब्धि निर्धारित करने की अनुमति है, जिससे आलोचना होती है। अतः, मैं 1 अप्रैल, 2018 से संसद सदस्यों को भुगतान योग्य वेतन, चुनाव क्षेत्र भत्ता, कार्यालयी व्यय, बैठक भत्ता पुनः निर्धारित करने के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने का प्रस्ताव रखता हूँ। विधि में भी मुद्रास्फीति के अधिसूचक के रूप में प्रत्येक 5 वर्षों में परिलब्धियों के संशोधन का प्रावधान होगा। मुझे विश्वास है कि सदस्य इस पहल का स्वागत करेंगे और भविष्य में उन्हें ऐसी आलोचना नहीं झेलनी पड़ेगी।

137. हमारे देश में 2 अक्टूबर, 2019 से 2 अक्टूबर, 2020 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। सरकार और भारत की जनता उन आदर्शों के प्रति अपने कार्यों द्वारा अपने आपको पुनः समर्पित करेंगे जिन्हें महात्मा गांधी ने सिखाया और अपना जीवन जिसके अनुसार जिया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विभिन्न रणनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, गांधीवादियों, चिंतकों और जीवन के सभी क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को शामिल करके स्मरण समारोह कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। स्मरण समारोह से संबंधित क्रिया-कलापों के लिए वर्ष 2018-19 के लिए मेरी सरकार ने डेढ़ सौ करोड़ रुपए अलग से रखे हैं।

भाग-III राजकोषीय प्रबंधन

138. अब मैं 2017-18 के लिए राजकोषीय कुल उत्पादन और 2018-19 के लिए राजकोषीय अनुमानों की ओर आता हूँ।

139. 2017-18 में, केन्द्रीय सरकार को 12 महिने के बजाए केवल 11 महिने के लिए जीएसटी राजस्व प्राप्त होगा। इसका राजकोषीय प्रभाव पड़ेगा। कुछ घटनाक्रम के कारण कर-भिन्न राजस्व में कुछ कमी भी आई जिनमें स्पेक्ट्रम निलामी का स्थगन शामिल है। इस कमी के कुछ भाग की भरपाई उच्चतर प्रत्यक्ष कर राजस्व और अधिक विनिवेश प्राप्तियों के द्वारा की गई है।

140. 2017-18 में व्यय के लिए कुल संशोधित अनुमान 21.47 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 21.57 लाख करोड़ रुपए (राज्यों को अंतरित जीएसटी प्रतिपूर्ति को घटाकर) है।

141. हमारी सरकार ने मई, 2014 में कार्यभार संभाला, जब राजकोषीय घाटा बहुत उच्च स्तर की ओर बढ़ रहा था। 2013-14 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत था। प्रधानमंत्री और सरकार विवेकशील राजकोषीय प्रबंधन और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने को हमेशा उच्च प्राथमिकता देती है। जैसाकि माननीय सदस्यों को स्मरण होगा, हमने 2014 में लगातार राजकोषीय कमी समेकन के पथ पर आगे बढ़े हैं। 2014-15 में, राजकोषीय घाटा कम करके 4.1 प्रतिशत और 2015-16 में 3.9 प्रतिशत पर लाया गया तथा 2016-17 में 3.5 प्रतिशत कर दिया गया। 2017-18 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा का अनुमान 5.95 लाख करोड़ रुपए है जो जीडीपी का 3.5 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 के लिए मैं जीडीपी के 3.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का अनुमान लगा रहा हूँ।

142. संशोधित राजकोषीय मार्गदर्शन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के प्रति असंदिग्ध विश्वसनीयता लाने के लिए ऋण नियम को अंगीकार करने और जीडीपी अनुपात की तुलना में केन्द्रीय सरकार के ऋण को 40 प्रतिशत नीचे लाने से संबंधित राजकोषीय सुधार और बजट प्रबंधन समिति की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकार ने भी राजकोषीय घाटा लक्ष्य को प्रमुख प्रचालनात्मक मानदण्ड के रूप में उपयोग करने की सिफारिश मान ली है। आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव वित्त विधेयक में हैं।

भाग-ख

अध्यक्ष महोदय,

143. अब मैं अपने कर प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूँ।

144. सरकार द्वारा नकदी की अर्थव्यवस्था घटाने तथा कर ढांचे में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने के लिए किए गए प्रयास से काफी अधिक लाभ प्राप्त हुए हैं। वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में प्रत्यक्ष करों की वृद्धि दर पर्याप्त रही है। हमने पिछले वर्ष 12.6 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की थी तथा चालू वर्ष के दौरान 15 जनवरी, 2018 तक प्रत्यक्ष कर की वृद्धि दर 18.7% है। इन दो वर्षों से पूर्व के सात वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आय कर में औसत वृद्धि का आंकड़ा 1.1 रहा है। साधारण शब्दों में कर में 1.1 के उछाल का अर्थ है कि यदि देश में जीडीपी की नाममात्रिक वृद्धि दर 10% होतो व्यक्तिगत आयकर की वृद्धि दर 11% होगी। तथापि, वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 (सं.अ.) में व्यक्तिगत आय कर में उछाल का आंकड़ा क्रमशः 1.95 और 2.11 दर्ज किया गया है। इससे यह सूचित होता है कि गत दो वित्त वर्ष के दौरान आयकर से संगृहीत अधिक राजस्व की राशि 2016-17 से पूर्व की औसत वृद्धि की तुलना में कुल लगभग ₹90,000 करोड़ है तथा इसका श्रेय सरकार द्वारा किए गए कर वंचन रोधी उपायों को दिया जा सकता है।

145. इसी प्रकार, कर दाताओं द्वारा दर्ज कराई गई विवरणियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 85.51 लाख नए कर दाताओं ने अपनी आय विवरणी दर्ज कराई है जबकि इससे ठीक

पूर्ववर्ती वर्ष में 66.26 लाख व्यक्तियों ने अपनी विवरणी दर्ज कराई थी। विवरणी दर्ज करने वाले नए व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जो विवरणी दर्ज नहीं कराते किंतु जिन्होंने अग्रिम कर यह स्रोत पर कर कटौती के द्वारा कर का भुगतान किया है, हम प्रभावी कर दावा आधार का चित्र प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावी करदाता आधार के संबंध में यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2014-15 के आरंभ के 6.47 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर 8.27 करोड़ हो गया। हम अपने उपायों की सफलताओं के लिए स्वयं को उत्साहित महसूस करते हैं तथा वचन देते हैं कि हम भविष्य में वे सभी उपाय करना जारी रखेंगे जिनसे काले धन पर रोक लगाई जा सके तथा ईमानदार कर दाताओं को पुरस्कृत किया जा सके। केवल यही एकमात्र कारण है कि ईमानदार कर दाताओं द्वारा विमुद्रीकरण का "ईमानदारी के उत्सव" के रूप में भारी स्वागत किया गया।

146. अध्यक्ष महोदया, अनुपालन को सरल बनाने के लिए सरकार ने ₹2 करोड़ से कम के वार्षिक टर्न ओवर वाले छोटे व्यापारियों तथा उद्यमियों के लिए अनुमानित आय योजना को उदार बनाया था तथा जिन व्यावसायिकों का वार्षिक टर्न ओवर ₹50 लाख से कम था, उनके लिए भी इसी प्रकार की योजना आरंभ की थी जो इस उम्मीद से की गई थी कि सरकार की इस योजना के अनुपालन में पर्याप्त वृद्धि होगी। इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान 41% अधिक विवरणी दर्ज कराई गई जिससे यह पता चलता है कि सरलीकृत योजना के अंतर्गत अन्य बहुत से लोग शामिल हुए। तथापि, दर्शाया गया टर्न ओवर अभी भी उत्साहवर्धक नहीं है। विभाग को निर्धारण वर्ष 2017-18 के दौरान व्यक्तिगत कर दाताओं और ₹17.97 लाख के कम औसत टर्न ओवर वाले हिन्दू अविवाहित परिवार (एचयूएफ) तथा फर्मों से 44.72 लाख विवरणियां प्राप्त हुई हैं जिनका औसत कर भुगतान मात्र ₹7,000 है। व्यावसायिकों द्वारा बेहतर कर अनुपालन आचरण प्रदर्शित नहीं किया गया है। विभाग को निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित आय योजना के अंतर्गत 5.68 लाख विवरणियां प्राप्त हुई हैं तथा औसत सकल प्राप्तियां मात्र ₹5.73 लाख हैं। इनके द्वारा भुगतान किया गया औसत कर मात्र ₹35000 है।

कृषि के संबंध में फसल कटाई के उपरांत क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहन

147. अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में प्राथमिक कृषि क्रियाकलापों में जुटे अपने सदस्यों को सहायता प्रदान करने वाले सहकारी समितियों के लाभ के संबंध में शत-प्रतिशत कर कटौती की अनुमति दी गई है। गत कुछ वर्षों के दौरान सहकारी समितियों की तर्ज पर अनेक किसान उत्पादक कंपनियां स्थापित की गई हैं जो अपने सदस्यों को इसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। कृषि में फसल कटाई के उपरांत मूल्य वर्धन में व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें वित्त वर्ष 2018-19 से पांच वर्षों की अवधि तक ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्त लाभ के संबंध में ₹100 करोड़ तक के वार्षिक टर्न ओवर वाली किसान उत्पादक कंपनियों के रूप में पंजीकृत इन कंपनियों को शत-प्रतिशत कर कटौती अनुमत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस उपाय से मैंने पूर्व में जिसे मिशन ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की थी उसे प्रोत्साहन प्राप्त होगा तथा संपदा योजना को बढ़ावा मिलेगा।

रोजगार सृजन

148. वर्तमान में, वर्ष के अंतर्गत न्यूनतम 240 दिनों की अवधि तक काम करने वाले पात्र नए कर्मचारियों को उनकी परिलब्धियों पर आयकर अधिनियम की धारा 80-अजकक के अंतर्गत 100% सामान्य कर कटौती के अतिरिक्त 30% की कटौती की अनुमति प्रदान की जाती है। तथापि, परिधान उद्योग के मामले में रोजगार की न्यूनतम अवधि कम करके 150 दिन कर दी गई है। नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैं इस छूट को जूते एवं चमड़ा उद्योग में भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, मैं यह प्रस्ताव भी करता

हूँ कि पहले वर्ष के दौरान न्यूनतम से कम अवधि तक रोजगार में रहे किसी नए कर्मचारी जो परवर्ती वर्ष में न्यूनतम अवधि तक रोजगार में बना रहता है, के संबंध में लाभ की अनुमति प्रदान करके 30% की इस कटौती को युक्ति-संगत बनाया जाए।

रियल एस्टेट के लिए प्रोत्साहन

149. वर्तमान में अचल संपत्ति के सौदों के संबंध में पूंजीगत प्राप्ति, व्यावसायिक लाभों तथा अन्य स्रोतों से आय के लिए कर का निर्धारण करते समय प्राप्त प्रतिलाभ सर्किल दर मूल्य जो भी अधिक हो, की स्वीकार किया जाता है तथा अंतर का क्रेता और विक्रेता दोनों के हाथ में पहुंचे आय के रूप में परिकलन किया जाता है। कभी-कभी भूखंड की आकृति तथा अवस्थिति सहित अनेक कारणों से एक ही क्षेत्र में स्थित भिन्न-भिन्न संपत्तियों के मूल्य में अंतर हो सकता है। रियल एस्टेट सौदों में कठिनाई को न्यूनतम करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जिस मामले में सर्किल दर मूल्य तथा भूखंड के निर्धारित मूल्य 5% से अधिक न हो उसमें कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहन

150. केन्द्रीय बजट, 2017 में मैंने जिन कंपनियों का टर्न ओवर वित्त वर्ष 2015-16 में ₹50 करोड़ से कम था उनके लिए कारपोरेट कर दर घटाकर 25% करने की घोषणा की थी। इससे कर विवरणी जमा करने वाली कुल कंपनियों में से 96% को लाभ पहुँचा। कारपोरेट कर दर को चरणबद्ध रूप में घटाने के लिए मैंने जो वचन दिया था उसे पूरा करते हुए मैं अब प्रस्ताव करता हूँ कि इस घटाए गए 25% दर का लाभ उन कंपनियों को भी दिया जाए जिन्होंने वित्त वर्ष 2016-2017 में ₹250 करोड़ तक टर्न ओवर होने की सूचना दी है। इससे संपूर्ण श्रेणी के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों जिनकी संख्या कर विवरणी भरने वाली समस्त कंपनियों का लगभग 99% है, को लाभ पहुँचेगा। इस उपाय के कारण परित्यक्त राजस्व वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹7,000 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद कर विवरणी भरने वाली लगभग 7 लाख कंपनियों में से लगभग 7000 कंपनियां हैं जो कर विवरणी भरती हैं तथा जिनका टर्न ओवर ₹250 करोड़ से अधिक है, 30% के स्लैब में रहेंगी। 99% कंपनियों के लिए कारपोरेट आयकर की कम दर होने से उन्हें अधिक मात्रा में निवेश योग्य अधिशेष राशि प्राप्त होगी जिससे अधिक रोजगार सृजित होंगे।

वेतनभोगी कर दाताओं को राहत

151. सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान व्यक्तिगत आय कर की दरों में अनेक लाभकारी परिवर्तन किए हैं। अतः मैं व्यक्तिगत आयकर के दर-ढांचे में किसी और बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता हूँ। समाज में एक सामान्य विचार व्याप्त रहा है कि वेतनभोगी वर्ग की तुलना में व्यक्तिगत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की आय बेहतर होती है। तथापि, आयकर आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि व्यक्तिगत आय कर संग्रहण का मुख्य भाग केवल वेतनभोगी वर्ग से ही आता है। निर्धारण वर्ष 2016-17 के दौरान 1.89 करोड़ वेतनभोगी व्यक्तियों ने अपनी कर विवरणी जमा कराई है तथा कुल ₹1.44 लाख करोड़ का कर भुगतान किया है जो प्रति व्यक्ति औसतन ₹76306 कर भुगतान बनता है। इसके मुकाबले, व्यावसायिकों सहित 1.88 करोड़ व्यक्तिगत व्यवसाय से जुड़े कर दाताओं ने इसी निर्धारण वर्ष के लिए अपनी विवरणी भरी तथा कुल ₹48,000 करोड़ का कर भुगतान किया जो औसतन प्रति व्यक्ति व्यावसायिक करदाता ₹25753 बनता है। वेतनभोगी करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि परिवहन भत्ता के संबंध में मौजूदा छूट तथा विविध चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति के बदले में ₹40,000 तक की मानक कटौती की अनुमति दी जाए। तथापि, दिव्यांग व्यक्तियों को

वर्धित दर पर परिवहन भत्ता देना जारी रखा जाए। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों के संबंध में अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कराए गए उपचार आदि के संबंध में अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति लाभ जारी रहेंगे। कागजी कार्यवाही को कम करने तथा इसके अनुपालन के लिए इससे मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी कर योग्यता में कमी के रूप में कही अधिक लाभ पहुँचेगा। मानक कटौती किए जाने के इस निर्णय से पेंशनभोगियों को भी पर्याप्त लाभ पहुँचेगा जिन्हें परिवहन तथा चिकित्सा व्यय के मद में कोई छूट नहीं प्राप्त हाती है। इस निर्णय की राजस्व लागत लगभग ₹8,000 करोड़ है। इस निर्णय से लाभान्वित होने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों की कुल संख्या लगभग 2.5 करोड़ है।

वरिष्ठ नागरिकों को राहत

152. गरिमा के साथ जीवन यापन करना हरेक व्यक्ति और विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार है। जिन लोगों ने हमारी देखभाल की उनकी देखभाल करना उन्हें सर्वोच्च सम्मान प्रदान करना है। इन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन देने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों की घोषणा करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- ◆ बैंकों तथा डाकघरों में जमा राशि पर ब्याज आय में छूट ₹10000 से बढ़ाकर ₹50000 करना तथा ऐसी आय पर धारा 194क के अंतर्गत स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी। यह लाभ सावधि जमा योजनाओं तथा आवर्ती जमा योजनाओं में प्राप्त होने वाले ब्याज के लिए भी उपलब्ध होगा।
- ◆ धारा 80घ के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और / या चिकित्सा व्यय हेतु कटौती सीमा को 30,000/- रुपए से बढ़ाकर 50,000/- रुपए तक करना। अब सभी वरिष्ठ नागरिक किसी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और / या किए गए किसी सामान्य चिकित्सा के संबंध में 50,000/- रुपए प्रतिवर्ष तक कटौती के लाभ का दावा कर सकेंगे।
- ◆ धारा 80घघख के तहत कतिपय गंभीर रुग्णता के संबंध में चिकित्सा व्यय के लिए कटौती सीमा को वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 60,000/- रुपए से और अति वरिष्ठ नागरिकों के मामले में 80,000/- रुपए से बढ़ाकर, सभी नागरिकों के संबंध में 1 लाख रुपए तक करना।

इन रियायतों से वरिष्ठ नागरिकों को 4000/- रुपए का अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त होगा। इन कर रियायतों के अतिरिक्त, मैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का मार्च, 2020 तक विस्तार किए जाने का प्रस्ताव करता हूँ जिसके अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 8% सुनिश्चित प्रतिलाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक 7.5 लाख रुपए का मौजूदा निवेश सीमा भी बढ़ाकर 15 लाख रुपए तक की जा रही है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के लिए कर-प्रोत्साहन

153. सरकार ने भारत में एक विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विकसित करने का प्रयास किया था। हाल के वर्षों में, उस उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से कर प्रोत्साहनों सहित विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, मैं, आईएफएससी को दो और रियायतें प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। आईएफएससी में स्थित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा व्युत्पन्न और कतिपय प्रतिभूतियों के अंतरण को पूंजी लाभ कर से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अलावा, आईएफएससी में संचालन करने वाले कार्पोरेट-भिन्न करदाताओं से कार्पोरेट के लिए अनुप्रयोग्य न्यूनतम वैकल्पिक कर (मेट) के बराबर 9% की रियायती दर पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (एएमटी) प्रभारित किया जाएगा।

नकदी अर्थव्यवस्था के नियंत्रण हेतु किए गए अन्य उपाय

154. वर्तमान में, न्यासों और संस्थाओं को आयकर से छूट प्राप्त है यदि वे अपना आय का आयकर अधिनियम के प्रासंगिक उपबंधों के अनुसार अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करें। तथापि, इन संस्थाओं पर नकद व्यय करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय की लेखा परीक्षा जांच कराने के उद्देश्य से, यह प्रस्ताव है कि ऐसी संस्थाओं द्वारा नकद किए गए 10,000/- रुपए से अधिक भुगतानों की अनुमति नहीं होगी और ये कर के अध्यक्षीन होंगे। इसके अलावा, इन संस्थाओं द्वारा टीडीएस अनुपालन में सुधार लाने के उद्देश्य से, मैं यह प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ कि कर-कटौती न किए जाने पर, 30% धनराशि की अनुमति नहीं होगी और इस पर कर लगेगा।

दीर्घावधिक पूंजी लाभ (एलटीसीजी) का यौक्तिकीकरण

155. अध्यक्ष महोदया, फिलहाल, सूचबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी उन्मुख निधि की यूनितों और व्यवसाय न्यास की यूनितों के अंतरण से प्रोद्भूत दीर्घावधिक पूंजी लाभ कर से छूट प्राप्त हैं। सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारों और अभी तक दिए गए प्रोत्साहनों के साथ, इक्विटी बाजार में उछाल आया है। निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तुत की गई विवरणियों के अनुसार, सूचीबद्ध शेयरों और यूनितों से छूट प्राप्त पूंजी लाभ की राशि लगभग 3,67,000 करोड़ रुपए है। इस लाभ का बड़ा भाग कार्पोरेट और एलएलपी को गया है। इससे विनिर्माण के प्रति झुकाव भी सृजित हुआ है, जिसकी वजह से वित्तीय परिसंपत्तियों में और अधिक कारोबारी अधिशेष राशि का निवेश किया जा रहा है। इक्विटी में निवेश पर प्रतिलाभ कर छूट के बगैर भी पहले से ही काफी आकर्षक है। अतः सूचीबद्ध इक्विटियों से दीर्घावधिक पूंजी लाभ को कर के दायरे में लाना आवश्यक है। तथापि, इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि आर्थिक वृद्धि के लिए गतिशील इक्विटी बाजार आवश्यक है, मैं मौजूदा व्यवस्था में केवल एक छोटा सा बदलाव करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, 1 लाख रुपए से अधिक के ऐसे दीर्घावधिक पूंजी लाभों पर किसी सूचकांकन के बिना 10% की दर से कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, दिनांक 31 जनवरी 2018 तक के सभी लाभ इस प्रकार संरक्षित होंगे। उदाहरणार्थ, यदि कोई इक्विटी शेयर 31 जनवरी, 2018 से छः माह पूर्व 100/- रुपए पर खरीदा जाता है और इस शेयर के संबंध में 31 जनवरी, 2018 को उद्भूत उच्चतम मूल्य 120/- रुपए है, तो यदि यह शेयर इसकी खरीद की तारीख से एक वर्ष पश्चात बेचा जाता है तक 20/- रुपए के लाभ पर कोई भी कर नहीं लगेगा। तथापि, 31 जनवरी, 2018 के पश्चात अर्जित 20/- रुपए से अधिक के किसी लाभ को 31 जुलाई, 2018 के बाद बेचे जाने पर 10% की दर से कर लगेगा। एक वर्ष तक धारित इक्विटी शेयर से लाभ अल्पावधिक पूंजी लाभ रहेगा और इस पर 15% की दर से कर लगाया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, मैं इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड द्वारा वितरित आय पर 10% की दर से कर प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। यह समस्त वृद्धि उन्मुख निधियों और लाभांश संवितरण निधियों के लिए समान कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराएगा। संरक्षित किए जाने के दृष्टिगत, पूंजी लाभ कर में यह बदलाव पहले वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का सीमांत राजस्व लाभ लाएगा। बाद के वर्षों में यह राजस्व अधिक हो सकता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर

156. अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में व्यक्तिगत आयकर और निगम कर पर तीन प्रतिशत उपकर - प्राथमिक शिक्षा पर दो प्रतिशत उपकर और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत उपकर सहित - है। बीपीएल और ग्रामीण परिवारों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए मैंने अपने भाषण के भाग क में कार्यक्रमों की घोषणा की है। इसे वित्तपोषित करने के लिए, मैं उपकर को एक प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। विद्यमान तीन प्रतिशत शिक्षा उपकर के स्थान पर देय कर पर लगाए जाने वाला चार प्रतिशत “स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर” प्रतिस्थापित किया जाएगा। इससे हम 11,000 करोड़ रुपये की अनुमानित अतिरिक्त धनराशि संगृहीत करने में समर्थ होंगे।

ई-निर्धारण

157. हमने वर्ष 2016 में प्रायोगिक आधार पर ई-निर्धारण प्रारंभ किया है और 2017 में विभाग और करदाताओं के बीच इंटरफेस में कमी लाने के उद्देश्य से 102 नगरों तक इसका विस्तार किया है। अभी तक प्राप्त हुए अनुभव से, अब हम ई-निर्धारण को पूरे देश में लागू करने के लिए तैयार हैं, जो आयकर विभाग की काफी पुरानी कर निर्धारण प्रक्रिया और उस विधि को रूपांतरित कर देगी जिसमें वे करदाताओं और अन्य हितधारकों के साथ व्यवहार करता था। तदनुसार, मैं निर्धारण के लिए एक नई योजना को अधिसूचित करने के लिए आयकर अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ जिसमें कर निर्धारण इलैक्ट्रॉनिक विधि से किया जाएगा जिससे व्यक्ति दर व्यक्ति से संपर्क करने की प्रक्रिया का उन्मूलन हो जाएगा जिससे कार्यक्षमता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

158. प्रत्यक्ष कर संबंधी अन्य कर प्रस्ताव मेरे भाषण के अनुबंध V में सूचीबद्ध किए गए हैं।

अप्रत्यक्ष कर

159. अप्रत्यक्ष कर के संबंध में, माल और सेवा कर लागू होने के पश्चात यह पहला बजट है। आयात पर तदनुसृत शुल्क के साथ, उत्पाद शुल्क को काफी हद तक और सेवा कर को जीएसटी में मिला दिया गया है। अतः, मेरे बजट प्रस्ताव मुख्य रूप से सीमा शुल्क के संबंध में हैं।

160. इस बजट में, मैं विगत दो दशकों से चली आ रही मूलभूत नीति से आंशिक रूप से विचलन कर रहा हूँ जिसमें सीमा शुल्क को कम करने पर अधिक बल दिया गया था कुछ क्षेत्रों खाद्य प्रसंस्करण, इलैक्ट्रॉनिक्स, ऑटो घटक, फुटवियर और फर्नीचर में घरेलू मूल्य वर्द्धन की व्यापक संभावनाएं हैं। ऐसे कुछ क्षेत्रों में घरेलू मूल्यवर्द्धन और मेक-इन-इंडिया को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए, मैं कुछ मदों पर सीमा शुल्क को बढ़ा रहा हूँ। मैं मोबाइल फोनों पर सीमा शुल्क को 15% से बढ़ाकर 20% करने, उनके कुछ पुर्जों और सहायक सामग्री पर 15% तक और टी.वी. के कतिपय पुर्जों पर 15% तक तक सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। इस कदम से देश में नौकरियों के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। सीमा शुल्क की दरों में और उत्पाद शुल्क के ढांचे में किए गए कतिपय बदलावों का ब्यौरा मेरे भाषण के अनुबंध 6 में दिया गया है।

161. काजू प्रसंस्करण उद्योग की सहायता के लिए, मैं कच्चे काजू पर सीमा शुल्क को 5% से घटा कर 2.5% करने का प्रस्ताव करता हूँ।

162. मैं आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा उपकर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ और इसके स्थान पर आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क की समग्र ड्यूटियों का 10% की दर से सामाजिक कल्याण अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि सरकार की सामाजिक कल्याण की स्कीमों के लिए प्रावधान किया जा सके। तथापि, वे वस्तुएं जो अब तक आयात पर शिक्षा उपकरों से छूट-प्राप्त थी, इस अधिभार से मुक्त होंगी। इसके अतिरिक्त, मेरे भाषण के अनुबंध 6 में दी गई कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर केवल सीमा शुल्क की समग्र शुल्कों पर की 3% की दर से प्रस्तावित अधिभार लगाया जाएगा।

163. मैं सीमा पार व्यापार में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में और सुधार लाने तथा व्यापार सुगमता करार के अंतर्गत इसके कतिपय उपबंधों को इसकी वचनबद्धताओं के अनुरूप बनाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में कुछ परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। विवादों को निपटाने की प्रक्रिया को सरल बनाने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कुछ संशोधन किए जा रहे हैं, ताकि नोटिस भेजने से पहले परामर्श, फैसले के लिए निश्चित समय-सीमा और इन समय-सीमाओं का पालन नहीं किए जाने पर मुकदमे को पूरी तरह बंद करने का प्रावधान किया जा सके।

164. जीएसटी को लागू किए जाने के मद्देनजर, मैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके लिए कानून में आवश्यक परिवर्तनों का प्रस्ताव वित्त विधेयक में किया गया है।

165. अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष के बजट में प्रस्ताव करते समय हमें कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एमएसएमई और भारतीय अर्थव्यवस्था की अवसंरचना के क्षेत्र को विशेष रूप से सुदृढ़ करने के मिशन द्वारा मार्गदर्शन मिला है। मुझे विश्वास है कि जिस नए भारत का निर्माण करने की हम आकांक्षा रखते हैं, वह जरूर आएगा। स्वामी विवेकानन्द ने भी यूरोप की यात्रा के दौरान के अपने संस्मरण में दशकों पहले कल्पना की थी। "आप स्वयं को उस रिक्ति में विलय कर दें और विलुप्त हो जाएं तथा अपने स्थान पर नए भारत का सृजन होने दें। उसे किसानों की कुटिया से, हल के जुए से; ... झोपड़ी से उत्पन्न होने दें। उसे किराना दुकानदार की दुकान से तथा पकौड़ा, फल या सब्जी बेचने वाले के चुल्हों की बगल से सृजित होने दें। उसे कारखानों से, हाटों से, बाजारों से उभरकर आने दें। उसे बाग-बगीचों से पहाड़ियों से तथा पर्वत श्रृंखलाओं से विकसित होने दें।"

166. इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदया मैं सदन में बजट पेश करता हूँ।

प्रशांत गोयल, संयुक्त सचिव (बजट)

अनुबंध I

(पैरा 45 में दिए गए अनुसार)

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आजीविका कार्यक्रमों के संबंध में बजटीय और बजटीय-भिन्न संसाधन

(करोड़ रु में)

योजना का नाम	अवसंरचना / आजीविका / दोनों	2018-19 लक्ष्य			
		वास्तविक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			जीबीएस	ईबीआर	जोड़
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय					
पीएमकेएसवाई—एआईबीपी	अवसंरचना	दिसम्बर 2019 तक 48 एआईबीपी प्राथमिकता परियोजनाएं		15000	15000
पीएमकेएसवाई—एचकेकेपी (सीडीडब्ल्यूएम)	अवसंरचना	15 लाख हैक्टे. की सिंचाई क्षमता का उपयोग	2300		2300
ज.सं., न.वि. और गं.सं. मंत्रालय की योजनाएं	दोनों		1461		1461
ज.सं., न.वि. और गं. सं. मंत्रालय का उप—जोड़			3761	15000	18761
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग					
प्रधनमंत्री फसल बीमा योजना	आजीविका	98 मिलियन हैक्टे. कुल फसल क्षेत्र	13000		13000
किसानों को अल्पावधि ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी	आजीविका		15000		15000
प्रधनमंत्री कृषि सिंचाई योजना	अवसंरचना	17.2 लाख हैक्टे. को कवर करते हुए सिंचाई परियोजनाएं	4000		4000
	आजीविका	15 लाख लाभार्थी			
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	आजीविका	15 लाख लाभार्थी	1500		1500
कृषि यांत्रिकीकरण संबंधी उप मिशन	अवसंरचना	62466 केन्द्र कृषि यंत्र और उपस्कर, फार्म यंत्र बैंक, उच्च तकनीकी उत्पाद	1100		1100

		उपस्कर के लिए			
	आजीविका	17.81 लाख लाभार्थी			
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	अवसंरचना	10,45,878 कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, ग्लास हाउस, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, मृदा/बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं आदि	3100		3100
	आजीविका	116.99 लाख लाभार्थी			
एकीकृत बागवानी विकास मिशन	अवसंरचना	3,30,436 केन्द्र	1599		1599
कृ.स. और कि.क. विभाग की अन्य योजनाएं	दोनों		2912		2912
कृ.स. और कि.क. विभाग का उप-जोड़			42211		42211
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय					
मेगा फूड पार्कों के लिए योजना	अवसंरचना	12 मेगा फूड पार्क	390	1170	1560
	आजीविका	2017-18 और 2018-19 में 95000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार			
कोल्ड चेन और मूल्य अभिवर्धन अवसंरचना के लिए योजना	अवसंरचना	101 परियोजनाएं	220	880	1100
	आजीविका	2017-18 और 2018-19 में प्रत्यक्ष : 12000 और अप्रत्यक्ष : 63000 रोजगार			
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की अन्य योजनाएं	दोनों		210	640	850
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का उप-जोड़			820	2690	3510
कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग					
डीएआरई	आजीविका	21960 टन बीजों का उत्पादन 255 लाख अदद वृक्षारोपण सामग्री, 132.5 लाख अदद पशु संसाधन	7800		7800

		1.60 लाख फ्रंटलाइन प्रदर्शन			
		450 फार्म स्तर का प्रशिक्षण			
		20 लाख मानव संसाधन विकास			
		98 एसएयू, 681 मौजूदा केवीके और 59 नए केवीके में अवसंरचना / बुनियादी सुविधाएं			
डीएआरई का उप-जोड़			7800		7800
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय					
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	अवसंरचना	(क) 1.88 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय	15343	15000	30343
	आजीविका	(ख) रोजगार: 16.92 करोड़ व्यक्ति दिवस			
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	अवसंरचना	पाईपयुक्त जलपूर्ति योजनाओं और सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के जरिए अवसंरचना सृजन—84000 निवासी	7000		7000
	आजीविका	आजीविका सृजन—84000			
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का उप-जोड़			22343	15000	37343
ग्रामीण विकास मंत्रालय/ग्रामीण विकास विभाग					
प्रधानमंत्री आवास योजना —ग्रामीण (पीएमएवाई—जी)	दोनों	49 लाख मकान, 46.55 करोड़ मानव दिवस	21000	12000	33000
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	दोनों	57,000 किमी. सड़कें और 28.35 करोड़ मानव दिवस	19000		19000
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा)	अवसंरचना	8552 एडब्ल्यूसी, 2.60 लाख किमी. ग्रामीण सड़कें, 1.83 लाख वर्मी / एनएडीईपी कम्पोस्ट, 675 खाद्य भंडारण गोदाम, 8340 जीपी	55000		55000

		भवन/भारत निर्माण सेवा केन्द्र			
	आजीविका	I. मवेशी शेड/मुर्गी शेल्टर/सुअरबाड़ा-99648 II. भूमि विकास-1.65 लाख 230 करोड़ मानव दिवस			
राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका- एनआरएलएम	एनआरएलएम के तहत आजीविका एमकेएसपी, एसवीईपी, कौशल विकास सहित	9 लाख अदद नए एसएचजी का निर्माण करना है सहायता किए जाने वाली महिला किसानों की संख्या-5 लाख मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना-15 एसवीईपी उद्यमों की संख्या-25000 कुशल बनाए जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या-4 लाख	5750		5750
ग्रामीण विकास विभाग का उप-जोड़			100750	12000	112750
ग्रामीण विकास मंत्रालय/भू-संसाधन विभाग					
1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जलसंभर विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई)	अवसंरचना	1.30 लाख जल संचयन संरचना का सृजन/पुनरुद्धार किया जाना है 1.81 लाख हैक्टे. क्षेत्र को संरक्षित सिंचाई के तहत लाया जाना है	2146		2146
	आजीविका	3. लाभान्वित किसानों की संख्या - 5.01 लाख			
भू-संसाधन विभाग की अन्य योजनाएं			250		250
भूमि विकास विभाग का उप-जोड़			2396		2396
विद्युत मंत्रालय					
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति	अवसंरचना	(i) गांवों का गहन	3800	15000	18800

योजना (डीडीयूजीजेवाई)		विद्युतीकरण—1 लाख (ii) फीडर पृथक्करण नई 11 किलोवाट लाईनों सहित—1 लाख सर्किट किमी. (iii) उप-केन्द्र (नए और अभिवर्धन) प्रारंभ करना—600 अदद			
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)		परिवारों को विद्युत कनेक्शनों की संख्या —175 लाख	2750		2750
विद्युत मंत्रालय का उप-जोड़			6550	15000	21550
सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय					
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	आजीविका	49000 परियोजनाएं 294000 रोजगार	1260		1260
सु.ल. और म.उ. मंत्रालय की अन्य योजनाएं	दोनों		1648		1648
एमएसएमई का उप-जोड़			2908		2908
पंचायती राज मंत्रालय					
2015–2020 की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान	दोनों	स्वास्थ्य और स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण, विद्युतीकरण, सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव आदि के प्रमुख क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य	45069		45069
पंचायती राज मंत्रालय की अन्य योजनाएं	दोनों		348		348
पंचायती राज मंत्रालय का उप-जोड़			45417		45417
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय					
पीएमकेवीवाई 2.0	आजीविका	18 लाख लाभार्थी	1171		1171
कौशल विकास मंत्रालय का उप-जोड़			1171		1171

वित्तीय सेवाएं विभाग					
कृषि ऋण	आजीविका			1100000	1100000
सूक्ष्म सिंचाई निधि				2000	2000
ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)	अवसंरचना			28000	28000
नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता (एनआईडीए)				3500	3500
डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)				2000	2000
मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास (एफआईडीएफ)				1000	1000
कृषि बाजार अवसंरचना				2000	2000
वित्तीय सेवाएं विभाग का उप-जोड़				1138500	1138500
जोड़			236127	1198190	1434317
टिप्पणी : उपर्युक्त आबंटन कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना और आजीविका के लिए विशिष्ट है।					

अनुबंध II

(पैरा 70 में यथा उल्लिखित)

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत स्कीमवार परिव्यय
(स्कीमवार परिव्यय)

मंत्रालय/विभाग/स्कीम का नाम	2017-18	2018-19
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण		
स्वास्थ्य में सीएसएस + सीएस	47,353	52,800
	34,657	39,199
जिसमें		
पीएमएसएसवाई	3,975	3,825
राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	2,000	2,100
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	21,189	24,280
राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	752	875
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा हेतु मानव संसाधन	4,025	4,225
तृतीयक देखभाल कार्यक्रम	725	750
आरएसबीवाई	1,000	2,000
आयुष	1,429	1,626
सीएसएस + सीएस	509	576
जिसमें		
नाम	441	504
स्वास्थ्य अनुसंधान	1,500	1,800
स्कूली शिक्षा	46,356	50,000
सीएसएस + सीएस	38,981	42,391
जिसमें		
एसएसए	23,500	26,129
आरएमएसए	3,830	4,022
मध्याह्न भोजन	10,000	10,500

उच्चतर शिक्षा	33,330	35,010
सीएस + सीएसएस	5,526	8,512
जिसमें		
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा)	1,300	1,400
ब्याज सब्सिडी और गारंटी निधि हेतु अंशदान	1,950	2,150
एचईएफए	250	2,750
ई-शोध सिंधु	240	180
तकनीकी शिक्षा - गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	260	275
महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति	320	340
प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम - छात्रवृत्ति एवं वजीफा	110	125
विश्व स्तर की संस्थाएं	50	250
आभासी कक्षा कक्ष की स्थापना	75	90
मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक और अध्यापन मिशन	120	120
एबी	26,896	25,339
जिसमें		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाएं	7,856	6,326
आईआईएम	1,030	1,036
ग्रामीण विकास		
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम		
सामाजिक न्याय	9,500	9,975
सीएस+सीएसएस	6,908	7,750
	6,836	7,670
जिसमें		
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (अजा)	50	125
मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति (अजा)	3,348	3,000
अजा उप-स्कीमों को विशेष केंद्रीय सहायता	800	1,000
अन्य पिछड़े वर्गों हेतु मैट्रिक-पश्च छात्रवृत्ति	885	1,100
अन्य पिछड़े वर्गों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	142	232

अजा हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप	230	300
दिव्यांग जनों का सशक्तिकरण	855	1,070
सीएस+सीएसएस	559	744
<i>जिसमें</i>		
दिव्यांग जनों को सहायता सामग्री और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता	150	220
दिव्यांग जन कार्यान्वयन हेतु स्कीम अधिनियम	207	300
महिला और बाल विकास विभाग	22,095	24,700
सीएसएस	21,844	24,454
<i>जिसमें</i>		
आंगनवाड़ी सेवाएं	15,245	16,335
किशोरियों हेतु स्कीमें	460	500
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	2,700	2,400
निर्भया निधि की स्कीमें	500	500
बाल संरक्षण स्कीम	648	725
राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	1,500	3,000
महिलाओं के संरक्षण और संरक्षण हेतु मिशन (अंब्रेला)	1,089	1,366
अल्पसंख्यक मामले	4,195	4,700
सीएस+सीएसएस	3,969	4,460
<i>जिसमें</i>		
शिक्षा सशक्तिकरण	2,054	2,453
कौशल विकास और आजीविका	635	602
एमएसपीडी	1,200	1,320
कुल स्कीमें (सीएस+सीएसएस)	1,22,381	1,37,981
ग्रामीण विकास मंत्रालय को छोड़कर ऊपर उल्लिखित कुल मांग/मंत्रालय वार	1,64,020	1,79,457

अनुबंध-III

(जैसाकि पैरा 114 में देखा जा सकता है)

अवसंरचना क्षेत्र पर पूंजी परिव्यय					
				करोड़ रु. में	
		सं.अ. 2017-18		ब.अ. 2018-19	
मंत्रालय/विभाग	स्कीम/सीपीएसई	जीबीएस	आईई बीआर	जीबीएस	आईई बीआर
1. कोयला मंत्रालय (10)	i) कोल इंडिया लि.	0	8500	0	9500
	ii) एनएलसी इंडिया लि.	0	4578	0	4299
	iii) सिंगरेनी कोलियरी कं. लि.	0	1400	0	2000
जोड़		0	14478	0	15799
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (23)	i) पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए संसाधनों का केन्द्रीय पूल	175	0	310	0
	ii) आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार	5	0	40	0
	iii) पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास स्कीम कार्यक्रम घटक	150	0	250	0
जोड़		330	0	600	0
3. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (67)	i) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	0	9287	0	10099
	ii) भारतीय सौर ऊर्जा निगम	50	179	0	217
जोड़		50	9466	0	10317
4. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (72)	i) कच्चा तेल भंडार के लिए भारतीय स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लि.	1121	0	701	0
	ii) फुलपुर धामरा हलदिया पाइप लाइन परियोजना	400	0	1674	0
	iii) राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान कार्यक्रम	10	0	1300	0
	iv) भारत पेट्रोलियम निगम लि.	0	7800	0	7400
	v) चेन्नई पेट्रोलियम निगम लि.	0	865	0	1010
	vi) इंजीनियर्स इंडिया लि.	0	0	0	1356

	vii) गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लि.	0	3309	0	4722
	viii) हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लि.	0	7110	0	8425
	ix) इंडियन आयल निगम लि.	0	18849	0	22862
	x) मैंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लि.	0	1138	0	744
	xi) नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	0	375	0	428
	xii) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि.	0	37218	0	32077
	xiii) आयल इंडिया लि.	0	4263	0	4300
	xiv) तेल प्राकृतिक गैस निगम विदेश लि.	0	6393	0	5886
जोड़		1531	87319	3675	89210
5. विद्युत मंत्रालय (74)	कारगिल के रास्ते श्रीनगर से लेह 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन	500	0	500	0
	ii) दामोदर घाटी निगम लि.	0	1057	0	1606
	iii) राष्ट्रीय पनबिजली निगम लि.	350	3173	482	2258
	iv) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि.	0	28000	0	22300
	v) पूर्वोत्तर विद्युत निगम लि.	1	1212	267	122
	vi) विद्युत वित्त निगम लि.	0	4000	0	0
	vii) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	0	25000	0	25000
	viii) सतलुज जल विद्युत निगम लि.	0	609	0	935
	ix) टिहरी हैडरो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	32	1267	52	1248
जोड़		883	64318	1301	53469
नागर विमानन मंत्रालय (9)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	150	2543	0	4086
जोड़		150	2543	0	4086
दूरसंचार विभाग (14)	रक्षा स्पेक्ट्रम - रक्षा सेवाओं हेतु आप्टीकल फाइबर केबल आधारित	3755	0	4500	0

	नेटवर्क				
	सीपीई में निवेश (भारत ब्रांडबैंड नेटवर्क लिमिटेड)	0	9786	0	16986
जोड़		3755	9786	4500	16986
रक्षा मंत्रालय (विविध) (19)	सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित निर्माण कार्य	2708	0	2785	0
	तट रक्षक संगठन	2200		2700	
जोड़		4908	0	5485	0
रेल मंत्रालय (80)	भारतीय रेलवे पर पूंजी परिव्यय	40000	34900	53060	38500
	भारतीय रेलवे वित्त निगम		45100		54940
जोड़		40000	80000	53060	93440
परमाणु ऊर्जा विभाग (4)	न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	1435	7785	1665	5656
जोड़		1435	7785	1665	5656
आवास और शहरी मामले मंत्रालय (56)	एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाएं	17810	1477	14924	1897
	आवास और शहरी विकास निगम	0	13716	0	13040
	पीएमएवाई (शहरी)	6043	0	6500	25000
जोड़		23853	15193	21424	39937
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (81)	एनएचएआई में निवेश	23892	59279	29663	62000
	सड़क और पुल	26967	0	29762	0
जोड़		50858	59279	59425	62000
पोत परिवहन मंत्रालय (87)	सागरमाला	125	0	250	0
	वोचिदंबरनर पत्तन न्यास		163		342
	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास		1569		2065
	मुंबई पत्तन न्यास		410		432
	दीन दयाल पत्तन न्यास, कांडला		347		458

	कामराजार पत्तन न्यास		325		250
	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड		351		495
जोड़		125	3165	250	4042
इस्पात मंत्रालय (93)	फैरो स्क्रेप निगम लिमिटेड	0	28	0	23
	केआईओसीएल	0	2024	0	1782
	मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड	0	272	0	279
	मेकॉन लिमिटेड	0	5	0	5
	एमएसटीसी लिमिटेड	0	33	0	49
	एनएमडीसी लिमिटेड	0	3324	0	3778
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	0	1570	0	1400
	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	0	4200	0	4000
जोड़		0	11428	0	11294
उच्चतर शिक्षा विभाग (58)	एचईएफए	250	0	2750	28000
जोड़		250	0	2750	28000
इलैक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	डिजिटल इंडिया	1426		3073	5700
जोड़		1426		3073	5700
कुल जोड़		129554	364759	157208	439935
		494313		597143	

अनुबंध IV

(पैरा 131 में यथासंदर्भित के अनुसार)

केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में ई-आफिस और ई-गवर्नेंस पहलें

1. फीस, अर्थदंड अभी अन्य गैर-कर देयताएं सरकारी खाते में जमा करने के लिए एक ही स्थान पर सेवाएं प्रदान करने के लिए एक गैर-कर प्राप्ति पोर्टल।
2. सभी विधानमंडलों को डिजिटाइज करने तथा कागजरहित बनाने के लिए परियोजना 'ई-विधान'।
3. खरीदारी करने के संबंध में सभी सूचनाएं एक ही स्थान पर प्राप्त करने के लिए एक केन्द्रीय सार्वजनिक लोक प्रापण पोर्टल लगभग 3.5 लाख ठेकेदार और विक्रेता (वेंडर) इस प्लेटफार्म के साथ पंजीकृत हैं। नवम्बर, 2017 में ही इस पोर्टल के माध्यम से लगभग दो लाख चालीस हजार करोड़ रुपये मूल्य की एक लाख निविदाओं के लिए इलेक्ट्रानिक बोलियां आमंत्रित की गईं।
4. उचित मूल्य पर उचित गुणवत्ता और उचित मात्रा में पारदर्शी और कार्यकुशल रीति से खरीदारी को सुकर बनाने के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम)। 'जेम' प्लेटफार्म (जेम 3.0) का तृतीय संस्करण 26 जनवरी, 2018 का आरंभ किया जाएगा। इस प्लेटफार्म में अठत्तर हजार खरीदार, छप्पन हजार विक्रेता, तीन लाख पिचहत्तर हजार उत्पाद और 12 सेवाएं हैं। लगभग दो लाख लेन-देन में तीन हजार करोड़ रुपये मूल्य के लेन-देन को सुकर बनाने के अतिरिक्त यह आधार मूल्य पर 25% से अधिक बचत प्राप्त कर सकता है।
5. सभी जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में सर्वसुलभ कंप्यूटरीकरण क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रयोग तथा ई-फाइलिंग और ई-भुगतान जैसी ई-सेवाओं की उपलब्धता के लिए ई-न्यायालय।
6. देश के लगभग सोलह हजार कंप्यूटरीकृत न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों से न्यायिक कार्यवाहियों और निर्णयों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आनलाइन प्लेटफार्म उपलब्ध करवाने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रीडवादी केन्द्रिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ई-कोर्ट सर्विस एप्प किया गया है।
7. महत्वपूर्ण सामान्य आवेदनों का सेट उपलब्ध करवाने के लिए ई-पंचायत प्लेटफार्म ताकि पंचायत के कार्यकरण से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे आयोजना, बजट की तैयारी, कार्यान्वयन, लेखाकरण, निगरानी और प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि जैसी सेवाओं की सामाजिक लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में कारवाई की जा सके।

बजट भाषण का अनुबंध-V

प्रत्यक्ष करों में अन्य परिवर्तन

1. यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि निर्धारण वर्ष 2018-19 और बाद के निर्धारण वर्षों के लिए दर्ज की गई विवरणियों की जांच के समय आयकर अधिनियम (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) की धारा 143 (1) (vi) के तहत कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।
2. उन कंपनियों के संबंध में, जिनमें शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 के तहत कोई आवेदन दाखिल किया गया है, यह प्रावधान प्रस्तावित है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ अवशोषित न किए गए मूल्यहास और अग्रेनीत हानि की सकल राशि को दर्ज लाभ में से घटाने की अनुमति होगी।
3. प्रस्ताव है कि अगले लाभ से हानि-पूर्ति के प्रयोजन के लिए शेरधारिता पर प्रतिबंध के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 79 का अनुबंध आईबीसी, 2016 के तहत अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार शेरधारिता के परिवर्तन के मामले में लागू नहीं होगा, यहां सुने जाने का अवसर प्रधान आयुक्त या आयुक्त को दिया गया है।
4. यह प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव है कि शोधन अक्षमता समाधान से संबंधित पेशेवर उस कंपनी के मामले में आय की विवरणी का सत्यापन करेगा जिसमें शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत कोई आवेदन दाखिल किया गया है।
5. यह प्रावधान प्रस्तावित है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर के उपबंध उन विदेशी कंपनियों के संबंध में लागू नहीं होंगे जिनकी आय उक्त अधिनियम की धारा 44ख, 44खख, 44खखक और 44खखख में निर्दिष्ट व्यवसायों से ही है, बशर्ते कि यह लाभ इन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों पर कर के लिए पेश की गई हो।
6. यह भी प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट से 40% तक की धन-निकासी के लिए छूट का लाभ न केवल कर्मचारियों को बल्कि सभी ग्राहकों को भी प्रदान किया जाए।
7. यह प्रावधान किए जाने का भी प्रस्ताव है कि ऐसे मामले में जहां अनेक वर्षों के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का भुगतान एक वर्ष में किया गया है, वहां जितने वर्षों के लिए स्वास्थ्य बीमा का लाभ उपलब्ध है उनके समानुपात में कटौती प्रदान की जाएगी।
8. स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए, किसी 'स्टार्ट-अप' के लिए 'पात्र कारोबार' की परिभाषा को औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा अधिसूचित की गई संशोधित परिभाषा के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव है। आगे यह भी प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 80-झकग के तहत लाभ उठाने के लिए किसी स्टार्ट-अप के लिए निगमन की तारीख को 31 मार्च 2019 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया जाए और लाभ उठाने के लिए टर्नओवर की शर्त को भी युक्तिसंगत बनाया जाए।
9. अधिनियम की धारा 56(2)(भ) के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव है जिसमें किसी पूर्णतः स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनी द्वारा इसके स्वामित्वाधीन होल्डिंग कंपनी को और किसी भारतीय होल्डिंग कंपनी द्वारा इसकी सहायक कंपनी को किसी परिसंपत्ति के अंतरण को कर से छूट प्रदान की गई है।
10. यह भी प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि कृषिगत वस्तु व्युत्पन्नों का किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करना सट्टा लेन देन नहीं माना जाएगा भले ही उन व्युत्पन्न के लेन देनों के संबंध में कोई वस्तु लेन देन कर (सीटीटी) न दिया गया हो।
11. लेन देनों की महत्वपूर्ण प्रकृति पर विचार करते हुए, यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन से प्राप्त की गई तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस से किसी अनिवासी को अर्जित हो रही आय कर से मुक्त होगी।

12. यह भी प्रावधान करना प्रस्तावित है कि कच्चे तेल के बचे हुए भंडार की बिक्री की छूट किसी महत्वपूर्ण तेल भंडार में भागीदार किसी विदेशी कंपनी से संबंधित संविदा या करार के समापन के संबंध में भी लागू होगी।
13. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि सरकार अधिनियम की धारा 10(46) के अंतर्गत किसी प्राधिकरण, बोर्ड, न्यास या आयोग को अधिसूचित करने के अलावा ऐसे व्यक्तियों के किसी वर्ग को भी अधिसूचित कर सकती है।
14. उसी प्रकार के कर शासन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जो केवल एक्सचेंज ट्रेड वाले निधियों जो केवल घरेलू कम्पनियों के सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश करती है, में निवेश की जाने वाली निधियों की निधि के लिए इक्विटी उन्मोखी निधियों के लिए उपलब्ध है।
15. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 115बीबीई के अंतर्गत कर निर्धारण करने वाले अधिकारी द्वारा निर्धारित अप्रकट आय के संबंध में किसी व्यय, भत्ता या किसी प्रकार की हानि की अनुमति नहीं होगी।
16. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि प्रत्येक संस्था, जो कोई व्यक्तिगत न हो, जो किसी वित्त वर्ष में कुल 2.50 लाख रुपए अथवा इससे अधिक की राशि की लेनदेन करती हो, उसे पर्मानेंट अकाउन्ट नम्बर(पैन) के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा। यह भी व्यवस्था की जाती है कि निदेशकों, भागीदरों, प्रधान अधिकारियों, कर्मचारियों या ऐसी संस्थाओं की ओर से कार्य करने वाले किसी सक्षम व्यक्ति भी पैन के लिए आवेदन करेगा।
17. अग्रिम व्यवस्था के लिए किसी नए सीमाशुल्क प्राधिकरण का गठन करने के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन को ध्यान में रखते हुए, यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत गठित अग्रिम व्यवस्था के लिए प्राधिकरण, अग्रिम व्यवस्था के लिए सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। यह भी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि जब प्राधिकरण आयकर अधिनियम से संबंधित किसी आवेदन पर सुनवाई कर रहा हो तो राजस्व सदस्य आयकर से होगा।
18. अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष लागू अधिनियम की धारा 271ज के अंतर्गत आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा आदेश पारित करवाने का प्रस्ताव किया जाता है।
19. अधिनियम की धारा 271चक के अंतर्गत आर्थिक दण्ड 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए और 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का प्रस्ताव किया जाता है।
20. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि कोई कर देय है अथवा नहीं, विवरणी दायर नहीं करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध अभियोग चलाया जाएगा।
21. यह अधिदेश देने का प्रस्ताव किया जाता है कि अध्याय VI-ग के अंतर्गत किसी कटौती का लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारित तिथि के भीतर विवरणी दायर करना होगा।
22. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि यदि व्यापार स्टॉक को पूँजीगत आस्ति के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तन की तारीख को व्यवसाय से आय का परिकलन करने के लिए उसके उचित बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा।
23. यह व्यवस्था करके कि छूट केवल अचल परिसंपत्ति की बिक्री से प्राप्त दीर्घकालिक पूँजी लाभों के संबंध में ही मिलेगी और बॉण्ड में निवेश मौजूदा 3 वर्ष से बढ़कर न्यूनतम 5 वर्षों के लिए होगा, पूँजीगत लाभ बॉण्डों में निवेश से संबंधित मौजूदा व्यवस्था को उदार बनाने का प्रस्ताव किया जाता है।
24. सरकार द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय लिखत के अनुसार, संशोधित आश्रित एजेंट स्थायी स्थापना के संबंध में व्यवसाय के अवसर को अनुरूप बनाने के लिए अधिनियम की धारा 9 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

25. अधिनियम की धारा 9 में यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि किसी अप्रवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति भारत के साथ व्यावसायिक संबंध का निर्माण करेगा। “महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति” उपवाक्य को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव किया जाता है।
26. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि व्यावसायिक संविदा समाप्त होने या उसमें संशोधन करने के संबंध में प्राप्त क्षतिपूर्ति और रोजगार संविदा कर कर योग्य होंगे।
27. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि भारी माल वाहनों (12 टन से अधिक भारी) के संबंध में अधिनियम की धारा 44कड. के अंतर्गत प्रकल्पित आय की गणना 1000 रुपए प्रति टन प्रति माह की दर से की जाएगी।
28. आय संगणन एवं प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) को सांविधिक सहयोग एवं निश्चितता प्रदान करने के लिए, व्यावसाय से होने वाली आमदनी की गणना करने से संबंधित अधिनियम के अध्याय IV-घ और अधिनियम के अध्याय XIV के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।
29. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि नव प्रवर्तित 7.75% जीओआई (कर योग्य) बॉण्ड, 2018 से ब्याज के संबंध में लागू दर पर टीडीएस बनाया जाएगा।
30. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि किसी समामेलित कम्पनी के मामले में लाभांश का निर्धारण करने के उद्देश्य से संग्रहित लाभों में समामेलन की तारीख को समामेलित कम्पनी की संग्रहित लाभ भी शामिल होंगे।
31. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम की धारा 2(22)(ड.) के अंतर्गत माना गया लाभांश कुल जोड़ किए बिना 30% की दर से लाभांश वितरण कर के अध्यक्षीन होगा।
32. यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया जाता है कि विनिर्माण के कार्य में लगी हुई नई घरेलू कम्पनियों के लिए 25% की रियायती दर अधिनियम के अध्याय XI के अंतर्गत प्रदत्त विशिष्ट आय के संबंध में विशेष दर के अध्यक्षीन होगा।
33. समय-सीमा और “करार” की परिभाषा निर्धारित करके कन्ट्री-बाई-कन्ट्री रिपोर्ट दायर करने से संबंधित व्यवस्थाओं को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया जाता है।
34. वायदा पण्यों में विकल्प के रूप में पण्य लेन-देन कर (सीटीटी) को युक्तिसंगत बनाने के लिए वित्त अधिनियम, 2013 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।
35. दण्ड एवं अभियोजन के लिए स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पदनामों को युक्तिसंगत बनाने के लिए काला धन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्तियां) और करारोपण अधिनियम, 2015 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

बजट भाषण के भाग ख का अनुबंध-VI

अप्रत्यक्ष कर

1. सीमा शुल्क दरों में परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव:

		अध्याय/शीर्षक उप-शीर्षक प्रशुल्क मद	वस्तु	शुल्क की दर	
				से	तक
I.	घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करना, 'मेक इन इंडिया'				
	क.	लागत घटाने के लिए निविष्टि और कच्ची सामग्री पर सीमा शुल्क में कटौती			
			खाद्य प्रसंस्करण		
	1	0801 31 00	छिलका सहित काजू नट (कच्चा काजू)	5%	2.5%
			पूंजीगत वस्तु और इलेक्ट्रानिकी		
	2	8483 40 00, 8466 93 90, 8537 10 00	शीर्ष 8456 से 8463 के अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की सीएनसी मशीनों टूल्स के विनिर्माण हेतु बॉल स्क्रूज, लाइनियर मोशन गाइड्स, सीएनसी सिस्टम	7.5%	2.5%
	3	70	सोलर सेल/ पैनल /मोड्यूल के विनिर्माण के लिए सोलर टेम्पर्ड ग्लास या सोलर टेम्पर्ड (रिफ्लेक्शन रोधी कोटेड) ग्लास	5%	शून्य
	ख.	कतिपय क्षेत्रों में शुल्क प्रतिलोम की समस्या का समाधान करने के लिए सीमा शुल्क में परिवर्तन			
			चिकित्सा उपकरण		
	4	कोई अध्याय	कोचलर इम्प्लैंट के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, भाग या सहायक उपकरण	2.5%	शून्य
	ग.	घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण देने के लिए सीमा शुल्क में परिवर्तन			
			खाद्य प्रसंस्करण		
	5	2009 11 00 2009 12 00 2009 19 00	संतरा रस	30%	35%
	6	2009 21 00 से 2009 90 00	अन्य फल का रस और वैजिटेबल जूस	30%	50%
	7	2009 81 00, 2009 90 00	क्रेनबेरी जूस	10%	50%
	8	2106 90	विविध खाद्य की तैयारियां (सोया प्रोटीन को छोड़कर)	30%	50%
			इत्र और प्रसाधन सामान		
	9	3303	इत्र और शौचालय पानी	10%	20%
	10	3304	सौंदर्य अथवा मेकअप का सामान अथवा त्वचा की देखभाल के सामान (दवाइयों के अतिरिक्त) जिसमें सनस्क्रीन अथवा संतन सामान; मेनीक्योर अथवा पेडीक्योर सामान तैयार करना	10%	20%

	11	3305	बालों में प्रयोग हेतु सामग्री	10%	20%
	12	3306	मुंह और दांतों की स्वच्छता की सफाई, डेंचर, फिक्सेटिव पेस्ट और पाउडर सहित, संबंधित सामान तैयार करना; व्यक्तिगत खुदरा पैकेजों में दांतों के बीच सफाई के लिए प्रयुक्त यार्न (डेंटल फ्लास)	10%	20%
	13	3307	सेविंग करने से पूर्व, सेविंग करते समय या सेविंग के बाद प्रयुक्त सामान, व्यक्तिगत डियोडोडेंट, स्नान से संबंधित सामान तैयार करना, डैपिलेटरीज और अन्य सुगंधित सामान, कास्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन या शौचालय संबंधी सामान जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या शामिल न हों, कक्ष महकाने वाले सामान तैयार करना, चाहे वे सुगंधित या डिसइन्फेक्टेंट प्रापर्टी से युक्त हों अथवा नहीं।	10%	20%
			ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल पार्ट		
	14	8407, 8408, 8409, 8483 10 91, 8483 10 92, 8511, 8708, 8714 10	मोटर वाहन, मोटर कार, मोटर साइकिल के विनिर्दिष्ट पार्ट/कलपुर्जे	7.5% / 10%	15%
	15	8702, 8703, 8704, 8711	मोटर वाहन, मोटर कार, मोटर साइकिल का सीकेडी आयात	10%	15%
	16	8702, 8704	मोटर वाहनों का सीबीयू आयात	20%	25%
	17	4011 20 10	ट्रक और बस रेडियल टायर	10%	15%
			वरत्र		
	18	5007	सिल्क फैब्रिक्स	10%	20%
			फुटवियर		
	19	6401, 6402, 6403, 6404, 6405	फुटवियर	10%	20%
	20	6406	फुटवियर के पार्ट्स	10%	15%
			डायमण्ड, कीमती रत्न और आभूषण		
	21	71	तराशे हुए और पालिश युक्त रंगीन रत्न	2.5%	5%
	22	71	हीरे प्रयोगशाला में निर्मित हीरे - अर्थसंशोधित आधे कटे हुए या टूटे हुए सहित; औद्योगिक -भिन्न हीरे प्रयोगशाला में निर्मित हीरे (बिना तराशे हुए हीरों को छोड़कर) सहित, तराशे हुए और पालिशयुक्त हीरे	2.5%	5%

	23	7117	नकली आभूषण	15%	20%
			इलेक्ट्रॉनिक्स/हार्डवेयर		
	24	8517 12	सेल्युलर मोबाइल फोन	15%	20%
	25	3919 90 90, 3920 99 99, 3926 90 91, 3926 90 99, 4016 99 90, 7318 15 00, 7326 90 99, 8504, 8506, 8507, 8517 70 90, 8518, 8538 90 00, 8544 19, 854442, 854449	सेल्युलर मोबाइल फोन के पार्ट और कलपुर्जे	7.5% 10%	15%
	26	8504 90 90/ 3926 90 99	सेल्युलर मोबाइल फोन के चार्जर/एडाप्टर और चार्जर/एडाप्टर के मोल्डिड प्लास्टिक का पीसीबीए	शून्य	10%
	27	कोई चैप्टर	निम्न के विनिर्माण से संबंधित इनपुट या पार्ट्स: क) पीसीबीए, या ख) सेल्युलर मोबाइल फोन के चार्जर/एडाप्टर के मोल्डिड प्लास्टिक	लागू दर	शून्य
	28	8517 62 90	स्मार्ट घड़िया/ पहनने योग्य चीजें	10%	20%
	29	8529 10 99 8529 90 90	एलसीडी/एलईडी/ऑएलईडी पैनल तथा एलसीडी/एलईडी/ऑएलईडी टीवी के अन्य कलपुर्जे	7.5%/ 10%	15%
	30	8529/4016	एलसीडी/एलईडी टीवी पैनलों के विनिर्माण हेतु 12 विनिर्दिष्ट कलपुर्जे	शून्य	10%
	31	70	दूरसंचार कोटि के ऑप्टिकल फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर केबल के विनिर्माण में उपयोग हेतु सिलिका के प्रिफार्म	शून्य	5%
			फर्नीचर		
	32	9401	सीटें और सीटों के अन्य भाग (एयरक्राफ्ट सीटों और उनके पार्ट्स को छोड़कर)	10%	20%
	33	9403	दूसरे फर्नीचर और पार्ट्स	10%	20%
	34	9404	गद्दे और तकिए: बेडिंग और इसी प्रकार की फर्निशिंग के सामान	10%	20%

	35	9405	लैम्प और लाइटिंग फिटिंग, इल्युमिनेटेड साइन, इल्युमिनेटेड नेमप्लेट और इसी प्रकार के सामान (सौर लालटेन और सौर बल्ब छोड़कर)	10%	20%
			घड़ियां एवं दीवाल घड़ियां		
	36	9101, 9102	हाथ की घड़ियां, पाकेटवाच, और अन्य घड़ियां, स्टाप घड़ियों सहित	10%	20%
	37	9103	क्लॉक विथ वाच मूवमेंट	10%	20%
	38	9105	अन्य घड़ियां, अलार्म घड़ियों सहित	10%	20%
			खिलौने एवं खेल		
	39	9503	तिपहिया साइकिल, स्कूटर, पैडल वाली कारें और इसी प्रकार के पहिए वाले खिलौने; गुड़ियों के पिंजड़े; गुड़िया; अन्य खिलौने; सभी प्रकार की पहेलियां	10%	20%
	40	9504	वीडियो गेम कंसोल और मशीनें, फनफेयर, टेबल या पार्लर गेम और आटोमेटिक बालिंग एलई उपकरण	10%	20%
	41	9505	त्योहार, समारोह या मनोरंजन संबंधी दूसरे सामान	10%	20%
	42	9506 [9506 91 के सिवाय]	खेलकूद और आउटडोर खेलों, स्वीमिंग पूल और पैडलिंग पूल (समान्य शारीक व्यायाम, कसस्त या एथलेटिक्स से संबंधित सामान और उपकरणों को छोड़कर)	10%	20%
	43	9507	फिशिंग राड्स, फिशिंग हुक और अन्य लाइन फिशिंग टैकल; फिश लैंडिंग नेट, तितलियों के नेट और इसी प्रकार के नेट; डिकाय बर्ड्स और इसी प्रकार की शिकार या शूटिंग से संबंधित सामान	10%	20%
	44	9508	चक्कर वाले झूले, झूले, शूटिंग गैलरी तथा अन्य फेयर ग्राउंड मनोरंजन; ट्रैविलिंग मैनेजरीच और ट्रैविलिंग थियेटर	10%	20%
			विविध मर्चे		
	45	3406	मोमबत्तियां, टैपर और इसी प्रकार की वस्तुएं	10%	25%
	46	4823 90 90	पतंगे	10%	20%
	47	9004 10	सनग्लासेस	10%	20%
	48	9611	डेट, सीलिंग या नम्बर वाली मोहरें और इसी प्रकार का सामान	10%	20%
	49	9613	सिगरेट लाइटर और अन्य लाइटर, चाहे वे यांत्रिक या इलेक्ट्रिकल हों या नहीं तथा फ्लेंट और विक्स को छोड़कर उनके पार्ट्स	10%	20%
	50	9616	सुगंधित स्प्रे और इसी प्रकार के शौचलय से संबंधित स्प्रे, और उनके माउंट्स और हेड; पाउडर-पप और	10%	20%

			कास्मेटिक या टायलेट प्रिपरेशन की अनुप्रयोज्यता हेतु पैड		
II	यौक्तिकीकरण संबंधी उपाय				
			वनस्पति मूल के खाद्य तेल		
	1	1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1515	कच्चे खाद्य वनस्पति तेल यथा मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, बिनौले का तेल, सूर्य मुखी का तेल, सफोला तेल, नारियल तेल, ताड़ का तेल, अलसी का तेल, मक्की का तेल, अरंड का तेल, तिल का तेल, अन्य फिक्सड वसा और तेल	12.5%	30%
	2	1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1515, 1516 20, 1517 10 21, 1517 90 10, 1518 00 11, 1518 00 21, 1518 00 31	रिफाइण्ड खाद्य वनस्पति तेल यथा मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, बिनौले का तेल, सूर्य मुखी का तेल, सफोला तेल, नारियल तेल, ताड़ का तेल, अलसी का तेल, मक्की का तेल, अरंड का तेल, तिल का तेल, अन्य फिक्सड वसा और तेल, वनस्पति मूल का खाद्य मार्गेरिन, साल वसा, शीर्षक 1518 के विनिर्दिष्ट सामान	20%	35%
			रिफ्रेक्ट्री आइटम		
	3	6815 91 00	मैग्नेसाइट, डोलोमाइट या क्रोमाइट युक्त पत्थर के अन्य सामान	10%	7.5%
	4	6901	ईटें, ब्लाक, टाइल्स और सिलिसियस फाजिल मील्स के अन्य सिरामिक निर्मित सामान या इसी प्रकार के सिलिसियस मिट्टी से निर्मित सामान	10%	7.5%
	5	6902	रिफ्रेक्ट्री ईटें, ब्लाक्स, टाइल्स और इसी प्रकार के रिफ्रेक्ट्री सिरामिक निर्माण संबंधी वस्तुएं, सिलिसियस फाजिल मील्स के अन्य सिरामिक निर्मित वस्तुएं या इसी प्रकार के सिलिसियस मिट्टी से निर्मित सामान को छोड़कर	5%	7.5%
	6	6903	अन्य रिफ्रेक्ट्री सिरामिक वस्तुएं	5%	7.5%
III	समाज कल्याण अधिभार				
	1	कोई चैप्टर	शिक्षा, आवासन और सामाजिक सुरक्षा के वित्तपोषण हेतु आयातित वस्तुओं (नीचे क्रम संख्या 3 से 6 में उल्लिखित वस्तुओं को छोड़कर) पर समाज कल्याण अधिभार लगाना	--	सीमा शुल्क के कुल शुल्क का 10%
	2	कोई चैप्टर	आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकर समाप्त करना	सीमा शुल्क के कुल शुल्क का 3% [2% + 1%]	शून्य

	3	2710	आम तौर पर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल ऑयल के नाम से प्रसिद्ध मोटर स्प्रिट पर समाज कल्याण अधिभार से छूट	--	सीमा शुल्क के कुल शुल्क का 3%
	4	7106	चांदी (सोने या प्लेटिनम के साथ सिल्वर प्लेटेड सहित), अपरिष्कृत या अर्ध विनिर्मित रूप या पाउडर के रूप में	--	सीमा शुल्क के कुल शुल्क का 3%
	5	7108	सोना (प्लेटिनम के साथ सोने की प्लेटेड सहित), अपरिष्कृत या अर्ध विनिर्मित रूप या पाउडर के रूप में	--	सीमा शुल्क के कुल शुल्क का 3%
	6	कोई चैप्टर	आयातित वस्तुओं पर शिक्षा उपकरण और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा उपकरण से अब छूट प्राप्त विनिर्दिष्ट वस्तुएं	--	शून्य
IV		सड़क एवं अवसंरचना उपकरण			
	1	2710	आम तौर पर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल ऑयल के नाम से प्रसिद्ध मोटर स्प्रिट पर सड़क एवं अवसंरचना उपकरण लगाना	--	8 रुपये प्रति ली.
	2	2710	आम तौर पर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल ऑयल के नाम से प्रसिद्ध घरेलू तौर पर उत्पादित प्रस्तावित सड़क और अवसंरचना उपकरण के बदले में सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के तहत लगाए जाने योग्य अतिरिक्त सीमा शुल्क प्रशुल्क से छूट	--	शून्य
	3	2710	आम तौर पर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल ऑयल के नाम से प्रसिद्ध आयातित मोटर स्प्रिट पर सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (सड़क उपकरण) का उन्मूलन	6 रुपये प्रति ली.	शून्य
	4		बुनियादी उत्पाद शुल्क ड्यूटी के बदले में सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3(1) के तहत सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क		
		2710	(i) आम तौर पर पेट्रोल के नाम से प्रसिद्ध मोटर स्प्रिट	6.48 रुपये प्रति ली.	4.48 रुपये प्रति ली.
		2710	(ii) हाईस्पीड डीजल आयल	8.33 रुपये प्रति ली.	6.33 रुपये प्रति ली.

2. सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में शुल्कों की प्रभावी दरों में कोई बदलाव नहीं, के साथ संशोधन

क्र.सं.	संशोधन
क	सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में संशोधन
1	एकीकृत कर एवं माल और सेवा कर क्षतिपूर्ति उपकर के प्रयोजनार्थ धारा 3 में संशोधन ताकि भांडागार में रखे गए माल, जिन्हें घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए स्वीकृति से पूर्व दूसरे व्यक्ति को बेचा जाता है, के मूल्यांकन का प्रावधान करने के लिए उपधारा 8क और 10क अंतःस्थापित की जा सकें।
ख	आयात शुल्क- सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची
1	विनिर्दिष्ट चिकित्सा उपकरणों के लिए सीमा शुल्क की प्रशुल्क दर 7.5% से बढ़ाकर 10% की जा रही है। तथापि, ऐसे चिकित्सा उपकरणों पर आयात शुल्क की प्रभावी दर अपरिवर्तित रहेगी।
2	लिथियम - ऑयन बैटरियों के लिए सीमा शुल्क ड्यूटी की प्रशुल्क दर 10% से बढ़ाकर 20% की जा रही है। तथापि, लिथियम - ऑयन बैटरियों पर आयात शुल्क की प्रभावी दर (सेल्युलर मोबाइल फोन के लिए लिथियम - ऑयन बैटरियों को छोड़कर) 10% पर अपरिवर्तित रहेगी।
ग	निर्यात शुल्क- सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची
1	सभी दूसरे माल जो अनुसूची के स्तंभ (2) के तहत कवर नहीं किए जाते हैं, के संबंध में शुल्क की शून्य दर विनिर्दिष्ट करने के लिए एक नई टिप्पणी अंतःस्थापित करना।
2	भट्टियों के लिए प्रयुक्त एक प्रकार के इलेक्ट्रॉड्स पर निर्यात शुल्क की 20% प्रशुल्क दर शुरू करना। तथापि, ऐसे इलेक्ट्रॉड्स पर निर्यात शुल्क की प्रभावी दर शून्य रहेगी।

3. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में महत्वपूर्ण संशोधन

क्र.सं.	संशोधन
क.	व्यापार को सुगम बनाने के लिए
1	स्व-निर्धारण के सत्यापित करने के लिए निर्धारण के कार्य क्षेत्र को परिभाषित करना और "जोखिम आधारित चयन" की शुरुआत करना (सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(2), 17)
2	विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों द्वारा अधिरोपित विनियामक नियंत्रणों के संबंध में आयातकों, निर्यातकों और अधिकारियों के लिए संदर्भ के एकल बिन्दु की स्थापना करना [सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11]
3	पूर्ण या आंशिक शुल्क छूटों के साथ मरम्मत, विनिर्माण और आगे संसाधन के उद्देश्य से आयात और निर्यात को सुगम बनाना [सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25क और धारा 25ख]
4	अपीलीय तंत्र के साथ एक नया सीमा शुल्क एडवांस रूलिंग प्राधिकरण की नियुक्ति करना [सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28ड से 28ड]
5	सीमा शुल्क ऑटोमेटिड प्रणाली द्वारा स्वीकृत के लिए विधिक आधार का प्रावधान करना [सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 45, 47, 51, 60, 68 और 69]
6	सीजीएसटी एक्ट में उपबंधों की तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर प्रारंभ करना [सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 51क]

7	लेखा परीक्षा संचालन हेतु नया अध्याय शुरू करना [सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 99क]
8	व्यापार सुगमता के भाग के रूप में सरल और विभिन्न प्रक्रियाएं उपलब्ध कराने हेतु नई धारा का अंतःस्थापन [सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 143कक]
9	दूसरे देशों के सक्षम प्राधिकरणों के साथ सूचना के आदान-प्रदान हेतु नई धारा प्रारंभ करना [सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 151ख]
ख.	मुकदमेबाजी में कमी लाना
10	अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर नोटिस से पहले परामर्श, अनुपूरक कारण बताओं नोटिस जारी करने किन्तु मौजूदा सीमित अवधि के भीतर, समयबद्ध न्याय निर्णयन और मामलों को बंद माने जाने हेतु प्रावधान करना [सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 28]
11	सभी देयों की स्वेच्छा से अदायगी के मामलों में उन्मोचन जुर्माना लगाए बिना मामलों को बंद करने के लिए प्रावधान करना [सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 125]
ग.	अनुपालन में सुधार लाना
12	सीमा शुल्क अधिनियम के कार्य क्षेत्र का भारत से बाहर उक्त अधिनियम के तहत किए गए किसी अपराध या उल्लंघन के लिए विस्तार करना [सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 1]
13	अधिसूचित किए जाने वाली कतिपय वस्तुओं के लिए नियंत्रित डिलिवरी हेतु उपबंध प्रारंभ करना [सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 109क]

4. उत्पाद शुल्क दरों में परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव :

		वस्तु	शुल्क की दर	
			से	से
I	आम तौर पर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल ऑयल के नाम से प्रसिद्ध मोटर स्प्रीट			
	1.	आम तौर पर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल ऑयल के नाम से प्रसिद्ध मोटर स्प्रीट पर सड़क एवं अवसंरचना उपकर लगाना	--	8 रुपये प्रति लीटर
	2.	आम तौर पर पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल ऑयल के नाम से प्रसिद्ध अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क उपकर) का उन्मूलन	6 रुपये प्रति लीटर	शून्य
	3.	निम्न पर बुनियादी उत्पाद शुल्क ड्यूटी:		
		(i) ब्रांडरहित पेट्रोल	6.48 रुपये प्रति लीटर	4.48 रुपये प्रति लीटर
		(ii) ब्रांड वाला पेट्रोल	7.66 रुपये प्रति लीटर	5.66 रुपये प्रति लीटर
		(iii) ब्रांडरहित डीजल	8.33 रुपये प्रति लीटर	6.33 रुपये प्रति लीटर
		(iv) ब्रांड वाला डीजल	10.69 रुपये प्रति लीटर	8.69 रुपये प्रति लीटर
	4.	निम्न पर बुनियादी उपकर	--	शून्य

		(i) 5% एथनॉल युक्त पेट्रोल (ii) 10% एथनॉल युक्त पेट्रोल और (iii) बायोडीजल-, बाल्यूम द्वारा 20% तक, इस शर्त के अधीन कि एथनॉल युक्त या बायोडीजल पर समुचित उत्पाद शुल्क अदा कर दिया गया है या ऐसे ब्लैंड के समय प्रयुक्त एथनॉल युक्त या बायोडीजल पर समुचित जीएसटी का भुगतान कर दिया गया है।		
	5.	पूर्वोक्त में स्थिति 4 विनिर्दिष्ट रिफाइनरियों में विनिर्मित और निकाले गए पेट्रोल और डीजल पर अवसंरचना उपकरण	--	4 रुपये प्रति लीटर

टिप्पणी: “बुनियादी उत्पाद शुल्क ड्यूटी” केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क ड्यूटी से है।

5. विविध

क्र.सं.	संशोधन
क.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड को केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में पुनर्नामित करना
	निम्नलिखित अधिनियमों में परिणामी संशोधनों के साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का नाम केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के रूप में पुनर्नामित करना: - i. केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 (1963 का 54) ii. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) iii. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2018

F. No. 2(10)-B(D)/2018.—The following is published for general information:—

Budget 2018-2019

Speech of

Arun Jaitley

Minister of Finance

February 1, 2018

Section I

Governance, Economy and Development

Madam Speaker,

I rise to present the Budget for 2018-19.

2. Madam, four years ago, we pledged to the people of India to give this nation an honest, clean and transparent Government. We promised a leadership capable of taking difficult decisions and restoring strong performance of Indian economy. We promised to reduce poverty, expedite infrastructure creation and build a strong, confident and a New India. When our Government took over, India was considered a part of fragile 5; a nation suffering from policy paralysis and corruption. We have decisively reversed this. The Government, led by Prime Minister, Shri Narendra Modi, has successfully implemented a series of fundamental structural reforms. With the result, India stands out among the fastest growing economies of the world.

3. The journey of economic reforms during the past few years has been challenging but rewarding. As a result of the reforms undertaken by the Government, foreign direct investment has gone up. Measures taken by the Government have made it much easier to do business in India. Natural resources are now allocated in a transparent and honest manner. There is a premium on honesty. There was a time when corruption was common-place. Today, our people, especially our youths, are curious to lead their lives honestly. The indirect tax system, with introduction of Goods and Services Tax, has been made simpler. Benefits to the poor have been targeted more effectively with use of digital technology. The demonetization of high value currency has reduced the quantum of cash currency and circulation in India. It has increased the taxation base and spurred greater digitization of the economy. The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) has changed the lender-debtor relationship. The recapitalized banks will now have a greater ability to support growth. All these structural reforms in the medium and long run will help Indian economy achieve stronger growth for a long time.

4. Indian economy has performed very well since our Government took over in May, 2014. India achieved an average growth of 7.5% in first three years of our Government. Indian economy is now 2.5 trillion dollar economy—seventh largest in the world. India is expected to become the fifth largest economy very soon. On Purchasing Power Parity (PPP) basis, we are already the third largest economy.

5. Indian society, polity and economy had shown remarkable resilience in adjusting with the structural reforms. GDP growth at 6.3% in the second quarter signaled turnaround of the economy. We hope to grow at 7.2% to 7.5% in the second half. IMF, in its latest Update, has forecast that India will grow at 7.4% next year. Manufacturing sector is back on good growth path. The services, mainstay of our growth, have also resumed their high growth rates of 8% plus. Our exports are expected to grow at 15% in 2017-18. We are now firmly on course to achieve high growth of 8% plus.

6. We have taken up programmes to direct the benefits of structural changes and good growth to reach farmers, poor and other vulnerable sections of our society and to uplift the under-developed regions. This year's Budget will consolidate these gains and particularly focus on strengthening agriculture and rural economy, provision of good health care to economically less privileged, taking care of senior citizens, infrastructure creation and working with the States to provide more resources for improving the quality of education in the country.

7. Prime Minister Shri Narendra Modi has always stressed importance of good governance. He has articulated the vision of "Minimum Government and Maximum Governance". This vision has inspired Government agencies in carrying out hundreds of reforms in policies, rules and procedures. This transformation is reflected in improvement of India's ranking by 42 places in last three years in the World Bank's 'Ease of Doing Business' with India breaking into top 100 for the first time. I would like to congratulate all those who worked to achieve this.

8. Now, our Government has taken Ease of Doing business further by stress on 'Ease of Leaving' for the common men of this country, especially for those belonging to poor & middle class of the society. Good governance also aims at minimum interference by the government in the life of common people of the country.

9. Government is providing free LPG connections to the poor of this country through Ujjwala Yojana. Under Saubhagya Yojna 4 crore household are being provided with electricity connections. More than 800 medicines are being sold at lower price through more than 3 thousand Jan Aushadhi Centres. Cost of stents have been controlled. Special scheme for free dialysis of poor have been initiated. Persons belonging to poor and middle class are also being provided a great relief in interest rates on housing schemes. Efforts are being made to provide all government services, whether bus or train tickets or individual certificates on line. These include passports which may be delivered at doorstep in two or three days or Company registration in one day time and these facilities have benefited a large section of our country. Certificate attestation is not mandatory, interviews for appointment in Group C and Group D posts have been done away with. These measures have saved time and money of lakhs of our youth. Our Government by using modern technology is committed to provide a relief to those who suffer because of rigid rules and regulations.

10. Madam, while undertaking these reforms and programmes, we have worked sincerely and without weighing the political costs. Our Government has ensured that benefits reach eligible beneficiaries and are delivered to them directly. Many services and benefits are being delivered to the people at their doorsteps or in their accounts. It has reduced corruption and cost of delivery and has eliminated middlemen in the process. Direct Benefit Transfer mechanism of India is the biggest such exercise in the world and is a global success story.

Section II

Investment, Expenditure and Policy Initiatives

Agriculture and Rural Economy

11. My Government is committed for the welfare of farmers. For decades, country's agriculture policy and programme had remained production centric. We have sought to effect a paradigm shift. Honourable Prime Minister gave a clarion call to double farmers' income by 2022 when India celebrates its 75th year of independence. Our emphasis is on generating higher incomes for farmers. We consider agriculture as an enterprise and want to help farmers produce more from the same land parcel at lesser cost and simultaneously realize higher prices for their produce. Our emphasis is also on generating productive and gainful on-farm and non-farm employment for the farmers and landless families.

12. Madam Speaker, as a result of the hard work of our country's farmers agriculture production in our country is at a record level. Doing the year 2016-17 we achieved a record food grain production of around 275 million tonnes and around 300 million tonnes of fruits and vegetables.

13. Madam Speaker, in our party's manifesto it has been stated that the farmers should realize at least 50 per cent more than the cost of their produce, in other words, one and a half times of the cost of their production. Government have been very much sensitive to this resolutions and it has declared Minimum support price (MSP) for the majority of rabi crops at least at one and a half times the cost involved. Now, we

have decided to implement this resolution as a principle for the rest of crops. I am pleased to announce that as per pre-determined principle, Government has decided to keep MSP for the all unannounced crops of kharif at least at one and half times of their production cost. I am confident that this historic decision will prove an important step towards doubling the income of our farmers.

14. Our Government works with the holistic approach of solving any issue rather than in fragments. Increasing MSP is not adequate and it is more important that farmers should get full benefit of the announced MSP. For this, it is essential that if price of the agriculture produce market is less than MSP, then in that case Government should purchase either at MSP or work in a manner to provide MSP for the farmers through some other mechanism. Niti Ayog, in consultation with Central and State Governments, will put in place a fool-proof mechanism so that farmers will get adequate price for their produce.

15. For better price realization, farmers need to make decisions based on prices likely to be available after its harvest. Government will create an institutional mechanism, with participation of all concerned Ministries, to develop appropriate policies and practices for price and demand forecast, use of futures and options market, expansion of warehouse depository system and to take decisions about specific exports and imports related measures.

16. Madam Speaker, last year, I had announced strengthening of e-NAM and to expand coverage of e-NAM to 585 APMCs. 470 APMCs have been connected to e-NAM network and rest will be connected by March, 2018.

17. More than 86% of our farmers are small and marginal. They are not always in a position to directly transact at APMCs and other wholesale markets. We will develop and upgrade existing 22,000 rural haats into Gramin Agricultural Markets (GrAMs). In these GrAMs, physical infrastructure will be strengthened using MGNREGA and other Government Schemes. These GrAMs, electronically linked to e-NAM and exempted from regulations of APMCs, will provide farmers facility to make direct sale to consumers and bulk purchasers.

18. An Agri-Market Infrastructure Fund with a corpus of ₹2000 crore will be set up for developing and upgrading agricultural marketing infrastructure in the 22000 Grameen Agricultural Markets (GrAMs) and 585 APMCs.

19. Task of connecting all eligible habitations with an all-weather road has been substantially completed, with the target date brought forward to March, 2019 from March 2022. It is now time to strengthen and widen its ambit further to include major link routes which connect habitations to agricultural and rural markets (GrAMs), higher secondary schools and hospitals. Prime Minister Gram Sadak Yojana Phase III will include such linkages.

20. For several years, we have been stating that India is primarily an agriculture based country. As India is primarily an agriculture based country, our districts can specialize in some or other agricultural produce and be known for it. But special attention is lacking in this regard. There is a need to develop cluster based model in a scientific manner for identified agriculture produces in our districts in the same manner as we have developed model for industrial sector.

21. Cultivation of horticulture crops in clusters bring advantages of scales of operations and can spur establishment of entire chain from production to marketing, besides giving recognition to the districts for specific crops. The Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare will reorient its ongoing Schemes and promote cluster based development of agri-commodities and regions in partnership with the Ministries of Food Processing, Commerce and other allied Ministries.

22. Our Government has promoted organic farming in a big way. Organic farming by Farmer Producer Organizations (FPOs) and Village Producers' Organizations (VPOs) in large clusters, preferably of 1000 hectares each, will be encouraged. Women Self Help Groups (SHGs) will also be encouraged to take up organic agriculture in clusters under National Rural Livelihood Programme.

23. Our ecology supports cultivation of highly specialized medicinal and aromatic plants. India is also home to a large number of small and cottage industries that manufacture perfumes, essential oils and

other associated products. Our Government shall support organized cultivation and associated industry. I propose to allocate a sum of ₹200 crore for this purpose.

24. Food Processing sector is growing at an average rate of 8% per annum. Prime Minister Krishi Sampada Yojana is our flagship programme for boosting investment in food processing. Allocation of Ministry of Food Processing is being doubled from ₹715 crore in RE 2017-18 to ₹1400 crore in BE 2018-19. Government will promote establishment of specialized agro-processing financial institutions in this sector.

25. Tomato, onion and potato are basic vegetables consumed throughout the year. However, seasonal and regional production of these perishable commodities pose a challenge in connecting farmers and consumers in a manner that satisfies both. My Government proposes to launch an “Operation Greens” on the lines of “Operation Flood”. “Operation Greens” shall promote Farmer Producers Organizations (FPOs), agri-logistics, processing facilities and professional management. I propose to allocate a sum of ₹500 crore for this purpose.

26. India’s agri-exports potential is as high as US \$ 100 billion against current exports of US \$ 30 billion. To realize this potential, export of agri-commodities will be liberalized. I also propose to set up state-of-the-art testing facilities in all the forty two Mega Food Parks.

27. I propose to extend the facility of Kisan Credit Cards to fisheries and animal husbandry farmers to help them meet their working capital needs. Small and marginal farmers will get more benefits.

28. Bamboo is ‘Green Gold’. We removed bamboo grown outside forest areas from the definition of trees. Now, I propose to launch a Re-structured National Bamboo Mission with an outlay of ₹1290 crore to promote bamboo sector in a holistic manner.

29. Many farmers are installing solar water pumps to irrigate their fields. Generation of solar electricity is harvesting of Sun by the farmers using their lands. Government of India will take necessary measures and encourage State Governments to put in place a mechanism that their surplus solar power is purchased by the distribution companies or licencees at reasonably remunerative rates.

30. Our Government set up a Long Term Irrigation Fund (LTIF) in NABARD for meeting funding requirement of irrigation works. Scope of the Fund would be expanded to cover specified command area development projects.

31. Last year, I had announced setting up of Micro Irrigation Fund (MIF) for facilitating expansion of coverage under micro irrigation and Dairy Processing Infrastructure Development Fund (DPIDF) to help finance investment in dairying infrastructure. It is now time to expand such focused investment Funds. I, now, announce setting up a Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FAIDF) for fisheries sector and an Animal Husbandry Infrastructure Development Fund (AHIDF) for financing infrastructure requirement of animal husbandry sector. Total Corpus of these two new Funds would be ₹10,000 crore.

32. Our Government has been steadily increasing the volume of institutional credit for agriculture sector from year-to-year from ₹8.5 lakh crore in 2014-15 to ₹10 lakh crore in 2017-18. I now propose to raise this to ₹11 lakh crore for the year 2018-19.

33. Presently, lessee cultivators are not able to avail crop loans. Consequently, a significant proportion of arable land remains fallow and tenant cultivators are forced to secure credit from usurious money lenders. NITI Aayog, in consultation with State Governments, will evolve a suitable mechanism to enable access of lessee cultivators to credit without compromising the rights of the land owners.

34. Government will extend a favourable taxation treatment to Farmer Producers Organisations (FPOs) for helping farmers aggregate their needs of inputs, farm services, processing and sale operations. I shall give details in Part B of my speech.

35. Air pollution in the Delhi-NCR region has been a cause of concern. A special Scheme will be implemented to support the efforts of the governments of Haryana, Punjab, Uttar Pradesh and the NCT of Delhi to address air pollution and to subsidize machinery required for in-situ management of crop residue.

36. Madam Speaker, the present top leadership of this country has reached at this level after seeing poverty at close quarters. Our leadership is familiar with the problems being faced by the SC, ST, Backward Classes and economically weaker sections of the society. People belonging to poor and middle class are not case studies for them, on the other hand they themselves are case study.

37. The Lower and Middle Class have been the focus of our Government during the last three years. This Government is continuously striving to alleviate all the small and major problems of the poor.

38. We launched Prime Minister's Ujjwala Scheme to make poor women free from the smoke of wood. Initially our target was to provide free LPG connections to about 5 crore poor women. But in view of the pace of implementation of Ujjwala scheme and its popularity among the women, we propose to increase the target of providing free connection to 8 crore poor women.

39. Our Government has launched Prime Minister Saubhagya Yojana for providing electricity to all households of the country. Under this scheme, four crores poor households are being provided with electricity connection free of charge. We are spending ₹16000 crore under this scheme. You can very well imagine our anxiety and restlessness even with one hour power cut. Think about those women and children whose houses will not get electricity. Their life is going to change because of Pradhan Mantri Saubhagya Yojana.

40. Swachh Bharat Mission has benefited the poor. Under this mission, Government has already constructed more than 6 crore toilets. The positive effect of these toilets is being seen on the dignity of ladies, education of girls and the overall health of family. Government is planning to construct around 2 crore toilets.

41. Madam Speaker, a roof for his family is another concern of the poor. Far from the Benami properties earned by corruption, the poor only desire to have a roof, a small house by his earning of honesty. Our Govt. is helping them so that they may fulfil the dream of their own house. We have fixed a target that every poor of this country may have his own house by 2022. For this purpose Prime Minister Awas Yojana has been launched in rural and urban areas of the country. Under Prime Minister Awas Scheme Rural, 51 lakhs houses in year 2017-18 and 51 lakh houses during 2018-19 which is more than one crore houses will be constructed exclusively in rural areas. In urban areas the assistance has been sanctioned to construct 37 lakh houses.

42. My Government will also establish a dedicated Affordable Housing Fund (AHF) in National Housing Bank, funded from priority sector lending shortfall and fully serviced bonds authorized by the Government of India.

43. Loans to Self Help Groups of women increased to about Rupees 42,500 crore in 2016-17, growing 37% over previous year. The Government is confident that loans to SHGs will increase to ₹75,000 crore by March, 2019. I propose to substantially increase allocation of National Rural Livelihood Mission to ₹5750 crore in 2018-19.

44. Ground water irrigation scheme under Prime Minister Krishi Sinchai Yojna- Har Khet ko Pani will be taken up in 96 deprived irrigation districts where less than 30% of the land holdings gets assured irrigation presently. I have allocated ₹2600 crore for this purpose.

45. As my proposals outlined indicate, focus of the Government next year will be on providing maximum livelihood opportunities in the rural areas by spending more on livelihood, agriculture and allied activities and construction of rural infrastructure. In the year 2018-19, for creation of livelihood and infrastructure in rural areas, total amount to be spent by the Ministries will be ₹14.34 lakh crore, including extra-budgetary and non-budgetary resources of ₹11.98 lakh crore. Apart from employment due to farming activities and self employment, this expenditure will create employment of 321 crore person days, 3.17 lakh kilometers of rural roads, 51 lakh new rural houses, 1.88 crore toilets, and provide 1.75 crore new household electric connections besides boosting agricultural growth. Details are in Annexure I.

Health, Education and Social Protection

46. My Government's goal is to assist and provide opportunity to every Indian to realize her full potential capable of achieving her economic and social dreams. Our Government is implementing a comprehensive social security and protection programme to reach every household of old, widows,

orphaned children, divyaang and deprived as per the Socio-Economic Caste Census. Allocation on National Social Assistance Programme this year has been kept at ₹9975 crore.

47. We have managed to get children to School but the quality of education is still a cause of serious concern. We have now defined learning outcomes and National Survey of more than 20 lakh children has been conducted to assess the status on the ground. This will help in devising a district-wise strategy for improving quality of education. We now propose to treat education holistically without segmentation from pre-nursery to Class 12.

48. Improvement in quality of teachers can improve the quality of education in the country. We will initiate an integrated B.Ed. programme for teachers. Training of teachers during service is extremely critical. We have amended the Right to Education Act to enable more than 13 lakh untrained teachers to get trained.

49. Technology will be the biggest driver in improving the quality of education. We propose to increase the digital intensity in education and move gradually from “black board” to “digital board”. Technology will also be used to upgrade the skills of teachers through the recently launched digital portal “DIKSHA”.

50. The Government is committed to provide the best quality education to the tribal children in their own environment. To realise this mission, it has been decided that by the year 2022, every block with more than 50% ST population and at least 20,000 tribal persons, will have an Ekalavya Model Residential School. Ekalavya schools will be on par with Navodaya Vidyalayas and will have special facilities for preserving local art and culture besides providing training in sports and skill development.

51. To step up investments in research and related infrastructure in premier educational institutions, including health institutions, I propose to launch a major initiative named “Revitalising Infrastructure and Systems in Education (RISE) by 2022” with a total investment of ₹1,00,000 crore in next four years. Higher Education Financing Agency (HEFA) would be suitably structured for funding this initiative.

52. Our Government has taken major initiative of setting up Institutes of Eminence. There has been tremendous response to this initiative by institutions both in public and private sectors. We have received more than 100 applications. We have also taken steps to set up a specialized Railways University at Vadodara.

53. We propose to set up two new full-fledged Schools of Planning and Architecture, to be selected on challenge mode. Additionally, 18 new SPAs would be established in the IITs and NITs as autonomous Schools, also on challenge mode.

54. The Government would launch the “Prime Minister’s Research Fellows (PMRF)” Scheme this year. Under this, we would identify 1,000 best B.Tech students each year from premier institutions and provide them facilities to do Ph.D in IITs and IISc, with a handsome fellowship. It is expected that these bright young fellows would voluntarily commit few hours every week for teaching in higher educational institutions.

55. Now I come to the Health Sector. सर्वे भवन्तु: सुखिन, सर्वे संतु: निरामया is the guiding principle of my Government. Only Swasth Bharat can be a Samridhha Bharat. India cannot realize its demographic dividend without its citizens being healthy.

56. I am pleased to announce two major initiatives as part of “Ayushman Bharat” programme aimed at making path breaking interventions to address health holistically, in primary, secondary and tertiary care system covering both prevention and health promotion.

57. The National Health Policy, 2017 has envisioned Health and Wellness Centres as the foundation of India’s health system. These 1.5 lakh centres will bring health care system closer to the homes of people. These centres will provide comprehensive health care, including for non-communicable diseases and maternal and child health services. These centres will also provide free essential drugs and

diagnostic services. I am committing ₹1200 crore in this budget for this flagship programme. I also invite contribution of private sector through CSR and philanthropic institutions in adopting these centres.

58. Madam Speaker, we are all aware that lakhs of families in our country have to borrow or sell assets to receive indoor treatment in hospitals. Government is seriously concerned about such impoverishment of poor and vulnerable families. Present Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) provide annual coverage of only ₹30,000 to poor families. Several State Governments have also implemented/supplemented health protection schemes providing varying coverage. My Government has now decided to take health protection to more aspirational level.

59. We will launch a flagship National Health Protection Scheme to cover over 10 crore poor and vulnerable families (approximately 50 crore beneficiaries) providing coverage upto 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization. This will be the world's largest government funded health care programme. Adequate funds will be provided for smooth implementation of this programme.

60. Madam Speaker, these two far-reaching initiatives under the Ayushman Bharat will build a New India 2022 and ensure enhanced productivity, well being and avert wage loss and impoverishment. These Schemes will also generate lakhs of jobs, particularly for women. The Government is steadily but surely progressing towards the goal of Universal Health Coverage.

61. TB claims more lives every year than any other infectious disease. It affects mainly poor and malnourished people. My Government has, therefore, decided to allocate additional ₹600 crore to provide nutritional support to all TB patients at the rate of ₹500 per month for the duration of their treatment.

62. In order to further enhance accessibility of quality medical education and health care, we will be setting up 24 new Government Medical Colleges and Hospitals by upgrading existing district hospitals in the country. This would ensure that there is at least 1 Medical College for every 3 Parliamentary Constituencies and at least 1 Government Medical College in each State of the country.

63. Our resolve of making our villages open defecation free is aimed at improving the life of our villagers. We will launch a Scheme called Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan (GOBAR-DHAN) for management and conversion of cattle dung and solid waste in farms to compost, fertilizer, bio-gas and bio-CNG.

64. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Beema Yojana (PMJJBY) has benefitted 5.22 crore families with a life insurance cover of ₹2 lakh on payment of a premium of only ₹330/- per annum. Likewise, under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, 13 crore 25 lakh persons have been insured with personal accident cover of ₹2 lakh on payment of a premium of only ₹12 per annum. The Government will work to cover all poor households, including SC/ST households, under these in a mission mode.

65. The Government will expand the coverage under Prime Minister Jan Dhan Yojana by bringing all sixty crore basic accounts within its fold and undertake measures to provide services of micro insurance and unorganized sector pension schemes through these accounts.

66. Our commitment towards "Beti Bachao Beti Padhao" is unflinching. Sukanya Samridhi Account Scheme launched in January 2015 has been a great success. Until November, 2017 more than 1.26 crore accounts have been opened across the country in the name of girl-child securing an amount of ₹19,183 crore.

67. Cleaning the Ganga is work of national importance and it is our firm commitment. Members will be happy to learn that this work has gathered speed. A total of 187 projects have been sanctioned under the Namami Gange programme for infrastructure development, river surface cleaning, rural sanitation and other interventions at a cost of ₹16,713 crore. 47 projects have been completed and remaining projects are at various stages of execution. All 4465 Ganga Grams—villages on the bank of river—have been declared open defecation free.

68. To give focused attention and to achieve our vision of an inclusive society, the Government has identified 115 aspirational districts taking various indices of development in consideration. The Government aims at improving the quality of life in these districts by investing in social services like health, education, nutrition, skill upgradation, financial inclusion and infrastructure like irrigation, rural electrification, potable drinking water and access to toilets at an accelerated pace and in a time bound manner. We expect these 115 districts to become model of development.

69. Economic and social advancement of hard working people of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) has received core attention of Government. Our Government increased total earmarked allocation for SCs in 279 programmes from ₹34,334 crore in 2016-17 to ₹52,719 crore in RE 2017-18. Likewise, for STs, earmarked allocation was increased from ₹21,811 crore in 2016-17 to ₹32,508 crore in RE 2017-18 in 305 programmes. I propose an earmarked allocation of ₹56,619 crore for SCs and ₹39,135 crore for STs in BE 2018-19.

70. Government's estimated schematic budgetary expenditure on health, education and social protection for 2018-19 is ₹1.38 lakh crore against estimated expenditure of ₹1.22 lakh crore in BE 2017-18. Details are in Annexure II. This expenditure is likely to go up by at least ₹15,000 crore in 2018-19 on account of additional allocation during the year and extra budgetary expenditure, including through Higher Education Financing Agency.

Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs) and Employment

71. Medium, Small and Micro Enterprises (MSMEs) are a major engine of growth and employment in the country. I have provided ₹3794 crore to MSME Sector for giving credit support, capital and interest subsidy and innovations. Massive formalization of the businesses of MSMEs is taking place in the country after demonetization and introduction of GST. This is generating enormous financial information database of MSMEs' businesses and finances. This big data base will be used for improving financing of MSMEs' capital requirement, including working capital.

72. It is proposed to onboard public sector banks and corporates on Trade Electronic Receivable Discounting System (TReDS) platform and link this with GSTN. Online loan sanctioning facility for MSMEs will be revamped for prompt decision making by the banks. Government will soon announce measures for effectively addressing non-performing assets and stressed accounts of MSMEs. This will enable larger financing of MSMEs and also considerably ease cash flow challenges faced by them. In order to reduce tax burden on MSMEs and to create larger number of jobs, I will be announcing some tax measures in Part B of my speech.

73. MUDRA Yojana launched in April, 2015 has led to sanction of ₹4.6 lakh crore in credit from 10.38 crore MUDRA loans. 76% of loan accounts are of women and more than 50% belong to SCs, STs and OBCs. It is proposed to set a target of ₹3 lakh crore for lending under MUDRA for 2018-19 after having successfully exceeded the targets in all previous years.

74. Non-Bank Finance Companies (NBFCs) stepped up financing of MSMEs after demonetization. NBFCs can be very powerful vehicle for delivering loans under MUDRA. Refinancing policy and eligibility criteria set by MUDRA will be reviewed for better refinancing of NBFCs.

75. Use of Fintech in financing space will help growth of MSMEs. A group in the Ministry of Finance is examining the policy and institutional development measures needed for creating right environment for Fintech companies to grow in India.

76. Venture Capital Funds and the angel investors need an innovative and special developmental and regulatory regime for their growth. We have taken a number of policy measures including launching "Start-Up India" program, building very robust alternative investment regime in the country and rolling out a taxation regime designed for the special nature of the VCFs and the angel investors. We will take additional measures to strengthen the environment for their growth and successful operation of alternative investment funds in India.

77. Creating job opportunities and facilitating generation of employment has been at the core of our policy-making. During the last three years, we have taken a number of steps to boost employment generation in the country. These measures include:-

- Contribution of 8.33% of Employee Provident Fund (EPF) for new employees by the Government for three years.
- Contribution of 12% to EPF for new employees for three years by the Government in sectors employing large number of people like textile, leather and footwear.
- Additional deduction to the employees of 30% of the wages paid for new employees under the Income Tax Act.
- Launch of National Apprenticeship Scheme with stipend support and sharing of the cost of basic training by the Government to give training to 50 lakh youth by 2020.
- Introducing system of fixed term employment for apparel and footwear sector.
- Increasing paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks, along with provision of crèches.

78. These measures have started showing results. An independent study conducted recently has shown that 70 lakh formal jobs will be created this year.

79. To carry forward this momentum, I am happy to announce that the Government will contribute 12% of the wages of the new employees in the EPF for all the sectors for next three years. Also, the facility of fixed term employment will be extended to all sectors.

80. To incentivize employment of more women in the formal sector and to enable higher take-home wages, I propose to make amendments in the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 to reduce women employees' contribution to 8% for first three years of their employment against existing rate of 12% or 10% with no change in employers' contribution.

81. The Government is setting up a model aspirational skill centre in every district of the country under Pradhan Mantri Kaushal Kendra Programme. 306 Pradhan Mantri Kaushal Kendra have been established for imparting skill training through such centers.

82. The Government had approved a comprehensive textile sector package of ₹6000 crore in 2016 to boost the apparel and made-up segments. I, now propose to provide an outlay of ₹7148 crore for the textile sector in 2018-19.

Infrastructure and Financial Sector Development

83. Infrastructure is the growth driver of economy. Our country needs massive investments estimated to be in excess of ₹50 lakh crore in infrastructure to increase growth of GDP, connect and integrate the nation with a network of roads, airports, railways, ports and inland waterways and to provide good quality services to our people.

84. We have made an all-time high allocation to rail and road sectors. We are committed to further enhance public investment. Provision of key linkages like coal for power, power for railways and railway rakes for coal have been rationalized and made very efficient. Prime Minister personally reviews the targets and achievements in infrastructure sectors on a regular basis. Using online monitoring system of PRAGATI alone, projects worth 9.46 lakh crore have been facilitated and fast tracked.

85. To secure India's defences, we are developing connectivity infrastructure in border areas. Rohtang tunnel has been completed to provide all weather connectivity to the Ladakh region. Contract for construction of Zozila Pass tunnel of more than 14 kilometer is progressing well. I now propose to

take up construction of tunnel under Sela Pass. For promoting tourism and emergency medical care, Government will make necessary framework for encouraging investment in sea plane activities.

86. Urbanization is our opportunity and priority. My Government has rolled out two interlinked programmes – Smart Cities Mission and the AMRUT.

87. Smart Cities Mission aims at building 100 Smart Cities with state-of-the-art amenities. I am happy to inform that 99 Cities have been selected with an outlay of ₹2.04 lakh crore. These Cities have started implementing various projects like Smart Command and Control Centre, Smart Roads, Solar Rooftops, Intelligent Transport Systems, Smart Parks. Projects worth ₹2350 crore have been completed and works of ₹20,852 crore are under progress. To preserve and revitalize soul of the heritage cities in India, National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY) has been taken up in a major way.

88. India is blessed with an abundance of tourist attractions. It is proposed to develop ten prominent tourist sites into Iconic Tourism destinations by following a holistic approach involving infrastructure and skill development, development of technology, attracting private investment, branding and marketing. In addition, tourist amenities at 100 Adarsh monuments of the Archaeological Survey of India will be upgraded to enhance visitor experience.

89. The AMRUT programme focuses on providing water supply to all households in 500 cities. State level plans of ₹77,640 crore for 500 cities have been approved. Water supply contracts for 494 projects worth ₹19,428 crore and sewerage work contract for 272 projects costing ₹12,429 crore has been awarded.

90. Reforms are being catalyzed by these missions. 482 cities have started credit rating. 144 cities have got investment grade rating.

91. My Ministry will leverage the India Infrastructure Finance Corporation Limited (IIFCL) to help finance major infrastructure projects, including investments in educational and health infrastructure, on strategic and larger societal benefit considerations.

92. Our Government has scaled new heights in development of Road Infrastructure sector. We are confident to complete National Highways exceeding 9000 kilometers length during 2017-18. Ambitious Bharatmala Pariyojana has been approved for providing seamless connectivity of interior and backward areas and borders of the country to develop about 35000 kms in Phase-I at an estimated cost of ₹5,35,000 crore. To raise equity from the market for its mature road assets, NHAI will consider organizing its road assets into Special Purpose Vehicles and use innovative monetizing structures like Toll, Operate and Transfer (TOT) and Infrastructure Investment Funds (InvITs).

93. Strengthening the railway network and enhancing Railways' carrying capacity has been a major focus of the Government. Railways' Capex for the year 2018-19 has been pegged at ₹1,48,528 crore. A large part of the Capex is devoted to capacity creation. 18,000 kilometers of doubling, third and fourth line works and 5000 kilometers of gauge conversion would eliminate capacity constraints and transform almost entire network into Broad Gauge.

94. There has also been significant improvement in the achievement of physical targets by Railways as well. We are moving fast towards optimal electrification of railway network. 4000 kilometers are targeted for commissioning during 2017-18.

95. Work on Eastern and Western dedicated Freight Corridors is in full swing. Adequate number of rolling stock – 12000 wagons, 5160 coaches and approximately 700 locomotives are being procured during 2018-19. A major programme has been initiated to strengthen infrastructure at the Goods sheds and fast track commissioning of private sidings.

96. A 'Safety First' policy, with allocation of adequate funds under Rashtriya Rail Sanraksha Kosh is cornerstone of Railways' focus on safety. Maintenance of track infrastructure is being given special attention. Over 3600 kms of track renewal is targeted during the current fiscal. Other major steps

include increasing use of technology like “Fog Safe” and “Train Protection and Warning System”. A decision has been taken to eliminate 4267 unmanned level crossings in the broad gauge network in the next two years.

97. Redevelopment of 600 major railway stations is being taken up by Indian Railway Station Development Co. Ltd. All stations with more than 25000 footfalls will have escalators. All railway stations and trains will be progressively provided with wi-fi. CCTVs will be provided at all stations and on trains to enhance security of passengers. Modern train-sets with state-of-the-art amenities and features are being designed at Integrated Coach Factory, Perambur. First such train-set will be commissioned during 2018-19.

98. Mumbai’s transport system, the lifeline of the City, is being expanded and augmented to add 90 kilometers of double line tracks at a cost of over ₹11,000 crore. 150 kilometers of additional suburban network is being planned at a cost of over ₹40,000 crore, including elevated corridors on some sections. A suburban network of approximately 160 kilometers at an estimated cost of ₹17,000 crore is being planned to cater to the growth of the Bengaluru metropolis.

99. Foundation for the Mumbai-Ahmedabad bullet train project, India’s first high speed rail project was laid on September 14, 2017. An Institute is coming up at Vadodara to train manpower required for high speed rail projects.

100. In the last three years, the domestic air passenger traffic grew at 18% per annum and our airline companies placed orders for more than 900 aircrafts. Regional connectivity scheme of UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) initiated by the Government last year shall connect 56 unserved airports and 31 unserved helipads across the country. Operations have already started at 16 such airports. सरकार की इस पहल से हवाई चप्पल पहनने वाले नागरिक भी हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं। Airport Authority of India (AAI) has 124 airports. We propose to expand our airport capacity more than five times to handle a billion trips a year under a new initiative - NABH Nirman. Balance sheet of AAI shall be leveraged to raise more resources for funding this expansion.

101. Our efforts to set up a Coalition on Disaster Resilient Infrastructure for developing international good practices, appropriate standards and regulatory mechanism for resilient infrastructure development are moving well. I propose to allocate ₹60 crores to kick start this initiative in 2018-19.

102. The Government and market regulators have taken necessary measures for development of monetizing vehicles like Infrastructure Investment Trust (InvIT) and Real Investment Trust (REITs) in India. The Government would initiate monetizing select CPSE assets using InvITs from next year.

103. In the current year, we included, in the scope of harmonized list of infrastructure, ropeways to promote tourism, logistics parks and expanded the scope of railways infrastructure to include development of commercial land around railway stations.

104. Reserve Bank of India has issued guidelines to nudge Corporates access bond market. SEBI will also consider mandating, beginning with large Corporates, to meet about one-fourth of their financing needs from the bond market.

105. Corporate bonds rated ‘BBB’ or equivalent are investment grade. In India, most regulators permit bonds with the ‘AA’ rating only as eligible for investment. It is now time to move from ‘AA’ to ‘A’ grade ratings. The government and concerned regulators will take necessary action.

106. We will take reform measures with respect to stamp duty regime on financial securities transactions in consultation with the States and make necessary amendments the Indian Stamp Act.

107. International Financial Service Centre (IFSC) at Gift City, which has become operational, needs a coherent and integrated regulatory framework to fully develop and to compete with other offshore financial centres. The Government will establish a unified authority for regulating all financial services in IFSCs in India.

108. Global economy is transforming into a digital economy thanks to development of cutting edge technologies in digital space – machine learning, artificial intelligence, internet of things, 3D printing and the like. Initiatives such as Digital India, Start Up India, Make in India would help India establish itself as a knowledge and digital society. NITI Aayog will initiate a national program to direct our efforts in the area of artificial intelligence, including research and development of its applications.

109. Combining cyber and physical systems have great potential to transform not only innovation ecosystem but also our economies and the way we live. To invest in research, training and skilling in robotics, artificial intelligence, digital manufacturing, big data analysis, quantum communication and internet of things, Department of Science & Technology will launch a Mission on Cyber Physical Systems to support establishment of centres of excellence. I have doubled the allocation on Digital India programme to ₹ 3073 crore in 2018-19.

110. Task of connecting one lakh gram panchayat through high speed optical fiber network has been completed under phase I of the Bharatnet project. This has enabled broadband access to over 20 crore rural Indians in about two lakh fifty thousand villages. The Government also proposes to setup five lakh wi-fi hotspots which will provide broadband access to five crore rural citizens. I have provided ₹10000 crore in 2018-19 for creation and augmentation of Telecom infrastructure.

111. To harness the benefit of emerging new technologies, particularly the 'Fifth Generation' (5G) technologies and its adoption, the Department of Telecom will support establishment of an indigenous 5G Test Bed at IIT, Chennai.

112. Distributed ledger system or the block chain technology allows organization of any chain of records or transactions without the need of intermediaries. The Government does not consider cryptocurrencies legal tender or coin and will take all measures to eliminate use of these crypto-assets in financing illegitimate activities or as part of the payment system. The Government will explore use of block chain technology proactively for ushering in digital economy.

113. The system of toll payments physically by cash at road toll plazas is being fast replaced with Fastags and other electronic payment systems to make road travel seamless. Number of Fastags has gone up from about 60,000 in December, 2016 to more than 10 lakh now. From December, 2017 all class "M" and "N" vehicles are being sold only with the Fastags. The Government will come out with a policy to introduce toll system on "pay as you use" basis.

114. In order to create employment and aid growth, Government's estimated budgetary and extra budgetary expenditure on infrastructure for 2018-19 is being increased to ₹5.97 lakh crore against estimated expenditure of ₹4.94 lakh crore in 2017-18. Details are in **Annexure III**.

Building Institutions and Improving Public Service Delivery

115. Our armed forces have played a stellar role in meeting the challenges we have been facing on our borders as well as in managing the internal security environment both in Jammu and Kashmir and the North East. I would like to place on record our appreciation for the efforts and the sacrifices made by the three services in defending the interests of the Nation.

116. Ever since the NDA Government has assumed office in 2014, lot of emphasis has been given to modernizing and enhancing the operational capability of the Defence Forces. A number of initiatives have been taken to develop and nurture intrinsic defence production capability to make the Nation self-reliant for meeting our defence needs. Ensuring adequate budgetary support will be our priority.

117. We have opened up private investment in defence production including liberalizing foreign direct investment. We will take measures to develop two defence industrial production corridors in the country. The Government will also bring out an industry friendly Defence Production Policy 2018 to promote domestic production by public sector, private sector and MSMEs.

118. Aadhar has provided an identity to every Indian. Aadhar has eased delivery of so many public services to our people. Every enterprise, major or small, also needs a unique ID. The Government will evolve a Scheme to assign every individual enterprise in India a unique ID.

119. To carry the business reforms for ease of doing business deeper and in every State of India, the Government of India has identified 372 specific business reform actions. All States have taken up these reforms and simplifications in a mission mode constructively competing with each other. Evaluation of performance under this Programme will now be based on user feedback.

120. Capital of the Food Corporation of India will be restructured to enhance equity and to raise long-term debt for meeting its standing working capital requirement.

121. Budgeting of Government of India's contribution in equity and debt of the metro ventures floated by the State Governments will be streamlined.

122. Department of Commerce will be developing a National Logistics Portal as a single window online market place to link all stakeholders.

123. The Government has approved listing of 14 CPSEs, including two insurance companies, on the stock exchanges. The Government has also initiated the process of strategic disinvestment in 24 CPSEs. This includes strategic privatization of Air India.

124. Process of acquisition of Hindustan Petroleum Corporation by the ONGC has been successfully completed. Three public sector general insurance companies National Insurance Company Ltd., United India Assurance Company Limited and Oriental India Insurance Company Limited will be merged into a single insurance entity and will be subsequently listed.

125. The Government introduced Exchange Traded Fund Bharat-22 to raise ₹14,500 crore, which was over-subscribed in all segments. DIPAM will come up with more ETF offers including debt ETF.

126. 2017-18 Budget Estimates for disinvestment were pegged at the highest ever level of ₹72,500 crore. I am happy to inform the House that we have already exceeded the budget estimates. I am assuming receipts of ₹1,00,000 crore in 2017-18. I am setting the disinvestment target of ₹80,000 crore for 2018-19.

127. Bank recapitalization program has been launched with bonds of ₹80,000 crore being issued this year. The programme has been integrated with an ambitious reform agenda, under the rubric of an Enhanced Access and Service Excellence (EASE) programme. This recapitalization will pave the way for the public sector banks to lend additional credit of ₹5 lakh crore.

128. It is proposed to allow strong Regional Rural Banks to raise capital from the market to enable them increase their credit to rural economy.

129. National Housing Bank Act is being amended to transfer its equity from the Reserve Bank of India to the Government. Indian Post Offices Act, Provident Fund Act and National Saving Certificate Act are being amalgamated and certain additional people friendly measures are being introduced. To provide the Reserve Bank of India an instrument to manage excess liquidity, Reserve Bank of India Act is being amended to institutionalize an Uncollateralized Deposit Facility. Securities and Exchange Board of India, Act 1992, Securities Contracts (Regulation) Act 1956, and Depositories Act 1996, are being amended to streamline adjudication procedures and to provide for penalties for certain infractions. These proposals are in the Finance Bill.

130. For easier access, links to all Detailed Demand for Grants will be provided at india.gov.in. The Government will also consider feasibility of providing disclosed fiscal information in a machine readable form.

131. The Government is transforming method of disposal of its business by introduction of e-office and other e-governance initiatives in central Ministries and Departments. These initiatives are listed in Annexure IV.

132. The Government will formulate a comprehensive Gold Policy to develop gold as an asset class. The Government will also establish a system of consumer friendly and trade efficient system of regulated gold exchanges in the country. Gold Monetization Scheme will be revamped to enable people to open a hassle-free Gold Deposit Account.

133. Outward Direct Investment (ODI) from India has grown to US\$15 billion per annum. The Government will review existing guidelines and processes and bring out a coherent and integrated Outward Direct Investment (ODI) policy.

134. Hybrid instruments are suitable for attracting foreign investments in several niche areas, especially for the startups and venture capital firms. The Government will evolve a separate policy for the hybrid instruments.

135. The emoluments of the President, the Vice President and the Governors were last revised with effect from 1st January, 2006. These emoluments are proposed to be revised to ₹5 lakh for the President, ₹4 lakhs for the Vice President and to ₹3.5 lakh per month for the Governors.

136. There has been a public debate with regard to the emoluments paid to the Members of Parliament. Present practice allows the recipients to fix their own emoluments which invites criticism. I am, therefore, proposing necessary changes to refix the salary, constituency allowance, office expenses and meeting allowance payable to Members of Parliament with effect from April 1, 2018. The law will also provide for automatic revision of emoluments every five years indexed to inflation. I am sure Hon'ble Members will welcome this initiative and will not suffer such criticism in future.

137. Our country will commemorate 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, Father of the Nation, from 2nd October, 2019 to 2nd October 2020. The Government and the People of India will rededicate them, through their actions, to the ideals that the Mahatma taught and lived by. A National Committee, chaired by the Prime Minister, which includes Chief Ministers of all the States, representatives from across the political spectrum, Gandhians, thinkers and eminent persons from all walks of life, has been constituted to formulate a Commemoration Programme. My Government has earmarked ₹150 crore for the year 2018-19 for the activities leading to the Commemoration.

Section III - Fiscal Management

138. I now turn to the fiscal situation for 2017-18 and fiscal estimates for 2018-19.

139. In 2017-18, Central Government will be receiving GST revenues only for 11 months, instead of 12 months. This will have fiscal effect. There has also been some shortfall in Non-Tax revenues on account of certain developments, including deferment of spectrum auction. A part of this shortfall has been made up through higher direct tax revenues and bigger disinvestment receipts.

140. Total Revised Estimates for expenditure in 2017-18 are ₹21.57 lakh crore (net of GST compensation transfers to the States) as against the Budget Estimates of ₹21.47 lakh crore.

141. Our Government assumed office in May, 2014 when fiscal deficit was running at very high levels. Fiscal Deficit for 2013-14 was 4.4% of GDP. The Prime Minister and the Government have always attached utmost priority to prudent fiscal management and controlling fiscal deficit. As Hon'ble Members would recall, we embarked on the path of consistent fiscal reduction and consolidation in 2014. Fiscal Deficit was brought down to 4.1% in 2014-15 to 3.9% in 2015-16, and to 3.5% in 2016-17. Revised Fiscal Deficit estimates for 2017-18 are ₹5.95 lakh crore at 3.5% of GDP. I am projecting a Fiscal Deficit of 3.3% of GDP for the year 2018-19.

142. In order to impart unquestionable credibility to the Government's commitment for the revised fiscal glide path, I am proposing to accept key recommendations of the Fiscal Reform and Budget Management Committee relating to adoption of the Debt Rule and to bring down Central Government's Debt to GDP ratio to 40%. Government has also accepted the recommendation to use Fiscal Deficit target as the key operational parameter. Necessary amendment proposals are included in the Finance Bill.

PART B

Madam Speaker,

143. I shall now present my tax proposals.

144. The attempts made by our Government for reducing the cash economy and for increasing the tax net have paid rich dividends. The growth rate of direct taxes in the financial years 2016-17 and 2017-18 has been significant. We ended the last year with a growth of **12.6%** in direct taxes and in the current year, the growth in direct taxes up to 15th January, 2018 is **18.7%**. The average buoyancy in personal income tax of seven years preceding these two years comes to **1.1**. In simple terms tax buoyancy of **1.1** means that if nominal GDP growth rate of the country is **10%**, the growth rate of personal income tax is **11%**. However, the buoyancy in personal income tax for financial years 2016-17 and 2017-18 (RE) is **1.95** and **2.11** respectively. This indicates that the excess revenue collected in the last two financial years from personal income tax compared to the average buoyancy pre 2016-17 amounts to a total of about **₹90,000 crores** and the same can be attributed to the strong anti-evasion measures taken by the Government.

145. Similarly, there has been huge increase in the number of returns filed by taxpayers. In financial year 2016-17, **85.51 lakhs** new taxpayers filed their returns of income as against **66.26 lakhs** in the immediately preceding year. By including all filers as well as persons who did not file returns but paid tax by way of advance tax or TDS, we can derive the figure of Effective Taxpayer Base. This number of effective tax payer base increased from **6.47 crores** at the beginning of F.Y.14-15 to **8.27 crores** at the end of F.Y.16-17. We are enthused by this success of our measures and we pledge to continue to take all such measures in future by which the black money is contained and the honest taxpayers are rewarded. Demonetization was received well by honest taxpayers as “*imandari ka utsav*” only for this reason.

146. Madam Speaker, recognising the need for facilitating compliance, Government had liberalized the presumptive income scheme for small traders and entrepreneurs with annual turnover of less than ₹2 crores and introduced a similar scheme for professionals with annual turnover of less than ₹50 lakhs with the hope that there would be significant increase in compliance. Under this scheme, **41%** more returns were filed during this year which shows that many more persons are joining the tax net under simplified scheme. However, the turnover shown is still not encouraging. The Department has received **44.72 lakh** returns for assessment year 2017-18 from individual, HUF and firms with a meagre average turnover of **₹17.97 lakhs** and an average tax payment of **₹7,000/-** only. The tax compliance behaviour of professionals is no better; the department has received **5.68 lakh** returns under the presumptive income scheme for assessment year 2017-18 with average gross receipts of **₹5.73 lakhs** only. Average tax paid by them is only **₹35,000/-**.

Tax incentive for promoting post-harvest activities of agriculture

147. Madam Speaker, at present, hundred per cent deduction is allowed in respect of profit of co-operative societies which provide assistance to its members engaged in primary agricultural activities. Over the last few years, a number of Farmer Producer Companies have been set up along the lines of co-operative societies which also provide similar assistance to their members. In order to encourage professionalism in post-harvest value addition in agriculture, I propose to allow hundred per cent deduction to these companies registered as Farmer Producer Companies and having annual turnover up to ₹100 crores in respect of their profit derived from such activities for a period of five years from financial year 2018-19. This measure will encourage “Operation Greens” mission announced by me earlier and it will give a boost to Sampada Yojana.

Employment generation

148. Currently, a deduction of 30% is allowed in addition to normal deduction of 100 % in respect of emoluments paid to eligible new employees who have been employed for a minimum period of 240 days during the year under section 80-JJAA of the Income-tax Act. However, the minimum period of employment is relaxed to 150 days in the case of apparel industry. In order to encourage creation of new employment, I propose to extend this relaxation to footwear and leather industry. Further, I also propose to rationalise this deduction of 30% by allowing the benefit for a new employee who is employed for less than the minimum period during the first year but continues to remain employed for the minimum period in subsequent year.

Incentive for real estate

149. Currently, while taxing income from capital gains, business profits and other sources in respect of transactions in immovable property, the consideration or circle rate value, whichever is higher, is adopted and the difference is counted as income both in the hands of the purchaser and seller. Sometimes, this variation can occur in respect of different properties in the same area because of a variety of factors including shape of the plot and location. In order to minimize hardship in real estate transaction, I propose to provide that no adjustment shall be made in a case where the circle rate value does not exceed 5% of the consideration.

Incentivising micro, small and medium entrepreneurs

150. In the Union Budget, 2017, I had announced the reduction of corporate tax rate to 25% for companies whose turnover was less than **₹50 crore** in financial year 2015-16. This benefitted **96%** of the total companies filing tax returns. Towards fulfilment of my promise to reduce corporate tax rate in a phased manner, I now propose to extend the benefit of this reduced rate of 25% also to companies who have reported **turnover up to ₹250 crore** in the financial year 2016-17. This will benefit the entire class of micro, small and medium enterprises which accounts for almost **99%** of companies filing their tax returns. The estimate of revenue forgone due to this measure is ₹7,000 crores during the financial year 2018-19. After this, out of about 7 lakh companies filing returns, about 7,000 companies which file returns of income and whose turnover is above ₹250 crores will remain in 30% slab. The lower corporate income tax rate for 99% of the companies will leave them with higher investible surplus which in turn will create more jobs.

Relief to salaried taxpayers

151. The Government had made many positive changes in the personal income-tax rate applicable to individuals in the last three years. Therefore, I do not propose to make any further change in the structure of the income tax rates for individuals. There is a general perception in the society that individual business persons have better income as compared to salaried class. However, income tax data analysis suggests that major portion of personal income-tax collection comes from the salaried class. For assessment year 2016-17, **1.89 crore salaried individuals** have filed their returns and have paid total tax of **₹1.44 lakh crores** which works out to average tax payment of **₹76,306/- per individual salaried** taxpayer. As against this, **1.88 crores individual business** taxpayers including professionals, who filed their returns for the same assessment year paid total tax of **₹48,000 crores** which works out to an average tax payment of **₹25,753/- per individual business** taxpayer. In order to provide relief to salaried taxpayers, I propose to allow a standard deduction of **₹40,000/-** in lieu of the present exemption in respect of transport allowance and reimbursement of miscellaneous medical expenses. However, the transport allowance at enhanced rate shall continue to be available to differently-abled persons. Also other medical reimbursement benefits in case of hospitalization etc., for all employees shall continue. Apart from reducing paper work and compliance, this will help middle class employees even more in terms of reduction in their tax liability. This decision to allow standard deduction shall significantly benefit the pensioners also, who normally do not enjoy any allowance on account of transport and medical expenses. The revenue cost of this decision is approximately ₹8,000 crores. The total number of salaried employees and pensioners who will benefit from this decision is around 2.5 crores.

Relief to senior citizen

152. A life with dignity is a right of every individual in general, more so for the senior citizens. To care of those who cared for us is one of the highest honours. To further the objective of providing a dignified life, I propose to announce the following incentives for senior citizens:

- Exemption of interest income on deposits with banks and post offices to be increased from **₹10,000/- to ₹50,000/-** and TDS shall not be required to be deducted on such income, under section 194A. This benefit shall be available also for interest from all fixed deposits schemes and recurring deposit schemes.
- Raising the limit of deduction for health insurance premium and/ or medical expenditure from **₹30,000/- to ₹50,000/-**, under section 80D. All senior citizens will now be able to claim benefit of deduction up to ₹50,000/- per annum in respect of any health insurance premium and/or any general medical expenditure incurred.

- Raising the limit of deduction for medical expenditure in respect of certain critical illness from, ₹60,000/- in case of senior citizens and from ₹80,000/- in case of very senior citizens, to **₹1 lakh** in respect of all senior citizens, under section 80DDB.

These concessions will give extra tax benefit of ₹4,000 crores to senior citizens. In addition to tax concessions, I propose to extend the Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana up to March, 2020 under which an assured return of 8% is given by Life Insurance Corporation of India. The existing limit on investment of ₹7.5 lakh per senior citizen under this scheme is also being enhanced to ₹15 lakh.

Tax incentive for International Financial Services Centre (IFSC)

153. The Government had endeavoured to develop a world class international financial services centre in India. In recent years, various measures including tax incentives have been provided in order to fulfil this objective. To further this objective, I propose to provide two more concessions for IFSC. In order to promote trade in stock exchanges located in IFSC, I propose to exempt transfer of derivatives and certain securities by non-residents from capital gains tax. Further, non-corporate taxpayers operating in IFSC shall be charged Alternate Minimum Tax (AMT) at concessional rate of 9% at par with Minimum Alternate Tax (MAT) applicable for corporates.

Further Measures to control cash economy:

154. Currently, the income of trusts and institutions is exempt if they utilise their income towards their objects in accordance with the relevant provisions of the Income-tax Act. However, there is no restriction on these entities for incurring expenditure in cash. In order to have audit trail of the expenses incurred by these entities, it is proposed that payments exceeding ₹10,000/- in cash made by such entities shall be disallowed and the same shall be subject to tax. Further, in order to improve TDS compliance by these entities, I propose to provide that in case of non-deduction of tax, 30% of the amount shall be disallowed and the same shall be taxed.

Rationalisation of Long Term Capital Gains (LTCG)

155. Madam Speaker, currently, long term capital gains arising from transfer of listed equity shares, units of equity oriented fund and unit of a business trust are exempt from tax. With the reforms introduced by the Government and incentives given so far, the equity market has become buoyant. The total amount of exempted capital gains from listed shares and units is around **₹3,67,000 crores** as per returns filed for **A.Y.17-18**. Major part of this gain has accrued to corporates and LLPs. This has also created a bias against manufacturing, leading to more business surpluses being invested in financial assets. The return on investment in equity is already quite attractive even without tax exemption. There is therefore a strong case for bringing long term capital gains from listed equities in the tax net. However, recognising the fact that vibrant equity market is essential for economic growth, I propose only a modest change in the present regime.

I propose to tax such long term capital gains **exceeding ₹1 lakh** at the rate of **10%** without allowing the benefit of any indexation. However, all **gains up to 31st January, 2018 will be grandfathered**. For example, if an equity share is purchased six months before 31st January, 2018 at ₹100/- and the highest price quoted on 31st January, 2018 in respect of this share is ₹120/-, there will be no tax on the gain of ₹20/- if this share is sold after one year from the date of purchase. However, any gain in excess of ₹20 earned after 31st January, 2018 will be taxed at 10% if this share is sold after 31st July, 2018. The gains from equity share held up to one year will remain short term capital gain and will continue to be taxed at the rate of 15%. Further, I also propose to introduce a tax on distributed income by equity oriented mutual fund at the rate of 10%. This will provide level playing field across growth oriented funds and dividend distributing funds. In view of grandfathering, this change in capital gain tax will bring marginal revenue gain of about **₹20,000 crores** in the first year. The revenues in subsequent years may be more.

Health and Education Cess

156. Madam Speaker, at present there is a three per cent cess on personal income tax and corporation tax consisting of two per cent cess for primary education and one per cent cess for secondary and higher education. In order to take care of the needs of education and health of BPL and rural families, I have announced programs in Part A of my speech. To fund this, I propose to increase the cess by one per cent.

The existing three per cent education cess will be replaced by a four per cent “Health and Education Cess” to be levied on the tax payable. This will enable us to collect an estimated additional amount of ₹11,000 crores.

E-assessment.

157. We had introduced e-assessment in 2016 on a pilot basis and in 2017, extended it to 102 cities with the objective of reducing the interface between the department and the taxpayers. With the experience gained so far, we are now ready to roll out the E-assessment across the country, which will transform the age-old assessment procedure of the income tax department and the manner in which they interact with taxpayers and other stakeholders. Accordingly, I propose to amend the Income-tax Act to notify a new scheme for assessment where the assessment will be done in electronic mode which will almost eliminate person to person contact leading to greater efficiency and transparency.

158. My other tax proposals on direct tax are listed in Annexure 5 of my speech.

Indirect Tax.

159. On the Indirect Taxes side, this is the first budget after the roll out of the Goods and Service Tax. Excise duties to a large extent and service tax have been subsumed in GST, along with corresponding duties on imports. Hence, my budget proposals are mainly on the customs side.

160. In this budget, I am making a calibrated departure from the underlying policy in the last two decades, wherein the trend largely was to reduce the customs duty. There is substantial potential for domestic value addition in certain sectors, like food processing, electronics, auto components, footwear and furniture. To further incentivise the domestic value addition and Make in India in some such sectors, I propose to increase customs duty on certain items. I propose to increase customs duty on mobile phones from 15% to 20%, on some of their parts and accessories to 15% and on certain parts of TVs to 15%. This measure will promote creation of more jobs in the country. Details of changes made in rates of customs duty as well as certain changes made in the excise duty structure are given in Annexure 6 to my speech.

161. To help the cashew processing industry, I propose to reduce customs duty on raw cashew from 5% to 2.5%.

162. I propose to abolish the Education Cess and Secondary and Higher Education Cess on imported goods, and in its place impose a Social Welfare Surcharge, at the rate of 10% of the aggregate duties of Customs, on imported goods, to provide for social welfare schemes of the Government. Goods which were hitherto exempt from Education Cesses on imported goods will, however, be exempt from this Surcharge. In addition, certain specified goods, mentioned in the Annexure 6 to my speech will attract the proposed Surcharge at the rate of 3% of the aggregate duties of customs only.

163. I also propose to make certain changes to the Customs Act, 1962, to further improve ease of doing business in cross border trade, and to align certain provisions with the commitments under the Trade Facilitation Agreement. To smoothen dispute resolution processes and to reduce litigation, certain amendments are being made, to provide for pre-notice consultation, definite timelines for adjudication and deemed closure of cases if those timelines are not adhered to.

164. With the roll out of GST, I propose to change the name of Central Board of Excise and Customs [CBEC] to Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC). The necessary changes in law for this are proposed in the Finance Bill.

165. Madam, while making the proposals in this year’s Budget, we have been guided by our mission to especially strengthen agriculture, rural development, health, education, employment, MSME and infrastructure sectors of Indian economy. I am sure the New India which we aspire to create now will emerge. Swami Vivekanand had also envisioned decades ago in his Memoirs of European Travel, *“You merge yourselves in the void and disappear, and let new India arise in your place. Let her arise – out of the peasants’ cottage, grasping the plough; out of the huts of the fisherman. Let her spring from the grocer’s shop, from beside the oven of the fritter-seller. Let her emanate from the factory, from marts, and from markets. Let her emerge from groves and forests, from hills and mountains”*.

166. With these words, Madam Speaker, I commend the Budget to the House.

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy. (Budget)

Annexure I
(as referred in para 45)

**Budgetary & Non-Budgetary Resources on Agriculture & other Livelihood
Programmes in Rural Area**

(₹crore)

Name of Scheme	Infrastructure/ Livelihood / Both	2018-19 targets			
		Physical Target	Financial Target		
			GBS	EBR	Total
M/o Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation					
PMKSY-AIBP	Infrastructure	48 AIBP priority Projects by December 2019		15000	15000
PMKSY-HKKP (CADWM)	Infrastructure	Utilisation of irrigation potential of 15 lakh Hectare	2300		2300
Other Schemes of MoWR, RD&GR	Both		1461		1461
Sub-total MoWR,RD&GR			3761	15000	18761
Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare					
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna	Livelihood	98 million ha Gross Crop Area	13000		13000
Interest Subsidy for short term credit to Farmers	Livelihood		15000		15000
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana	Infrastructure	Irrigation projects covering 17.2 lakh ha	4000		4000
	Livelihood	15 lakh beneficiaries			
National Food Security Mission	Livelihood	1.81 lakh beneficiaries	1500		1500
Sub Mission on Agricultural Mechanization	Infrastructure	62466 centres for Agriculture Machinery and equipment, Farm Machinery Banks, Hi-Tech Productive Equipment	1100		1100
	Livelihood	17.81 lakh beneficiaries			
Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)	Infrastructure	10,45,878 Cold Storage, Godowns, Glass Houses, Custom Hiring Centers, Soil/Seed Testing Labs, etc.	3100		3100
	Livelihood	116.99 lakh beneficiaries			
Mission for Integrated Development of Horticulture	Infrastructure	3,30,436 centres	1599		1599
Other Schemes of D/o AC&FW	Both		2912		2912
Sub-total of D/o AC&FW			42211		42211
Ministry of Food Processing					
Scheme for Mega Food Parks	Infrastructure	12 Mega Food Parks	390	1170	1560
	Livelihood	Direct & indirect employment to 95000 persons in 2017-18 & 2018-19			
Scheme for Cold Chain and Value Addition Infrastructure	Infrastructure	101 projects	220	880	1100
	Livelihood	Direct: 12000 & indirect: 63000 employment in 2017-18 & 2018-19			

Other Schemes of M/o Food Processing	Both		210	640	850
Sub-total of M/o Food Processing			820	2690	3510
Department of Agriculture, Research and Education					
DARE	Livelihood	Production of 21960 tons Seeds, 255 lakh nos. planting material, 132.5 lakh nos. Animal resources	7800		7800
		1.60 lakh Frontline demonstration			
		450 Farm level trainings			
		20 lakh Human Resources development			
		Infrastructure/ Basic amenities development in 98 SAUs, 681 existing KVKs & 59 new KVKs			
Sub-total of DARE			7800		7800
Ministry of Drinking Water & Sanitation					
Swachh Bharat Mission (Gramin)	Infrastructure	(a) 1.88 crore Household toilets (b) Employment: 16.92 crore Persondays	15343	15000	30343
	Livelihood				
National Rural Drinking Water Programme (NRDWP)	Infrastructure	Infrastructure creation through Piped Water Supply Schemes and Community Water Purification Plants -84000 habitats	7000		
	Livelihood	Livelihood generation - 84000			
Sub-total of M/o DWS			22343	15000	37343
Ministry of Rural Development/ Department of Rural Development					
Pradhan Mantri Awaas Yojana - Gramin (PMAY-G)	Both	49 lakh houses, 46.55 crore Mandays	21000	12000	33000
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY)	Both	57,000 km roads & 28.35 crore Mandays	19000		19000
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme (MGNREGA)	Infrastructure	8552 AWC, 2.60 lakh Kms. of Rural Roads, 1.83 lakh Vermi/NADEP Compost, 675 Food Storage Godowns, 8340 GP Bhawan/Bharat Nirman Seva Kendra	55000		55000
	Livelihood	I. Cattle Shed/ Poultry Shelter/ Piggery shed -99648 II. Land Development -1.65 lakh			
		230 cr Persondays			
National Livelihood Mission-Aajeevika -NRLM	Livelihood under NRLM including MKSP, SVEP, Skill Development	9 lakh nos. of new SHGs to be formed	5750		5750
		Number of Mahila Kisan to be supported- 5 lakh			
		Value Chain Development Project-15			

		Number of SVEP enterprises-25000			
		Number of Trainees to be Skilled - 4 lakh			
Sub-total of D/o Rural Development			100750	12000	112750
Ministry of Rural Development/ Department of Land Resources					
1. Watershed Development Component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (WDC-PMKSY)	Infrastructure	1.30 lakh nos.Water Harvesting Structures to be created/rejuvenated	2146		2146
		1.81 lakhs ha area to be brought under protective irrigation			
	Livelihood	3. No. of farmers benefitted - 5.01 lakh			
Other Schemes of D/o Land Resources			250		250
Sub-total of D/o Land Development			2396		2396
Ministry of Power					
Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY)	Infrastructure	(i) Intensive electrification of villages - 1 lakh nos. (ii) Feeder segregation including new 11 KV Lines - 1 lakh Circuit Km (iii) Commissioning of Substations (New & Augmentation) - 600 nos.	3800	15000	18800
Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (Saubhagya)		Electricity connections to Households - 175 lakh nos.	2750		2750
Sub-total of M/o Power			6550	15000	21550
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises					
Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)	Livelihood	49000 projects 294000 Employment	1260		1260
Other Schemes of MSME	Both		1648		1648
Sub-total of MSME			2908		2908
Ministry of Panchayati Raj					
Fourteenth Finance Commission (FFC) Grant to Gram Panchayats for the period 2015-2020	Both	Works at Gram Panchayat level in focus areas of Health & Sanitation, Drinking Water, Rural Electrification, Maintenance of Community Assets, etc	45069		45069
Other Schemes of M/o Panchayati Raj	Both		348		348
Sub-total of M/o Pachayati Raj			45417		45417
Ministry of Skill Development & Entrepreneurship					
PMKVY 2.0	Livelihood	18 lakh beneficiaries	1171		1171
Sub-total of M/o Skill Development			1171		1171
Department of Financial Services					
Agriculture Credit	Livelihood			1100000	1100000

Micro Irrigation Fund				2000	2000
Rural Infrastrucure Development Fund (RIDF)	Infrastructure			28000	28000
NABARD Infrastructure Development Assistance (NIDA)				3500	3500
Dairy Infra Development Fund (DIDF)				2000	2000
Fisheries & Aquaculture Infra Development (FIDF)				1000	1000
Agri-market Infrastructure				2000	2000
Sub-total D/o Financial Services				1138500	1138500
Total			236127	1198190	1434317
Note: The above allocations are specific for infrastructure and livelihood development in agri and Rural sector					

Annexure II
(As referred in Para 70)

**Schematic outlays under Education, Health and
Social Protection Sectors
(Schematic Outlays)**

Ministry/Department/Scheme Name	2017-18	2018-19
Health & Family Welfare	47,353	52,800
CSS+CS in Health	34,657	39,199
<i>of which</i>		
PMSSY	3,975	3,825
National AIDS and STD Control programme	2,000	2,100
National Rural Health Mission	21,189	24,280
National Urban Health Mission	752	875
Human Resoruces for Health & Medical Education	4,025	4,225
Tertiary care programme	725	750
RSBY	1,000	2,000
AYUSH	1,429	1,626
CSS+CS	509	576
<i>of which</i>		
NAM	441	504
Health Research	1,500	1,800
School Education	46,356	50,000
CSS+CS	38,981	42,391
<i>of which</i>		
SSA	23,500	26,129
RMSA	3,830	4,022
Mid day meal	10,000	10,500

Higher Education	33,330	35,010
CS+CSS	5,526	8,512
<i>of which</i>		
Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)	1,300	1,400
Interest subsidy and contribution for guarantee fund	1,950	2,150
HEFA	250	2,750
e-Shodh Sindu	240	180
Technical Education- Quality Improvement Programme	260	275
Scholarship for College and University Students	320	340
Programme for Apprenticeship Training -Scholarships & Stipentes	110	125
World Class Institutions	50	250
Setting up of virtual class room	75	90
Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Teaching	120	120
ABs	26,896	25,339
<i>of which</i>		
Indian Institutes of Technology	7,856	6,326
IIM	1,030	1,036
Rural Development		
National Social Assistance Program	9,500	9,975
Social Justice	6,908	7,750
CS+CSS	6,836	7,670
<i>of which</i>		
Prematric Scholarship (SC)	50	125
Post-matric scholarship (SC)	3,348	3,000
Special Central Assistance to SC sub schemes	800	1,000
Post-matric scholarship for OBC	885	1,100
Pre-matric scholarship for OBC	142	232
National fellowship for SCs	230	300
Empowerment of Persons with Disability	855	1,070
CS+CSS	559	744
<i>of which</i>		
Assistance to Disabled Persons for purchase/ fitting of Aids and appliances	150	220
Schemes for Implementation of Persons with Disability Act	207	300
Department of Women and Child Development	22,095	24,700
CSS	21,844	24,454
<i>of which</i>		
Anganwadi Services	15,245	16,335
Schemes for Adolescent girls	460	500
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana	2,700	2,400

Nirbhaya Fund Schemes	500	500
Child Protection Scheme	648	725
National Nutrition Mission	1,500	3,000
Mission for protection and empowerment of women (Umbrella)	1,089	1,366
Minority Affairs	4,195	4,700
CS+CSS	3,969	4,460
<i>of which</i>		
Education Empowerment	2,054	2,453
Skill Development & Livelihood	635	602
MSDP	1,200	1,320
TOTAL of Schemes (CS+CSS)	1,22,381	1,37,981
Demand/Ministry-wise Total featured above, except for MoRD	1,64,020	1,79,457

				Annexure III	
				(As referred in Para 114)	
Capital Outlay on Infrastructure Sector					
				₹ crore	
		RE 2017-18		BE 2018-19	
Ministry/Deptt.	Scheme/CPSEs	GBS	IEBR	GBS	IEBR
1. Ministry of Coal (10)	i) Coal India Limited	0	8500	0	9500
	ii) NLC India Limited	0	4578	0	4299
	iii) Singareni Collieries Co. Ltd.	0	1400	0	2000
Total		0	14478	0	15799
2. Ministry of Development of North Eastern Region (23)	i)Central Pool of Resources for North East and Sikkim	175	0	310	0
	ii) Construction/ Improvement of Roads of Economic Importance	5	0	40	0
	iii) North East Road Sector Develop. Scheme- Programme Component	150	0	250	0
Total		330	0	600	0
3. Ministry of New and Renewable Energy (67)	i) Indian Renewable Energy Development Agency	0	9287	0	10099
	ii) Solar Energy Corporation of India	50	179	0	217
Total		50	9466	0	10317
4. Ministry of Petroleum and Natural Gas (72)	i) Payment to Indian Strategic Petroleum Reserve Ltd. (ISPRL) for Crude Oil Reserve	1121	0	701	0
	ii) Phulpur Dhamra Haldia Pipeline Project	400	0	1674	0
	iii) National Seismic Programme	10	0	1300	0
	iv) Bharat Petroleum Corporation Ltd.	0	7800	0	7400

	v) Chennai Petroleum Corp. Ltd.	0	865	0	1010
	vi) Engineers India Ltd.	0	0	0	1356
	vii) Gas Authority of India Ltd.	0	3309	0	4722
	viii) Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	0	7110	0	8425
	ix) Indian Oil Corp. Ltd.	0	18849	0	22862
	x) Mangalore Refineries and Petrochemicals Ltd.	0	1138	0	744
	xi) Numaligarh Refinery Ltd.	0	375	0	428
	xii) Oil and Natural Gas Corp. Ltd.	0	37218	0	32077
	xiii) Oil India Ltd.	0	4263	0	4300
	xiv) Oil Natural Gas Corp. Videsh Ltd.	0	6393	0	5886
Total		1531	87319	3675	89210
5. Ministry of Power (74)	i) 220 KV Transmission line from Srinagar to Leh via Kargil	500	0	500	0
	ii) Damodar Valley Corp. Ltd.	0	1057	0	1606
	iii) National Hydro Electric Power Corp. Ltd.	350	3173	482	2258
	iv) National Thermal Power Corp. Ltd.	0	28000	0	22300
	v) North Eastern Electric Power Corp. Ltd.	1	1212	267	122
	vi) Power Finance Corp. Ltd.	0	4000	0	0
	vii) Power Grid Corp. of India Ltd.	0	25000	0	25000
	viii) Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd.	0	609	0	935
	ix) Tehri Hydro Development Corp. Ltd.	32	1267	52	1248
Total		883	64318	1301	53469
Ministry of Civil Aviation (9)	Airport Authority of India	150	2543	0	4086
Total		150	2543	0	4086
Department of Telecommunication (14)	Defence Spectrum - Optical Fibre Cable based network for Defence Services	3755	0	4500	0
	Investment in CPE (Bharat Broadband Network Ltd.)	0	9786	0	16986
Total		3755	9786	4500	16986
Ministry of Defence (Misc) (19)	Works executed by Border Roads Development Board	2708	0	2785	0
	Coast Guard Organisation	2200		2700	
Total		4908	0	5485	0
Ministry of Railways (80)	Capital Outlay on Indian Railways	40000	34900	53060	38500
	Indian Railway Finance Corporation		45100		54940
Total		40000	80000	53060	93440
Department of Atomic Energy (4)	Nuclear Power Corporation of India Ltd.	1435	7785	1665	5656
Total		1435	7785	1665	5656
Ministry of Housing and Urban Affairs (56)	MRTS and Metro Projects	17810	1477	14924	1897

	Housing and Urban Development Corporation	0	13716	0	13040
	PMAY (Urban)	6043	0	6500	25000
Total		23853	15193	21424	39937
Ministry of Road Transport and Highways (81)	Investment in NHAI	23892	59279	29663	62000
	Roads and Bridges	26967	0	29762	0
Total		50858	59279	59425	62000
Ministry of Shipping (87)	Sagarmala	125	0	250	0
	VoChidambaranar Port Trust		163		342
	Jawaharlal Nehru Port Trust		1569		2065
	Mumbai Port Trust		410		432
	Deen Dayal Port Trust Kandla		347		458
	Kamarajar Port Trust		325		250
	Cochin Shipyard Limited		351		495
Total		125	3165	250	4042
Ministry of Steel (93)	Ferro Scrap Nigam Limited	0	28	0	23
	KIOCL	0	2024	0	1782
	Manganese Ore India Limited	0	272	0	279
	MECON Limited	0	5	0	5
	MSTC Limited	0	33	0	49
	NMDC Limited	0	3324	0	3778
	Rashtriya Ispat Nigam Limited	0	1570	0	1400
	Steel Authority of India Limited	0	4200	0	4000
Total		0	11428	0	11294
Department of Higher Education (58)	HEFA	250	0	2750	28000
Total		250	0	2750	28000
Ministry of Electronics & Information Technology	Digital India	1426		3073	5700
Total		1426		3073	5700
Grand Total		129554	364759	157208	439935
		494313		597143	

Annexure IV

(As referred in para 131)

E-office and E-governance initiatives in central Ministries and Departments

1. A web-based Government Integrated Financial Management Information System (GIFMIS), administered by Controller General of Accounts, for budgeting, accounting, expenditure and cash management for more effective fiscal management of Government.
2. A Non Tax Receipt Portal (NTRP) to provide one stop services for depositing fees, fines and other non-tax dues into Government account;
3. Project 'e-Vidhan' to digitize and make the functioning of all State Legislatures paperless.
4. A Central Public Procurement Portal to provide a single point access for all information on procurement. Around 3.5 lakh contractors and vendors are registered on this platform. In November, 2017 alone, electronic bids for over one lakh tenders valued at around two lakh forty thousand crore were invited through this Portal.
5. The Government E-Marketplace (GeM) to facilitate procurement at the right price, in right quality and quantity in a transparent and efficient manner. Third version of the GeM platform (GeM 3.0) will be launched on 26th January, 2018. The platform has seventy eight thousand buyers, fifty six thousand sellers, three lakh seventy five thousand products and twelve services. Besides facilitating transaction of the value of ₹3000 crore in about two lakh transactions, it could achieve savings of more than 25% over the base price.
6. E-Courts, to bring about universal computerization of all Districts and Subordinate Courts, use of cloud computing and availability of e-services like e-filing and e-payments as well.
7. A National Judicial Data Grid to provide an online platform for information relating to judicial proceedings and decisions from over sixteen thousand computerized Courts and Subordinate Courts in the country. An e-Courts Services App has also been launched to provide litigant centric services.
8. e-Panchayats platform to provide a suite of core common applications to address various aspects of panchayats functioning from internal core functions of planning, budgeting, implementation, accounting, monitoring and social audit to delivery of services like issue of certificates, licenses etc.

Annexure V to Part B of Budget Speech**Other changes in Direct Taxes:**

1. It is proposed that the provision of section 79 of the Income-tax Act (the Act) regarding restriction on shareholding for the purpose of carry forward loss shall not apply in case of change of shareholding pursuant to an approved resolution plan under IBC, 2016 where an opportunity of being heard has been given to the Principal Commissioner or Commissioner.
2. In respect of companies where an application under Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016 has been admitted, it is proposed to provide that for the purpose of computation of Minimum Alternative Tax (MAT) the aggregate amount of unabsorbed depreciation and brought forward loss shall be allowed to be reduced from the book profit.
3. It is proposed to provide that the insolvency resolution professional shall verify the return of income in case of a company where an application under IBC, 2016 has been admitted.
4. It is proposed to provide that provisions of MAT shall not apply in respect of foreign companies having income solely from businesses referred to in sections 44B, 44BB, 44BBA and 44BBB of the Act provided such income has been offered to tax at the rates specified in these sections.
5. It is proposed to extend the benefit of exemption for withdrawal up to 40% from National Pension System Trust (NPS) to all subscribers and not only to employees.
6. It is proposed to provide that in a case where premium for health insurance for multiple years has been paid in one year, the deduction shall be allowed proportionately over the years for which the benefit of health insurance is available.

7. In order to encourage start-ups, the definition of 'eligible business' for a start-up is proposed to be aligned with the modified definition notified by DIPP. It is further proposed to extend the incorporation date for a start-up for availing benefit under section 80-IAC of the Act to 31st March, 2021 from 31st March, 2019 and rationalise the condition of turnover for availing the benefit.
8. It is proposed to rationalise the provisions of section 56(2)(x) of the Act to provide that the receipt of any property by a wholly-owned Indian subsidiary from its holding company and by an Indian holding company from its subsidiary shall be exempt from tax.
9. It is proposed to provide that trading in agricultural commodity derivatives on a recognized stock exchange shall not be treated as a speculative transaction even if no Commodities Transaction Tax (CTT) has been paid in respect of those derivative transactions.
10. Considering the strategic nature of the transactions, it is proposed to provide that income arising to a non-resident from royalty or fees for technical services received from National Technical Research Organisation shall be exempt from tax.
11. It is proposed to provide that the exemption of sale of leftover stock of crude oil shall also apply in respect of termination of the contract or arrangement in respect of a foreign company participating in a strategic oil reserve.
12. It is proposed to provide that in addition to notifying any authority, Board, Trust or Commission under section 10(46) of the Act, the Government can also notify any class of such persons.
13. It is proposed to provide similar tax regime as available to equity oriented funds to Fund of Funds investing only in exchange traded funds which only invest in listed equity shares of domestic companies.
14. It is proposed to provide that no adjustments shall be made under section 143(1)(vi) of the Act while processing the return filed for the assessment year 2018-2019 and subsequent assessment years.
15. It is proposed to provide that no expenditure or allowance or set off of any loss shall be allowed in respect of undisclosed income determined by the Assessing Officer under section 115BBE of the Act.
16. It is proposed to provide that every entity, not being an individual, which enters into any financial transaction of an amount aggregating to Rs. 2.50 Lakh or more in a financial year shall be required to apply for a permanent account number (PAN). It is also proposed that directors, partners, principal officers, office bearer or any person competent to act on behalf of such entities shall also apply for PAN.
17. In view of the proposed amendment in the Customs Act creating a new custom Authority for Advance Ruling, it is proposed to provide that the Authority for Advance Ruling constituted under the Income-tax Act shall act as an Appellate Authority in respect of the rulings given by the customs Authority for Advance Ruling. It is also proposed to provide that when the authority is dealing with an application relating to Income-tax Act, the revenue member shall be from income-tax.
18. It is proposed to make the order passed by the Commissioner of Income-tax (Appeals) under section 271J of the Act appealable before Appellate Tribunal.
19. It is proposed to enhance the penalty from ₹100/- to ₹500/- and from ₹500/- to ₹1000/- under section 271FA of the Act.
20. It is proposed to provide that prosecution shall lie against companies for non-filing of return irrespective of the fact that whether any tax is payable or not.
21. It is proposed to mandate that in order to avail benefit of any deduction under Chapter VIA-C, the persons have to file return within due date specified under section 139(1) of the Act.
22. It is proposed to provide that if stock-in-trade is converted into capital asset, the fair market value of the same on the date of conversion shall be taken into account for computing business income.
23. It is proposed to rationalise the existing provision relating to investment in capital gain bonds by providing that the exemption shall be available only in respect of long-term capital gains arising out of sale of immoveable property and investment in the bond shall be for a minimum period of 5 year from the existing 3 years.

24. It is proposed to amend section 9 of the Act to align the scope of "business connection" with the modified dependent agent permanent establishment rule as per Multilateral Instrument signed by the Government.
25. It is proposed to amend section 9 of the Act to provide that significant economic presence of a non-resident shall constitute "business connection" with India. It is also proposed to define the phrase 'significant economic presence'.
26. It is proposed to provide that compensation received in connection with termination or modification of business contract and employment contract shall be taxable.
27. It is proposed to provide that in respect of heavy goods vehicles (more than 12 tonnes), the presumptive income under section 44AE of the Act shall be computed at the rate of ₹1000 per tonne per month.
28. In order to provide statutory backing and certainty to Income Computation and Disclosure Standards (ICDS), it is proposed to amend the provisions of Chapter IV-D of the Act relating to computation of business income and Chapter XIV of the Act.
29. It is proposed to provide that TDS at the applicable rate shall be made in respect of interest exceeding ₹10,000 from newly introduced 7.75% GOI Savings (Taxable) Bonds, 2018.
30. It is proposed to provide that in the case of an amalgamated company, accumulated profits for the purpose of determining dividend shall also include the accumulated profits of the amalgamating company on the date of amalgamation.
31. It is proposed to provide that deemed dividend under section 2(22)(e) of the Act shall be subject to dividend distribution tax at the rate of 30% without grossing up.
32. It is proposed to provide that the concessional tax rate of 25% for new domestic companies engaged in manufacturing shall be subject to the special rates in respect of specified income provided under Chapter XII of the Act.
33. It is proposed to rationalise the provisions relating to filing of Country-by-Country Report by providing the time-limits and the definition of 'agreement'.
34. It is proposed to amend Finance Act, 2013 to rationalise levy of Commodities Transaction Tax (CTT) on options in commodity futures.
35. It is proposed to amend the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015 to rationalise the designations of authorities competent to grant approval for penalty and prosecution.

Annexure VI to Part B of Budget Speech

INDIRECT TAXES

1. PROPOSALS INVOLVING CHANGE IN CUSTOMS DUTY RATES:

		Chapter/ heading/ sub-heading/ Tariff item	Commodity	Rate of Duty	
				From	To
I.	Incentivizing domestic value addition, 'Make in India'				
	A.	Reduction in Customs duty on inputs and raw materials to reduce costs			
			Food processing		
	1	0801 31 00	Cashew nuts in shell [Raw cashew]	5%	2.5%
			Capital goods and Electronics		
	2	8483 40 00, 8466 93 90, 8537 10 00	Ball screws, linear motion guides, CNC systems for manufacture of all types of CNC machine tools falling under headings 8456 to 8463	7.5%	2.5%
	3	70	Solar tempered glass or solar tempered [anti-reflective coated] glass for manufacture of solar cells /panels/modules	5%	Nil

B. Changes in Customs duty to address the problem of duty inversions in certain sectors					
			Medical Devices		
4	Any Chapter		Raw materials, parts or accessories for the manufacture of Cochlear Implants	2.5%	Nil
C. Changes in Customs duty to provide adequate protection to domestic industry					
			Food Processing		
5	2009 11 00 2009 12 00 2009 19 00		Orange fruit juice	30%	35%
6	2009 21 00 to 2009 90 00		Other fruit juices and vegetable juices	30%	50%
7	2009 81 00, 2009 90 00		Cranberry juice	10%	50%
8	2106 90		Miscellaneous Food preparations (other than soya protein)	30%	50%
			Perfumes and toiletry preparations		
9	3303		Perfumes and toilet waters	10%	20%
10	3304		Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or suntan preparations; manicure or pedicure preparations	10%	20%
11	3305		Preparations for use on the hair	10%	20%
12	3306		Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages	10%	20%
13	3307		Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included, prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties	10%	20%
			Automobile and automobile parts		
14	8407, 8408, 8409, 8483 10 91, 8483 10 92, 8511, 8708, 8714 10		Specified parts/accessories of motor vehicles, motor cars, motor cycles	7.5%/10%	15%
15	8702, 8703, 8704, 8711		CKD imports of motor vehicle, motor cars, motor cycles	10%	15%
16	8702, 8704		CBU imports of motor vehicles	20%	25%
17	4011 20 10		Truck and Bus radial tyres	10%	15%
			Textiles		
18	5007		Silk Fabrics	10%	20%
			Footwear		
19	6401, 6402, 6403, 6404, 6405		Footwear	10%	20%
20	6406		Parts of footwear	10%	15%
			Diamonds, precious stones and jewellery		
21	71		Cut and polished colored gemstones	2.5%	5%
22	71		Diamonds including lab grown diamonds-semi processed, half-cut or broken; non-industrial diamonds including lab-grown diamonds (other	2.5%	5%

			than rough diamonds), including cut and polished diamonds		
	23	7117	Imitation Jewellery	15%	20%
			Electronics / Hardware		
	24	8517 12	Cellular mobile phones	15%	20%
	25	3919 90 90, 3920 99 99, 3926 90 91, 3926 90 99, 4016 99 90, 7318 15 00, 7326 90 99, 8504, 8506, 8507, 8517 70 90, 8518, 8538 90 00, 8544 19, 8544 42, 8544 49	Specified parts and accessories of cellular mobile phones	7.5%/ 10%	15%
	26	8504 90 90/ 3926 90 99	PCBA of charger/adaptor and moulded plastics of charger/adaptor of cellular mobile phones	Nil	10%
	27	Any Chapter	Inputs or parts for manufacture of: a) PCBA, or b) moulded plastics of charger/adaptor of cellular mobile phones	Applicable rate	Nil
	28	8517 62 90	Smart watches/wearable devices	10%	20%
	29	8529 10 99 8529 90 90	LCD/LED/OLED panels and other parts of LCD/LED/OLED TVs	7.5%/ 10%	15%
	30	8529/4016	12 specified parts for manufacture of LCD/LED TV panels	Nil	10%
	31	70	Preform of silica for use in the manufacture of telecommunication grade optical fibres or optical fibre cables	Nil	5%
			Furniture		
	32	9401	Seats and parts of seats [except aircraft seats and parts thereof]	10%	20%
	33	9403	Other furniture and parts	10%	20%
	34	9404	Mattresses supports; articles of bedding and similar furnishing	10%	20%
	35	9405	Lamps and lighting fitting, illuminated signs, illuminated name plates and the like [except solar lanterns or solar lamps]	10%	20%
			Watches and Clocks		
	36	9101, 9102	Wrist watches, pocket watches and other watches, including stop watches	10%	20%
	37	9103	Clocks with watch movements	10%	20%
	38	9105	Other clocks, including alarm clocks	10%	20%
			Toys and Games		
	39	9503	Tricycles, scooters, pedal cars and similar wheeled toys; dolls' carriages; dolls; other toys; puzzles of all kinds	10%	20%
	40	9504	Video game consoles and machines, articles for funfair, table or parlor games and automatic bowling alley equipment	10%	20%
	41	9505	Festive, carnival or other entertainment articles	10%	20%

	42	9506 [except 9506 91]	Articles and equipment for sports or outdoor games, swimming pools and paddling pools [other than articles and equipment for general physical exercise, gymnastics or athletics]	10%	20%
	43	9507	Fishing rods, fishing-hooks and other line fishing tackle; fish landing nets, butter fly nets and similar nets; decoy birds and similar hunting or shooting requisites	10%	20%
	44	9508	Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements; travelling circuses, traveling menageries and travelling theatres	10%	20%
			Miscellaneous items		
	45	3406	Candles, tapers and the like	10%	25%
	46	4823 90 90	Kites	10%	20%
	47	9004 10	Sunglasses	10%	20%
	48	9611	Date, sealing or numbering stamps, and the like	10%	20%
	49	9613	Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical, and parts thereof other than flints and wicks	10%	20%
	50	9616	Scent sprays and similar toilet sprays, and mounts and heads therefor; powder-puffs and pads for the application of cosmetic or toilet preparations	10%	20%
II	Rationalization measures				
			Edible oils of vegetable origin		
	1	1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1515	Crude edible vegetable oils like Ground nut oil, Olive oil, Cotton seed oil, Safflower seed oil, Saffola oil, Coconut oil, Palm Kernel/Babassu oil, Linseed oil, Maize corn oil, Castor oil, Sesame oil, other fixed vegetable fats and oils.	12.5%	30%
	2	1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1515, 1516 20, 1517 10 21, 1517 90 10, 1518 00 11, 1518 00 21, 1518 00 31	Refined edible vegetable oils, like Ground nut oil, Olive oil, Cotton seed oil, Safflower seed oil, Saffola oil, Coconut oil, Palm Kernel/Babassu oil, Linseed oil, Maize corn oil, Castor oil, Sesame oil, other fixed vegetable fats and oils, edible margarine of vegetable origin, Sal fat; specified goods of heading 1518	20%	35%
			Refractory Items		
	3	6815 91 00	Other articles of stone containing magnesite, dolomite or chromite	10%	7.5%
	4	6901	Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals or of similar siliceous earths	10%	7.5%
	5	6902	Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than those of siliceous fossil meals or similar siliceous earths	5%	7.5%

	6	6903	Other refractory ceramic goods	5%	7.5%
III		Social Welfare Surcharge			
	1	Any chapter	Levy of Social Welfare Surcharge on imported goods [other than those mentioned at S. No. 3 to 6 below] to finance education, housing and social security	--	10% of the aggregate duties of customs
	2	Any chapter	Abolition of Education Cess and Secondary and Higher Education Cess on imported goods	3% of the aggregate duties of Customs [2% + 1%]	Nil
	3	2710	Exemption from Social Welfare Surcharge on motor spirit commonly known as petrol and high speed diesel oil	--	3% of the aggregate duties of Customs
	4	7106	Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured form, or in powder form	--	3% of the aggregate duties of Customs
	5	7108	Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-manufactured form, or in powder form	--	3% of the aggregate duties of Customs
	6	Any Chapter	Specified goods hitherto exempt from Education Cess and Secondary and Higher Education Cess on imported goods	--	Nil
IV		Road and Infrastructure Cess			
	1	2710	Levy of Road and Infrastructure Cess on imported motor spirit commonly known as petrol and high speed diesel oil	--	Rs. 8 per litre
	2	2710	Exemption from additional duty of customs leviable under section 3(1) of the Customs Tariff Act, 1975 in lieu of the proposed Road and Infrastructure cess on domestically produced motor spirit commonly known as petrol and high speed diesel oil	--	Nil
	3	2710	Abolition of Additional Duty of Customs [Road Cess] on imported motor spirit commonly known as petrol and high speed diesel oil	Rs. 6 per litre	Nil
	4		Additional duty of customs under sections 3(1) of the Customs Tariff Act, 1975 in lieu of basic excise duty		
		2710	(i) Motor spirit commonly known as petrol	Rs. 6.48 per litre	Rs. 4.48 per litre
		2710	(ii) High speed diesel oil	Rs. 8.33 per litre	Rs. 6.33 per litre

2. AMENDMENTS TO THE CUSTOMS TARIFF ACT, 1975 WITH NO CHANGES IN EFFECTIVE RATES OF DUTIES

S. No.	Amendment
A	Amendment in the Customs Tariff Act, 1975
1	Amendment to the section 3 so as to insert subsections 8A and 10A to provide for valuation of warehoused goods, which are sold to another person before clearance for home consumption or export, for the purposes of Integrated Tax and Goods and Services Tax Compensation Cess.

B	Import duty – First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975
1	The tariff rate of customs duty for the specified medical devices is being increased from 7.5% to 10%. The effective rate of import duty on such medical devices will, however, remain unchanged.
2	The tariff rate of customs duty for Lithium-ion batteries is being increased from 10% to 20%. The effective rate of import duty on Lithium-ion batteries [other than Lithium-ion batteries for cellular mobile phones] will, however, remain unchanged at 10%.
C	Export duty – Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975
1	To insert a new Note to specify Nil rate of duty in respect of all other goods which are not covered under column (2) of the Schedule.
2	Introduction of 20% Tariff rate of Export Duty on Electrodes of a kind used for furnaces. The effective rate of Export duty on such electrodes will, however, remain Nil.

3. MAJOR AMENDMENTS IN THE CUSTOMS ACT, 1962

S. No	Amendment
A.	For facilitating trade
1	Defining scope of Assessment and introducing “risk based selection” for verifying Self-Assessment [Section 2(2), 17 of Customs Act]
2	Establishing single point of reference for importers, exporters and Officers with regard to Regulatory Controls imposed by various Ministries, Departments and Agencies [Section 11 of Customs Act]
3	Facilitating imports and exports meant for Repair, Manufacture and further Processing with full or partial duty exemptions [Section 25A and Section 25B of Customs Act]
4	Appointing a new Customs Advance Ruling Authority with Appellate mechanism [Sections 28E to 28M of Customs Act]
5	Providing legal basis for clearance by Customs Automated System [Sections 45, 47, 51, 60, 68 and 69 of Customs Act]
6	Introducing an electronic Cash ledger on the lines similar to provisions in CGST Act [Section 51A of Customs Act]
7	Introducing a new chapter for conduct of Audit [Section 99A of Customs Act]
8	Inserting a new section to provide for simplified and different procedures as part of Trade Facilitation [Section 143AA of Customs Act]
9	Introducing a new section for exchange of information with competent authorities of other countries [Section 151B of Customs Act]
B.	For reducing litigation
10	Providing for pre-notice consultation, issue of supplementary show cause notices on receipt of additional information but within present limitation period, time bound Adjudication and deemed closure of cases [Section 28 of Customs Act]
11	Providing for closure of cases without imposition of redemption fine in cases of voluntary payment of all dues [Section 125 of Customs Act]
C.	For improving compliance
12	Expanding the scope of the Customs Act to any offence or contravention committed under the said Act outside India [Section 1 of Customs Act]
13	Introducing provisions for controlled delivery for certain goods to be notified [Section 109A of Customs Act]

4. PROPOSALS INVOLVING CHANGE IN EXCISE DUTY RATES:

		Commodity	Rate of Duty	
			From	To
I	Motor spirit commonly known as petrol and high speed diesel oil			
	1.	Levy of Road and Infrastructure Cess on motor spirit commonly known as petrol and high speed diesel oil	--	Rs. 8 per litre
	2.	Abolition of Additional Duty of Excise [Road Cess] on motor spirit commonly known as petrol and high speed diesel oil	Rs. 6 per litre	Nil
	3.	Basic excise duty on:		
		(i) Unbranded Petrol	Rs. 6.48 per litre	Rs. 4.48 per litre
		(ii) Branded petrol	Rs. 7.66 per litre	Rs. 5.66 per litre
		(iii) Unbranded diesel	Rs. 8.33 per litre	Rs. 6.33 per litre
		(iv) Branded diesel	Rs. 10.69 per litre	Rs. 8.69 per litre
	4.	Infrastructure Cess on (i) 5% ethanol blended petrol, (ii) 10% ethanol blended petrol and (iii) bio-diesel, up to 20% by volume, subject to the condition that appropriate excise duties have been paid on petrol or diesel and appropriate GST has been paid on ethanol or bio-diesel used for making such blends	--	Nil
	5.	Infrastructure Cess on petrol and diesel manufactured in and cleared from 4 specified refineries located in the North-East	--	Rs. 4 per litre

Note : "Basic Excise Duty" means the excise duty set forth in the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985.

5. MISCELLANEOUS

S. No.	Amendment
A.	Renaming of Central Board of Excise and Customs as the Central Board of Indirect Taxes and Customs
	Name of Central Board of Excise and Customs is being changed to Central Board of Indirect Taxes and Customs with consequential amendments in the following Acts:— i. The Central Boards of Revenue Act, 1963 (54 of 1963) ii. The Customs Act, 1962 (52 of 1962) iii. The Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)